3 | राजधानी
ठेके पर काम करने वालों को सात तक देना होगा वेतन

8 | अभिमत
कटुतापूर्ण होगा 2019 का चुनाव प्रचार

13 | विदेश
इमरान ने भारत पर शांति प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया

14 | स्पोर्ट्स
पुजारा बल्लेबाजी में शीर्ष तीन में शामिल

RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 7 अंक 65
नई दिल्ली, बुधवार, 9 जनवरी, 2019
पृष्ठ 16 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

सिनेमा को लोकतांत्रिक होना चाहिए
विविध-16

बंधे हाथ के साथ सीबीआई निदेशक पद पर वर्मा बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जबरन छुट्टी पर भेजने का केंद्र सरकार और सीवीसी का आदेश

- वर्मा के भी पर कतरे, प्रवर समिति के निर्णय तक नहीं ले सकेंगे कोई बड़ा नीतिगत फैसला
- पीएम की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति को हफ्ते भर में बैठक बुलाने को कहा
- समिति तय करेगी वर्मा सीबीआई चीफ रहेंगे या नहीं, 31 को खत्म हो रहा उनका कार्यकाल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार को झटका देते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने का उसका आदेश खारिज कर दिया। मंगलवार को सीबीआई चीफ पद पर वर्मा की बहाली का निर्णय सुनाती ऊपरी अदालत ने उन्हें ऑफिस जाने की अनुमति तो दे दी लेकिन यह कहकर उनके हाथ भी बांध दिए कि उनकी शक्तियां छीनने के मुद्दे पर उच्चाधिकार प्राप्त प्रवर समिति का फैसला आने तक वे कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे।

बहाली के बावजूद वर्मा के सिर पर शक्तियों एवं अधिकारों से वंचित किए जाने की तलवार अब भी लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है लिहाजा सीबीआई प्रमुख को चुनने वाली उच्चाधिकार प्राप्त प्रवर समिति अब भी वर्मा से जुड़े मामले पर विचार कर सकती है। अदालत ने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोस में नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता वाली प्रवर समिति को एक हफ्ते के भीतर बैठक बुलाने को कहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति यह तय करेगी कि वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाया जाए या नहीं। लोस में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश समिति के सदस्य हैं। यह कहते हुए कि कानून में अंतरिम निलंबन या सीबीआई निदेशक को हटाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी फैसला प्रवर समिति की सहमति से ही लिया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने 44 पेज के फैसले में वर्मा को उनकी शक्तियों से वंचित करने और संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने संबंधी सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 23 अक्टूबर, 2018 के आदेशों को निरस्त कर दिया।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत यह निर्देश देना उचित समझती है कि सीबीआई निदेशक वर्मा अपने (शेष पेज 7)

सरकार की सफाई, सीवीसी के कहने पर छुट्टी पर भेजा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सफाई देते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अनुशंसा पर सरकार ने सीबीआई के दो बड़े अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का निर्णय लिया था। यह फैसला पूरी तरह वैध था क्योंकि दोनों आपस में भिड़े हुए थे। सरकार शीर्ष अदालत के आदेशों का अनुपालन करेगी।

संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बात करते जेटली ने वर्मा एवं सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने के निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि यह फैसला सीबीआई की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्णत: प्रामाणिक एवं सीवीसी की अनुशंसा के मुताबिक की गई थी क्योंकि दोनों अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। सरकार ने महसूस किया कि सीबीआई की (शेष पेज 7)

राफेल से जोड़ते राहुल ने कहा पीएम को बर्बाद कर देगा सच

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सीबीआई निदेशक पद पर आलोक वर्मा की बहाली के उच्चतम न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर पीएम मोदी पर फिर वार किया। उन्होंने दावा किया कि राफेल मामले का सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्बाद कर देगा। राफेल मामले की जांच से उन्हें कोई नहीं बचा सकता और एक दिन पूरे देश को पता चलेगा कि मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये अपने मित्र अनिल अंबानी को दे दिए।राहुल ने ट्वीट किया कि कानून को बहाल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को बधाई।

इससे पहले, संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। अदालत फैसले से उन लोगों को कुछ राहत मिली है। सीबीआई प्रमुख बहाल हो गए हैं। (शेष पेज 7)

गरीबों को आरक्षण संबंधी विधेयक लोकसभा में मंजूर

- समर्थन में 323 और विरोध में सिर्फ 3 मत पड़े, आज राज्य सभा में पेश होगा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गई। अब कल इसके राज्यसभा में जाने की संभावना है जहां उच्च सदन की बैठक एक दिन और बढ़ा दी गई है। लोकसभा में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक का समर्थन किया। साथ ही सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है। लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार बनने के बाद ही गरीबों की सरकार होने की बात कही थी और इसे अपने हर कदम से उन्होंने साबित भी किया। उनके जवाब के बाद सदन ने 3 के मुकाबले 323 मतों से विधेयक को पारित कर दिया। अन्नाद्रमुक के एम थंबिदुरै, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध किया।

चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि बहुत सारे सदस्यों ने आशंका जताई है कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा है तो यह कैसे होगा? जो पहले के फैसले किए गए वो संवैधानिक प्रावधान के बिना हुए थे। उन्होंने कहा कि नरसिंह राव की सरकार को संवैधानिक प्रावधान के बिना 10 फीसदी आरक्षण का आदेश जारी किया था, जो नहीं करना चाहिए था। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति और नीयत अच्छी है। इसलिए संविधान में प्रावधान करने के बाद हम आरक्षण देने का काम करेंगे। ऐसे में इस तरह की (उच्चतम न्यायालय में निरस्त होने की) शंका निराधार है। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। (शेष पेज 7)

एचआरडी मंत्रालय कर रहा 10 फीसदी कोटा पर काम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- देश भर में शैक्षिक संस्थानों में बढ़ानी होगी दस लाख सीटें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को एक बैठक बुलाकर उच्च शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की रूपरेखा पर काम करने के संबंध में विचार-विमर्श किया। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय यह देख रहा है कि शैक्षिक संस्थानों में कितनी सीटें तय की जाए जिससे कि इस कोटे पर अमल किया जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दी है। भाजपा के समर्थन का आधार मानी जाने वाली अगड़ी जातियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गरीब तबकों को आरक्षण दिया जाए।

सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय इस पर काम कर रहा है कि इस आरक्षण को लागू करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में कितनी सीटों को बढ़ाने की जरूरत है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम जैसे अन्य प्रतिष्ठित उच्च शैक्षिक संस्थानों समेत देशभर में संस्थानों में करीब 10 लाख सीटें बढ़ानी होगी।

सूत्रों ने कहा, अभी यह रूपरेखा तैयार नहीं की गई है कि आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान चाहे वे सरकारी हो या निजी उन्हें आरक्षण लागू करना होगा। (शेष पेज 7)

मौसम

अधिकतम 19.7°C (0)
न्यूनतम 7.0°C (0)

बाजार

सेंसेक्स	35,980	▲ 130	
निफ्टी	10,802	▲ 30	
सोना	32,690	▲ 40	/10g
चांदी	39,800	▼ 200	/kg

क्विक न्यूज

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा के जाहिदपोरा इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी में एक अज्ञात आतंकी मारा गया और घटनास्थल से कुछ हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।

अयोध्या मामले में संविधान पीठ गठित, सुनवाई 10 से

- पांच सदस्यीय संविधान पीठ की प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे अध्यक्षता

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक संबंधी विवाद की सुनवाई के लिए मंगलवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित की। यह पीठ दस जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई नोटिस में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि अयोध्या भूमि विवाद में याचिकाएं 10 जनवरी, 2019 को सुबह साढ़े दस बजे प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होंगी। कोर्ट ने चार जनवरी को कहा था कि इस मामले में गठित होने वाली उचित पीठ 10 जनवरी तक अगले आदेश देगी। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित 2.77 एकड़ भूमि के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर, 2010 के 2:1 के बहुमत के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं। उच्च न्यायालय ने इस फैसले में विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था।

देशभर में भारत बंद का रहा आंशिक असर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन मंगलवार को पश्चिम बंगाल में छिटपुट घटनाएं हुईं, जबकि मुंबई में सार्वजनिक परिवहन की बसें सड़कों से दूर रहीं। दूसरी तरफ बैंकों का कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। यूनियनों ने सरकार पर श्रमिकों विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य जनजीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि, वामदल शासित केरल में यह आंदोलन पूरी तरह हड़ताल में तब्दील हो गया। वहां स्कूल, कॉलेज बंद रहे और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं। मुंबई में सार्वजनिक परिवहन सेवा बेस्ट के 32,000 से अधिक कर्मचारी मंगलवार को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनकी यह हड़ताल ट्रेड यूनियनों की (शेष पेज 7)

फिलहाल ऑनलाइन नहीं मंगा सकेंगे दवाएं

- दिल्ली हाईकोर्ट का रोक हटाने से इनकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आनलाइन फार्मेसी से सीधी मंगाई जाने वाली दवा अथवा डाक्टर के पर्चे के आधार पर दवाओं की बिक्री पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी तक यह रोक बनी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा, सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि इसके लिए सांविधिक नियम अभी बनाए जाने हैं, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। अदालत जहीर अहमद द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में दवाओं की गैरकानूनी आनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है। सुनवाई के दौरान एक आनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है। दवाओं की आनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैरकानूनी तरीके से नहीं करती हैं।

नागरिकता विधेयक पर लोस की मुहर, रास में राह होगी कठिन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के प्रावधान वाले विधेयक पर लोकसभा ने मुहर लगा दी। अब इसे राज्यसभा में पारित कराना होगा जहां सत्ता पक्ष के लिए राह आसान नहीं होगी। असम के कुछ वर्गों की आशंकाओं और धार्मिक आधार पर नागरिकता दिए जाने के आरोपों को निराधार बताते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि असम की जनता की परंपराओं, संस्कृति को संरक्षित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सिंह ने संसद की संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा के जवाब में यह बात कही। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।

यह विधेयक नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता विधेयक के संबंध में गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और असम के कुछ भागों में आशंकाएं पैदा करने की कोशिश हो रही हैं। सिंह ने कहा, इस विधेयक को लेकर तरह तरह की आशंकाएं, भ्रम पैदा करने की कोशिशें निर्मूल हैं, निराधार हैं। असम के लोगों की परंपराओं, संस्कृति को संरक्षित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी पैदा की जा रही है कि इस विधेयक का बोझ असम सहेगा। ऐसा नहीं है, पूरा देश इसे सहेगा। सरकार और पूरा देश असम की जनता के साथ खड़े हैं।

सिंह ने जोर दिया कि पाकिस्तान में राष्ट्र एवं समुदाय के स्तर पर अल्पसंख्यकों के साथ सुनियोजित तरीके से भेदभाव किया जाता है। उन्हें बुनियादी अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे में इन लोगों के पास भारत में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने असम में राष्ट्रीय नागरिक (शेष पेज 7)

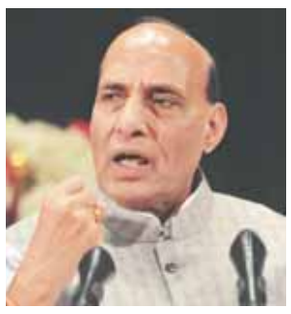

- असम की जनता की परंपराओं, संस्कृति को संरक्षित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं : राजनाथ

दो देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ मोदी लगाएंगे संगम में डुबकी

- नेपाल के प्रधानमंत्री ओली तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ के इस माह के अंत में कुंभ आने की संभावना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेपाल तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों के साथ कुंभ में डुबकी लगाएंगे। पीएम के संगम स्नान को लेकर सरकार में उच्चस्तरीय तैयारी चल रही है। हालांकि पीएम मोदी के संगम स्नान की तिथि का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं हुआ है और इसके लिये दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के कुंभ आने के कार्यक्रम का इंतजार है।

उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक तीनों प्रधानमंत्रियों का कुंभ स्नान जनवरी माह के अंत में होने की संभावना है। पन्द्रह जनवरी को मकर संक्रान्ति के शाही स्नान के साथ प्रयागराज कुंभ शुरू होगा और 21 जनवरी को दूसरा शाही स्नान है। कुंभ में आने वाली भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखकर शाही स्नान और इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद अतिविष्टिजनों को प्रयागराज न आने की सलाह दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान के बाद पीएम मोदी, नेपाल के पीएम खड्क प्रसाद ओली तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ के जनवरी माह के अंत में संगम स्नान के लिये कुंभ में आने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव सूचना अवनीश अवस्थी का कहना है कि कुंभ में अभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने की तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है। पीएमओ से कार्यक्रम के आने का इंतजार किया जा रहा है। सीएम योगी के विशेष कार्याधिकारी मृत्युन्जय कुमार ने बताया कि पीएम मोदी और (शेष पेज 7)

राष्ट्रपति 17 को कुंभ स्नान के लिए पहुंचेंगे प्रयागराज

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

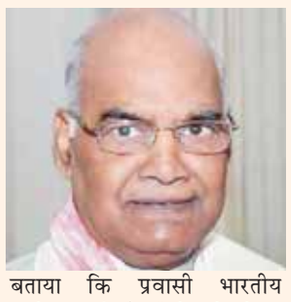

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 जनवरी को कुंभ 2019 में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। कुंभ में उपराष्ट्रपति एम वेंकेया नायडू के भी आने का कार्यक्रम है लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि इससे पहले दस जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ जाएंगे। योगी पर्यटन ग्राम और अक्षयवट में भ्रमण करेंगे।

निर्मल आखाड़ा के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अवस्थी ने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर 16 जनवरी को मुख्यमंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लखनऊ में प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार कुंभ क्षेत्र करीब दो गुना हो गया है। 32 हजार वर्ग मीटर में कुंभ नगरी बसाई गई है। इस बार कुंभ के लिए 4300 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है जबकि पिछले कुंभ में यह बजट 1200 करोड़ रुपए का था। कुंभ क्षेत्र में 250 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले साल करीब 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार इससे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 22 राज्यों में कुंभ को लेकर मंत्रियों ने प्रेस कान्फ्रेंस की और सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ ही हर ग्रामवासी को कुंभ आने का निमंत्रण दिया गया है।

एक्वा मेट्रो का बोड़ाकी तक होगा विस्तार

इस रूट पर दो से तीन स्टेशन बनाए जाएंगे, प्राधिकरण ने तैयार किया प्रस्ताव

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

एक्वा मेट्रो लाइन नोएडा-ग्रेटर नोएडा का विस्तार डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक किया जाएगा। प्राधिकरण ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे आगामी फरवरी या मार्च माह में होने वाली बोर्ड बैठक में पास कराया जाएगा। एक्वा लाइन का

● डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक होगी 3.5 किलोमीटर होगी दूरी

विस्तार होने से दादरी के लोगों को भी फायदा होगा। भविष्य में बोड़ाकी शहर का महत्वपूर्ण प्वाइंट हो जाएगा। यह जानकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने दी।

सीईओ ने बताया कि एक्वा मेट्रो लाइन का डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक विस्तार किए जाने का निर्णय लिया गया है। डिपो स्टेशन से बोड़ाकी की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। इस लाइन का विस्तार होने से बोड़ाकी के आसपास और दादरी के लोगों को भी फायदा मिलेगा। साथ ही दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन से भी यह जुड़ जाएगी।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। सीईओ का कहना है बोड़ाकी तक मेट्रो का विस्तार होने से बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन पर उतरकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से लेकर दिल्ली जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस रूट पर दो से तीन स्टेशन बनाए जाएंगे। डीपीआर तैयार होने पर इसका पता चल जाएगा।

सीईओ नरेंद्र भूषण का कहना है कि बोड़ाकी के पास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब भी बनना है इसलिए भी एक्वा लाइन का विस्तार किया जाना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट हब के लिए इसी साल अप्रैल-मई माह में निविदा जारी होने का अनुमान है। साथ ही साल के अंत तक लॉजिस्टिक हब व ट्रांसपोर्ट हब पर काम शुरू होने की उम्मीद है। बोड़ाकी से ही दिल्ली एयरपोर्ट और जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट तक भी हाई स्पीड ट्रेन व मेट्रो चलाने की योजना है।

फर्जी आईएएस धरा

नोएडा। सूरजपुर पुलिस ने एक फर्जी

आईएएस को गिरफ्तार किया है। इसके पास से फर्जी आईएएस का आईकार्ड और विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुआ है।

थाना प्रभारी मुनीश चौहान ने बताया कि दो दिन पहले अभय बहल नाम के व्यक्ति का फोन आया था जो कि पुलिस पर एक दुकान को खाली कराने का दबाव बना रहा था। इसके बाद कल वह खुद थाने आया और अपने आप को आईएएस बता कर पुलिस पर एक दुकान को खाली कराने की बात कही। आईकार्ड मांगे जाने पर उसने अपना फर्जी आईकार्ड पुलिस को दिखाया। जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। फर्जी आईएएस नोएडा सेक्टर 15ए का रहने वाला है।

कैंटर में घुसी बेकाबू कार, तीन की मौत

यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, एक की हालत गंभीर-भर्ती

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा की रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र स्थित जीरो पॉइंट यमुना एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार आई-10 कार एक कैंटर में जा घुसी। तेज रफ्तार के चलते गाड़ी चला रहे युवक ने अपना आपा खो दिया जिससे यह हादसा हुआ। हादसे में गाड़ी चला रहे युवक समेत दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग व क्षतिग्रस्त कार।

एसपी ग्रामीण विनीत जयसवाल ने बताया कि मंगलवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्राम नगला भटौना के पास एक कार अनियंत्रित होकर कैंटर में घुस गई। इस घटना में कार में बैठे अंकुर गुप्ता 28, कुमारी नेहा गुप्ता 25, विक्रम गुप्ता 21 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुमारी दीक्षा 23 गंभीर रूप से घायल है। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसपी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि सभी आगरा के रहने वाले थे। अंकुर की सगाई नेहा गुप्ता से हुई थी विक्रम और दीक्षा नेहा के भाई-बहन हैं। वे नोएडा से आगरा की तरफ जा रहे थे।

सील बूचड़खाने में अब भी काटे जा रहे हैं पशु

डीएम खुद करें औचक निरीक्षण : पार्षद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

जिले में अवैध तरह से पशु काटे जाने पर थाना प्रभारियों को उत्तरदायी ठहराने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जिले के किस हिस्से में अवैध तरह से बूचडखाने चल रहे हैं यह देखने वाला कोई नहीं है।

सूत्र बताते हैं कि विजय नगर थाना क्षेत्र में जिस बूचड खाने को डीएम के आदेश पर सील किया गया था वहां मौजूदा में भी पशु काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पार्षद हाजी आसिफ ने कहा कि सजवान नगर से कुछ कदम की दूरी पर इस बूचडखाने का कभी भी डीएम जायजा लें तो सच्चाई निश्चित तौर से सामने होगी। उन्होंने कहा कि अवैध बूचड खानों पर कार्रवाई के नाम पर सरकार को गुमराह किया जा रहा है। किन अधिकारियों के संरक्षण में ये बूचडखाना चल रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए।

वैसे तो शासन द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं कि जिला प्रशासन अधिकृत बूचड़खानों का औचक निरीक्षण करें और वहां नजर रखे। जिले के किसी भी हिस्से में अवैध तरीके से बूचड़खाने नहीं चलने चाहिए। थाना प्रभारियों को क्षेत्र में अवैध बूचडखाना चलते हुए पाए जाने पर उत्तरदायी ठहराया जाए।

सूत्र बताते हैं कि एनएच 24 पर सजवान नगर से कुछ कदम की दूरी पर मौजूदा में भी अवैध तरीके से बूचड़खाना संचालित हो रहा है और बाकायदा वहां पशु काटे जा रहे हैं। इस बूचड़खाने को जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ समय पहले ही सील किया गया था।

लिपिक पर धन वसूली का लगाया आरोप

गाजियाबाद। डासना नगर पंचायत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसी कड़ी में डासना नगर पंचायत के पूर्व लिपिक दिनेश कौशिक पर अवैध रूप से टेंडर देने की एवज में डेढ़ लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया है।

गौरतलब है कि डासना नगर पंचायत के पूर्व में रहे लिपिक दिनेश कौशिक पर आरोप दर आरोप लग रहे हैं। पहले उन पर फाइल चोरी करने के आरोप लगे थे। जिसके कारण उनपर पालिका अध्यक्ष द्वारा सस्पेंड की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उन पर लगातार आरोपों की झड़ी डासना नगर पंचायत ही नहीं कस्बे से भी लोग लगाने लगे हैं।

इसी बीच गुलजार पुत्र यामीन निवासी मोहल्ला कुरैशीयान का आरोप है कि उन्होंने मुर्दा मवेशी का ठेका देने की एवज में पूर्व लिपिक रहे दिनेश कौशिक को डेढ़ लाख रुपए की रकम दी थी।

सपना चौधरी के गाने को लेकर चले लात और घूंसे

नशे में धुत 6 युवकों ने किया हंगामा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● शांतिभंग के आरोप में लिए गए हिरासत में

सपना चौधरी के गाने की फरमाइश को लेकर बवाल होने का मामला सामने आया है। नोएडा सेक्टर-38ए स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने सपना चौधरी का गाना नहीं लगाने पर पब में जमकर तोड़फोड़ कर दी। कोतवाली सेक्टर-39 पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शांतिभंग में चालान कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गार्डेन गैलेरिया मॉल में एक पब में रविवार रात आधा दर्जन युवक गए थे। वहां उन लोगों ने शराब पी और डांस करने लगे। ये लोग बार-बार सपना चौधरी का गाना लगाने को कह रहे थे। इसी पर डीजे ने जब गाना बदलने से मना कर दिया तो नाराज युवकों ने हंगामा कर दिया।

आरोप है कि नशे में धुत होकर युवकों ने जमकर मारपीट की और उसके बाद तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खोड़ा निवासी सोनू पंडित, विकास मिश्र, चंद्रशेखर चौहान, गौड़ सिटी निवासी उदय शर्मा, सिंहराज सहित एक अन्य को हिरासत में ले लिया।

बताया जाता है कि इनके हिरासत में लिए जाने के बाद हिंदू संगठनों के कई नेताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर छोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया।

आरोपी नहीं मिला तो पत्नी को पकड़ा

नोएडा। कोतवाली दादरी पुलिस ने धरम सिंह उर्फ धर्मी हत्याकांड के मामले में आरोपियों के नाम मिलने पर उनकी पत्नियों को ही पकड़ लिया है और उन्हें तीन दिनों से पुलिस हिरासत में रखा है।

मंगलवार सुबह जब इस संबंध में गांव समाधिपुर की महिलाओं को पता चला तो उन्होंने थाने का घेराव कर हंगामा किया। हंगामा कर रही महिलाओं का कहना है कि भरत की पत्नी और ब्राह्मी की पत्नी को पुलिस ने तीन दिन से हिरासत में लिया हुआ है। दोनों के ही एक से डेढ़ महीने के बच्चे हैं। ऐसी ठंड में यदि बच्चों को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा।

वहीं, पुलिस का कहना है कि बच्चों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें मां की बजाय गाय का दूध दिया जा रहा है। फिलहाल जब तक इनके पति गिरफ्त में नहीं आते तब तक इनको छोड़ना सही नहीं है।

डॉ. अजयपाल पहुंचे प्रयागराज वैभव कृष्ण के जिम्मे नोएडा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

तेज तर्रार माने जाने वाले एसएसपी डॉ अजयपाल शर्मा का जिले से तबादला कर दिया गया है। उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज बनाया गया है। अब जिले की कमान बागपत में तैनात वैभव कृष्ण को दी गई है।

डॉ अजयपाल शर्मा

वैभव कृष्ण इससे पहले पड़ोसी जिले गाजियाबाद में एसएसपी रह चुके हैं। सोमवार को मुख्यालय लखनऊ से जारी की गई लिस्ट में दूसरे नंबर पर उनका नाम है।

गौतमबुद्धनगर जिले में उनका कार्यकाल 16 मार्च 2018 से 7 जनवरी 2019 तक रहा। जिले में रहने के दौरान एसएसपी डॉ अजय पाल शर्मा ने छोटे-बड़े सैकड़ों एनकाउंटर किए। उनकी छवि एक तेजतर्रार पुलिस वालों में की जाती है। जिले में कमान संभालने के बाद से ही वो काफी सक्रिय हो गए थे। कई इनामी बदमाश उनके कार्यकाल के दौरान जिले से बाहर चले गए थे।

शहर में कई बड़े विवादों को उन्होंने सूझबूझ से सुलझाया था। इनमें एडीएम और रिटायर्ड कर्नल और सेक्टर-58 में पार्क में नमाज अता करने का मामला प्रमुख था। इसके अलावा उन्होंने 5 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के कई इनामी बदमाशों को एनकाउंटर के बाद सलाखों के पीछे पहुंचाया।

संक्षिप्त समाचार

प्ले वे स्कूलों के नियमानुसार संचालन के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी को ज्ञापन सौंपते ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य।

प्ले वे स्कूल के संबंध में डीएम को दिया ज्ञापन

गाजियाबाद। ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन ने जनपद में प्ले वे स्कूलों का संचालन नियमानुसार कराने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन का कहना है कि प्ले वे स्कूल में समय-समय पर दुर्घटनाएं होती रहती है। वर्ष-2018 में एक डॉक्टर की बेटी को स्कूल में पीटा गया था। बीएसए से शिकायत करने पर उनका जबाव था कि यह स्कूल उनके अधीन नहीं आते हैं। प्ले वे स्कूलों की मान्यता के संदर्भ में जनसूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा विभाग से 15 फरवरी 2018 को एक पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिया गया, जिसमें प्लेवे स्कूलों की मान्यता के संदर्भ में कुल 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, मगर दस माह से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी ना तो सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराई है और ना प्ले वे स्कूलों की निगरानी के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मृतक सफाईकर्मियों का रिकॉर्ड मांगा

गाजियाबाद। सीवर लाइन और सैप्टिक टैंक में सफाई के दौरान कर्मचारियों की मौत के मामले में शासन द्वारा गठित कमेटी ने नगर निगम से रिकार्ड तलब किया है। बाकायदा कमेटी के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर निगम अधिकारियों में हडकंप मचा रहा। गौरतलब है कि सीवर और सैप्टिक टैंक की सफाई के लिए सफाईकर्मियों को उनमें उतार तो दिया जाता है, लेकिन उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जाति संबंधी संयुक्त समिति की द्वितीय उपसमिति की टीम मंगलवार की सुबह गाजियाबाद पहुंची। एडीएम वित्त द्वारा नगर निगम को प्रकरण से जुड़ी बीस-बीस बुकलेट के साथ कलेक्ट्रेट में उपलब्ध रहने के आदेश दिए हैं।

मोदी डिस्टलरी की दस करोड़ की शराब जब्त

गाजियाबाद। गन्ना बकाया भुगतान न होने पर प्रशासन ने सोमवार को मोदी शुगर मिल की सहयोगी कंपनी मोदी डिस्टलरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने मोदी डिस्टलरी की 10 करोड़ रुपये की शराब जब्त कर ली। वहीं, इस कार्रवाई के बाद फैक्टरी के कर्मचारियों ने रात को तहसील पर जमकर हंगामा किया। उनको लगा कि इससे वे बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन अधिकारियों के समझाने पर कर्मचारी मान गए। गाजियाबाद में गन्ना किसानों के बकाए को लेकर लापरवाह रवैया अपनाने वाली मोदी शुगर मिल के मालिकों पर एक और कार्रवाई की गई है। मोदी शुगर मिल के मालिक की डिस्टलरी और मोदी रेवलॉन कंपनी के स्टॉक को प्रशासन ने सील कर दिया है। इससे पहले जिला गन्ना अधिकारी ने मोदी शुगर मिल पर एफआईआर भी कराई थी। अब भी किसानों का 174 करोड़ रुपए मोदी शुगर मिल पर बकाया है। इसकी भरपाई अब मोदी शुगर मिल के मालिकों की दूसरी कंपनियों से की जा जाएगी।

तीन शातिर ठग गिरफ्तार 20 एटीएम कार्ड बरामद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

साहिबाबाद थाना क्षेत्र पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 एटीएम भी बरामद किए हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।

पुलिस ने बताया कि उन्हें जीटी रोड स्थित शिव मंदिर के पास कुछ संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने जांच अभियान चलाकर वहां मौजूद तीन शातिरों की तलाशी ली और उनके पास से 20 एटीएम बरामद किए। आरोपियों की पहचान अर्थला निवासी अनिल और राजीव कॉलोनी के सतीश एवं यूनुस के तौर पर की गई।

थानाप्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शातिर अपराधी हैं जो एटीएम बदलकर लोगों के खातों से पैसे निकाल लिया करते थे।

आईएमएस लॉ कॉलेज में सेमिनार का आयोजन

नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईएमएस लॉ कॉलेज में हॉफडे सेमिनार का आयोजन किया गया। मंगलवार को संस्थान परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एसएन श्रीवास्तव, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता बलराज मलिक एवं एरिसेंट टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग हेड लक्षिका जोशी ने शिरकत की।

कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, मौलिक कानून, न्याय एवं संविधान के साथ कानूनी शिक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

कार्रवाई में एसटीएफ के दो सिपाही भी घायल, अस्पताल में भर्ती

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

लोनी इलाके में सोमवार देर रात पुलिस और एसटीएफ की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि जवाबी कार्रवाई में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

घायल बदमाश सौरव

मिली जानकारी के अनुसार घायल बदमाश की पुलिस को पिछले काफी समय से तलाश थी। उस पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और थाना बीबीनगर ने बदमाश पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार बरामद किया है।

एसपी देहात अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि सोमवार रात करीब 9.30 बजे लोनी कोतवाली क्षेत्र की बंथला नहर पर सिखरानी गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में यूपी एसटीफ की नोएडा यूनिट और लोनी थाना पुलिस संयुक्त रूप से शामिल रहीं। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान सौरव पुत्र देवेंद्र थाना बीबी नगर जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई है।

सौरभ कुख्यात योगेश भदौड़ा गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है तथा उस पर हत्या, हत्या के प्रयास और गैंगरेप जैसे कई जघन्य अपराध दर्ज हैं।

इंदिरापुरम में जनवरी बाद शुरू होंगे सिविल कार्य

गाजियाबाद। इंदिरापुरम में सभी सिविल कार्य अब जनवरी माह बाद ही शुरू किए जाएंगे। कुछ दिन पहले नगर निगम के इंदिरापुरम को टेकओवर करने से मना करने के बाद यह फैसला जीडीए ने किया है।

एग्जिक्यूटिव इंजीनियर आरपी सिंह ने बताया कि सीवर, स्ट्रीट लाइट, सड़कों और नालियों का जिस भी जगह पर निर्माण होना है या प्रस्ताव है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। उस आधार पर पूरा लेआउट बनाया जाएगा जिनमें सभी प्रोजेक्ट की लागत तय की जाएगी।

कैंटर-बाइक की टक्कर में एक की मौत, दूसरा घायल

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

मुरादनगर के डिंडोली गांव में एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी। घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि सोमवार देर शाम मोहित (20) एवं बाबू (24) बाइक से मुरादनगर गंग नहर की पटरी पर बने कावड़ यात्रा मार्ग से घर की ओर जा रहे थे। जब वह दोनों डिंडोली गांव के पास पहुंचे तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाबू की मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल मोहित को गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

थानाप्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कैंटर चालक की तलाश शुरु कर दी गई है।

मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई

हापुड़। प्रेस क्लब धौलाना द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि जिला सूचनाधिकारी राकेश कुमार चौहान ने प्रेस क्लब के गठन के बाद हुए विस्तार में क्लब के नव मनोनीत पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।

राजशगुन फार्म हाउस में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि व जिला सूचना अधिकारी ने कहा समाचार पत्र की नाक, कान और आंख कहे जाने वाला संवाददाता ही होता है जो खबरों को खोजकर उसे गढ़ने का कार्य करता है।

मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने पहुंचे किसान। फोटो : दीपक यादव

टावरों को ठंडा करने को एसटीपी के पानी का होगा इस्तेमाल

एनटीपीसी दादरी तक 36 किलोमीटर पाइप लाइन डालने में 550 करोड़ रुपए आएगा खर्च

रिंकू यादव। नोएडा

एनटीपीसी दादरी में लगे टावरों को ठंडा करने के लिए एसपीटी के पानी का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए 36 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन डाली जाएगी। यह लाइन सेक्टर.54 एसटीपी प्लांट से एनटीपीसी तक होगी। इसके लिए सर्वे व डीपीआर तैयार की जा रही है जिसमें 550 करोड़ रुपए खर्च

● प्राधिकरण को सालाना करीब 30 करोड़ रुपए होगी आमदनी

किए जाएंगे। यह पैसा एनटीपीसी की ओर से खर्च किया जाएगा।

लाइन डलने के बाद सेक्टर-54 एसटीपी प्लांट से करीब 80 एमएलडी शोधित पानी एनटीपीसी को मुहैया कराया जाएगा। इससे प्राधिकरण को सालाना करीब 30 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जून-2018 में इसके लिए एनटीपीसी व नोएडा

प्राधिकरण के बीच साझा समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

बताते चलें कि पूरे उत्तर भारत में नोएडा पहला ऐसा शहर है, जहां के एसटीपी के शोधित पानी से थर्मल पावर प्लांट की दो यूनिटों को चलाया जा सकेगा। समझौते के तहत एनटीपीसी के संयंत्र में लगे टावरों को ठंडा करने के लिए नोएडा प्राधिकरण उन्हें 80 एमएलडी सीवेज ट्रीटेड पानी उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना को उप्र सरकार के उपक्रम उप्र जल निगम द्वारा पूर्ण कराया जाएगा।

परियोजना के तहत करीब 36 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन डाली जाएगी। यह लाइन नोएडा से एसटीपी प्लांट से एनटीपीसी थर्मल प्लांट तक होगी। उप्र जल निगम को रूट के अनुसार सर्वे कर तीन माह में इसकी डीपीआर तैयार करनी थी। ऐसे में यह तय कर लिया गया है कि शोधित पानी की लाइन सेक्टर-54 एसटीपी से दादरी तक जाएगी।

2016 में बनी थी नीति

30 जून 2016 को एनटीपीसी ने प्राधिकरण को इस आधार पर पत्र लिखा कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 28 जनवरी 2016 को जारी टैरिफ नीति के क्लाज के तहत थर्म पावर प्लांट को उनके 50 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत स्थित एसटीपी से शोधित जल प्राप्त कर प्लांट में प्रयोग किया जाए। ऐसे में एनटीपीसी ने नोएडा के एसटीपी से निकलने वाले पानी की जांच करवाई। जांच में सकारात्मक रिपोर्ट मिली। जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण व एनटीपीसी के बीच साझा समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

मूल आबादी तोड़ने के विरोध में प्राधिकरण का किया घेराव

राजनीतिक दलों के नेता व पदाधिकारी पहुंचे

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

मंगलवार को बख्तावरपुर गांव में तोड़ी गई मूल आबादी के विरोध में नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया गया। घेराव में सैकड़ों संख्या में महिलायें, विभिन्न दलों के नेता, विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी व 81 गांवों के किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ हुंकार भरी।

नोएडा प्राधिकरण पर घेराव करने के लिए किसान नेता गौतम अवाना खुद ट्रेक्टर चलाकर पहुंचे। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम नागर व कांग्रेस नेता ललित अवाना सैकड़ों किसानों के साथ प्राधिकरण का घेराव करने को पहुंचे। पंचायत की अध्यक्षता जगगी पहलवान व मंच संचालन विपिन तंवर ने किया।

किसानों ने प्राधिकरण के गेट का ताला तोड़ कर मुख्य द्वार के सामने बैठकर धरना शुरू कर दिया। किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्राधिकरण पिछले 43 वर्षों से यहां के किसानों का खून चूसने का काम कर रहा है। आज जिन किसानों की मूल आबादी को तोड़ा गया है वो प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों की पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ का ही नतीजा है जिसे हम किसान कतई बरदास्त नहीं करेंगे।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

ठेके पर काम करने वालों को सात तक देना होगा वेतन

दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर विभाग प्रमुखों को दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

ठेका कर्मियों को अब हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिल जाएगा। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले इसके लिए दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। इससे सरकार में प्रत्यक्ष रूप से अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों के साथ उन कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलेगी जो किसी ठेकेदार के जरिये दिल्ली सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभाग प्रमुखों को सख्त आदेश दिया है कि अलग-अलग विभागों में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को 7 तारीख को वेतन दिया जाए।

आदेश का उल्लंघन करने पर मिलेगा कारण बताओ नोटिस

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूर दी जा चुकी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार विभाग प्रमुख सचिव की ये जिम्मेदारी है कि ठेके पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल जाए। कैबिनेट में ये भी फैसला लिया गया था कि संबंधित विभाग प्रमुख हर महीने की 20 तारीख तक मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट भेजेंगे कि उनके विभाग में ठेके पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है। मुख्य सचिव यही रिपोर्ट हर महीने की 22 तारीख तक मुख्यमंत्री को सौपेंगे।

दिल्ली सरकार की तरफ से सभी विभाग प्रमुखों को सख्त सर्कुलर जारी किया गया है कि वे अनुबंध पर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के कैबिनेट के फैसले का पालन करें। कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुखों को सौंपी गयी है। ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी ठेकेदार के पास 1000 से कम कर्मचारी हैं तो वह हर महीने की 7 तारीख तक सभी कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन दे देगा। अगर उसके पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो भी उसे हर महीने की 10 तारीख तक अपने कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन देना होगा।

पत्रकार को बेल, ईडी मामले में रहेंगे कैद

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के आरोप में पिछले साल मई में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार पत्रकार उपेंद्र राय को जमानत दे दी है। हालांकि, वह जेल में बने रहेंगे क्योंकि इसी से संबंधित ईडी के एक मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने राय की जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्होंने कहा कि वह आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और मुकदमे में कुछ वक्त लगने की संभावना है। न्यायाधीश ने कहा, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना और तथ्यों और परिस्थितियों को समग्रता में देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे में कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि नियमित जमानत के लिए याचिकाकर्ता ने अपना मामला बनाया है।

राय को सीबीआई ने तीन मई को संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में शामिल होने और गलत सूचना देकर हवाई अड्डा पहुंच पास हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

हथौड़े से ताबड़तोड़ वारकर प्रेमिका को किया घायल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार

प्रेमिका के नजरअंदाज करने से प्रेमी उसके जान का दुश्मन बन गया। लंबे समय तक रिलेशन में रहने के बाद प्रेमिका के बदले रुख से नाराज प्रेमी ने उसे महिपालपुर स्थित एक होटल में बुलाकर हथौड़े से ताबड़तोड़ पांच वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद का चयन टीवी सीरियल में होने के झांसा देकर प्रेमिका को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था।

डीसीपी देवेंद्र आर्य ने बताया कि पुलिस को सोमवार रात को मामले की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान निशांत सैनी (24) के रूप में की गई है, जो अपने परिवार के साथ सरोजिनी नगर इलाके में रहता है। पुलिस जांच में सामने आया कि निशांत ने युवती को झूठ बोलकर महिपालपुर स्थित एक होटल में बुलाया था। उसने युवती से कहा था कि उसको एक टीवी सीरियल में काम मिल गया है। जिस कारण वह मुंबई जा रहा है। वह युवती से सिर्फ आखिरी बार मिलना चाहता है। इस पर युवती रविवार को मिलने के लिए होटल चली गई।

इस दौरान युवती अपना आधार कार्ड होटल में भूल गई। उसने निशांत को इस बारे में बताया तो उसने सोमवार को होटल में आकर आधार कार्ड लेकर जाने की बात कही। सोमवार को जब युवती होटल पहुंची तो आरोपी ने हथौड़े से युवती के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिया। इस दौरान कमरे का दरवाजा खुला था। युवती की चीख सुनकर होटल का कर्मचारी कमरे में पहुंचा गया। निशांत ने बताया कि युवती के सिर पर कुछ गिर गया, जिस कारण वहां जमीन पर गिर गई और उसके सिर में चोट लगी है।

संक्षिप्त समाचार

त्रिलोकपुरी में पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी लोगों की समस्याएं सुनते हुए।

सांसद ने चौपाल में किया समस्याओं का निराकरण

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने त्रिलोकपुरी में गिरी चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान संबंधित अधिकारियों को करने के निर्देश दिए। इस मौके पर निगम, डीडीए, पुलिस, बीएसईएस, डीटीसी के अधिकारी मौजूद थे। महेश गिरी के अनुसार इलाके के लोगों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित तथा स्वच्छ वातावरण मुहैया कराना ही इस चौपाल का मकसद है। साथ ही जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का प्रत्यक्ष निराकरण करना भी है। चौपाल में आये सभी लोगों ने अपनी समस्याओं को सांसद के सम्मुख रखा।

मंगलवार को हिंदी अकादमी ने श्रीराम सेंटर में नृत्यनाटिका का आयोजन किया।

राधा नृत्यनाटिका ने दर्शकों का मनमोहा

नई दिल्ली। हिंदी अकादमी ने श्रीराम सेंटर में नृत्यनाटिका आयोजन किया। इसमें राधा नामक नृत्यनाटिका ने दर्शकों का मनमोह लिया। आप सरकार के समाज कल्याण मन्त्री राजेन्द्र पाल गौतम ने इस नाट्य समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नाटकों के माध्यम से आम लोगों में प्रेम, भाईचारा, साहचर्य समरसता के सन्देशों को आसानी से पहुंचाते हैं क्योंकि नाटक साहित्य की रूचिकर विद्या है। अकादमी के सचिव डॉ जीतराम भट्ट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में राधा का चरित्र समर्पण प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा के लिए जाना जाता है। इसीलिए अनेक साहित्यकारों ने राधा पर केन्द्रित कथाए कविताएं कहानीयां, उपन्यास की रचना की।

विधेयक पारित होने पर मिश्रित प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। राज्य सभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक पर इंटिग्रेटिड मेडिकल एसोसिएशन ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभी तक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का नियमन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1970 के अंतर्गत होता है। उक्त विधेयक पारित होने के बाद 1970 के अधिनियम का स्थान लेगा। 1970 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने राज्यों में पंजीकृत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग का अधिकार दे सकती हैं। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित विधेयक में इस प्रावधान को नहीं रखा गया था। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ युवराज कुमार त्यागी और महासचिव डॉ आरपी पाराशर ने एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग से संबंधित अधिकार को प्रस्तुत विधेयक में सम्मिलित करने के निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉ त्यागी और पाराशर ने आयोग के अन्तर्गत आयुर्वेद के लिए अलग बोर्ड के गठन के लिए भी सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन आयोग के गठन में कथित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ताक पर रखने के फैसले पर सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की।

सौर पैनल निपटारा नीति न होने से एनजीटी चिंतित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एंटीमनी लेपित सौर पैनलों के निपटारे के संबंध में नीति या नियमों के अभाव पर चिंता जताई है और इसके लिए कम से कम कितने समय की आवश्यकता होगी सरकार से यह बताने को कहा है।

न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अन्य पक्षों की ओर से उपस्थित वकील से मुद्दे पर निर्देश लेने और इस तरह का नियम बनाने के लिए कितना समय चाहिए इस बारे में उसे जानकारी देने को कहा। पीठ ने कहा, यह तथ्य निर्विवाद है कि एंटीमनी लेपित सौर पैनलों के निपटारे के लिए न तो कोई नीति है और न ही कोई नियम है।

पीठ ने कहा, हम संबंधित वकीलों को निर्देश देते हैं कि वे इस मुद्दे पर निर्देश लें।

कार की टक्कर से हवलदार की मौत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मृतक गुलजारी लाल

द्वारका सेक्टर-23 में मंगलवार देर रात पुलिस पिकेट के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से एक 53 वर्षीय हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मंगलवार दोपहर 33 वर्षीय आरोपी को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान गुलजारी लाल के रूप में की गई है। वे द्वारा में सेक्टर-23 पुलिस थाने में तैनात थे।

द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त एंटो अल्फोंस के मुताबिक हादसा मंगलवार रात के एक बजे हुआ जब हेड कांस्टेबल गुलजारी लाल हेड कांस्टेबल एचसी प्रकाश के साथ सेक्टर-23 इलाके में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। डीसीपी ने बताया कि उन्होंने एक बलेनो कार को अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने कार को रोकने का इशारा किया लेकिन ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार

पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा

पिकेट के बैरिकेड को टक्कर मारते हुए निकल गया। टक्कर से बैरिकेड गुलजारी लाल के गले में लगा। उन्हें तुरंत वेकेंटेश्वर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

डीसीपी ने बताया कि इस संबंध में द्वारका सेक्टर-23 पुलिस थाने में धारा १८६/३५३/२७९/३०४/४२७ के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों को द्वारका और आसपास की कार मरम्मत की दुकानों, बीमा एजेंटों तथा सर्विस स्टेशनों पर भेजा गया, जिससे हादसे में शामिल गाड़ी के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। इसके अलावा व्हाट्सएप और उस क्षेत्र के आरडब्ल्यूए को भी इस संबंध में मैसेज भेजा गया।

डीसीपी ने बताया कि पोछनपुर गांव में एक कार रिपेयर मेकेनिक ने सूचना दी कि उसकी दुकान के पास एक क्षतिग्रस्त बलेनो कार खड़ी है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार की पहचान की। इसके बाद पोछनपुर में गोपी अपार्टमेंट निवासी आरोपी नागेश कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह गुरुग्राम में अपने दोस्तों से मिलकर रात एक बजे लौट रहा था, जब पिकेट पर तैनात पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रोका तो वह डर और बच निकलने की कोशिश में उसने पुलिस बैरिकेड तथा पुलिस कर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद उसने क्षतिग्रस्त कार को अपने घर के पास सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर दिया।

अब, निजी एफएम चैनलों पर सुनिए समाचार

नई दिल्ली। जल्द ही आप निजी एफएम चैनलों पर नए-पुराने गानों के साथ खबरें भी सुन सकेंगे। अब निजी चैनलों को भी अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के समाचारों के प्रसारण की अनुमति दी जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को यह सुविधा शुरू की।

निजी एफएम चैनल बिना कांट-छांट के आकाशवाणी के समाचारों का प्रसारण कर पाएंगे और इस साल 31 मई तक परीक्षण के आधार पर यह सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षण काल में नियम और शर्तों के अनुसार, निजी एफएम प्रसारकों से अशांत या सीमा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रसारण से बचने को कहा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस कदम से नागरिकों का सशक्तिकरण होगा।

हरियाणा में आप हर घर का खटखटाएगी दरवाजा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी अपने प्रचार अभियान को धार देने की कवायद शुरू कर दी है।

दिल्ली की तर्ज पर पार्टी हरियाणा में घर-घर पहुंच कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हर लोकसभा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है।

दिल्ली सरकार के मंत्री व हरियाणा के प्रभारी गोपाल राय के अनुसार मंगलवार को रोहतक,सिरसा और भिवानी के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। इससे पहले 6 जनवरी को गुरुग्राम, हिसार और करनाल के नेताओं को प्रशिक्षित किया गया था। इसकी शुरुआत 5 तरीख को सोनीपत, अम्बाला और फरीदाबाद से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों पाठ पढ़ाया गया। बुधवार को कुरुक्षेत्र लोकसभा के पदाधिकारियों की कक्षा लगेगी। प्रशिक्षण के अगले दिन से ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर-घर प्रचार में जुट जा रहे हैं। जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है वो गांवों में जाकर 10 लोगों की एक टीम बना रहे हैं। साथ ही इन टीमों को मोटिवेट करके वैसी ही ट्रेनिंग दे रहे हैं जैसी उन्हें केजरीवाल ने दी गई है।

इसके बाद ये टीमें समूह में आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर लोगों से संपर्क साधा रहे हैं। प्रशिक्षित लोग चौराहों, नुक्कड़ और चौपालों में भी जा रहे हैं और वहां लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिन्द के अनुसार कार्यकर्ताओं को अगर किसी प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो समाधान के लिए अलग से टीम बनाई गई है।

योजनाएं अधर में, बजट पटरी से उतरा : गुप्ता

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के मात्र 11 सप्ताह शेष बचे हैं। बजट पटरी से उतर गया है और योजनाऐं अधर में लटक गईं हैं।

विभिन्न विभाग निर्धारित बजट का अब तक सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत ही खर्च कर पाए हैं। सरकार की टाईम-लाईन बजट समय सीमा के अंतर्गत प्रमुख विभाग अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न विभाग बजट खर्च करने में भी विफल रहे हैं।

बढ़ते आवारा कुत्तों से पार पाने की तैयारी में निगम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हर महीने 3 हजार बंध्याकरण की योजना

आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम तिमारपुर और बेला रोड पर नवनिर्मित कुत्तों के बंध्याकरण केन्द्रों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दोनों केन्द्रों के चालू होने के बाद कुत्तों के बंध्याकरण की क्षमता हर महीने 15 सौ से बढ़ाकर 3 हजार तक हो जायेगी।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति की अध्यक्ष वीना विरमानी मंगलवार को तिमारपुर तथा बेला रोड पर नवनिर्मित कुत्तों के बंध्याकरण केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पार्षद राजा इकबालय, अतिरिक्त आयुक्त स्वास्थ्य आरएस मीणा, निदेशक पशु सेवा जगवीर मौजूद थे।

डीडीए में भ्रष्टाचार, जरूरी है डिजिटलीकरण : हरदीप पुरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

शहरी कार्य एवं आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में भ्रष्टाचार मौजूद है। इस संस्था की पूरी कार्यप्रणाली का डिजिटलीकरण करके ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पुरी ने कहा कि डीडीए में एक सतर्कता इकाई है जो एक स्वतंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी के तहत काम कर रही है। यह सतर्कता इकाई भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करती है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। भ्रष्टाचार तब तक रहेगा जब तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल नहीं हो जाती।

डीडीए में भ्रष्टाचार समय के साथ कम होता जाएगा और हमने इस संदर्भ में कदम उठाया है। डीडीए को यह नहीं पता है कि उसके पास कितनी जमीन है और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस बारे में पता चल सकता है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने आप नेता अरिवंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा चलने के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि इस मामले में मुकदमा अभी भी लंबित है और निर्वाचित सदस्यों को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। पीठ ने कहा मुकदमा अब भी चल रहा है। वह बरी हो सकते हैं। तब आप क्या करेंगे। आप उनके दोषी ठहराए जाने के बाद आएं। इसमें कुछ दम नहीं है, इसे खारिज किया जाता है।

पीठ वकील हरिनाथ राम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उपराज्यपाल को केजरीवाल तथा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपी अन्य मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

एसडीएमसी ने भी लागू की संपत्ति कर माफी योजना

31 मार्च तक भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने पर सौ फीसदी छूट

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम संपत्ति कर माफी योजना 2018-19 लागू कर दिया है। ददिननि की स्थायी समिति की बैठक में मंगलवार को सभी कॉलोनियों में हर प्रकार के संपत्ति के लिए शत प्रतिशत ब्याज, जुर्माना समेत अन्य शुल्क माफ करने की आम माफी योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

यह प्रस्ताव स्थायी समिति की अध्यक्ष शिखा राय ने पेश किया। नेता सदन कमलजीत सहरावत ने इसका समर्थन किया। इससे बकाया संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह योजना गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों के संपत्ति करदाताओं के लिए लागू होगी।

स्थायी समिति की अध्यक्ष शिखा राय के अनुसार इस आम माफी योजना के अंतर्गत उन संपत्ति करदाताओं की ब्याज, जुर्माने और अन्य शुल्क सौ फीसदी माफ हो जाएगी जो कुल बकाया कर राशि का भुगतान 31 मार्च 2019 तक कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में वे सभी सम्पत्तियां शामिल होंगी जिनके मालिकों ने 1 अप्रैल 2004 या उससे आगे संपत्ति कर जमा नहीं किया या नियमित तौर पर जमा करने में असमर्थ या जिन संपत्तियों के बारे में 2004 और उससे आगे कर निर्धारण नहीं हुआ। उन्हें भी आम माफी योजना का लाभ मिलेगा।

शिखा राय ने बताया कि जिन संपत्तियों का अब तक के बकाया कर का भुगतान कर दिया जाएगा उन पर देय ब्याज, जुर्माने और अन्य शुल्क की शत प्रतिशत राशि माफ की जाएगी।

उपमहापौर ने मढ़ा निगमों को पंगु बनाने का आरोप

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उपमहापौर राजेश कुमार लावड़िया ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बदले की भावना से काम कर रहें है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को नामंजूर करके नगर निगमों को पंगू बनाने की साजिश कर रही है।

समाज निर्माण गृहस्थ की जिम्मेदारी : तारा

हरियाणा प्रांत की प्रचारिका ने कहा-व्यक्ति के केंद्रित होने से संकुचित हो रहे सामाजिक संबंध

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मक्रर संक्रांति के मौके पर राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम।

समाज के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थ की है क्योंकि गृहस्थ ही समाज का निर्माण कर उसमें संस्कारों की स्थापना करता है। यह बात राष्ट्र सेविका समिति की हरियाणा प्रांत प्रचारिका , धार्मिक विभाग तारा देवी ने मेरा परिवार आनंदी परिवार कार्यक्रम में कही।

तारा जी ने कहा कि आज का समाज व्यक्ति केंद्रित हो रहा है सामाजिक संबंध संकुचित हो रहे हैं जबकि पहले संयुक्त परिवार में शिशु अधिक सीखता था। वहां संस्कार देने का कार्य केवल माता-पिता तक सीमित नहीं था।

मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विश्व के सबसे बड़े महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति द्वारा सरस्वती बाल मंदिर, राजौरी गार्डन में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉ मधु वेद (निर्देशिका विद्वत परिषद) ने कहा कि हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने संस्कारों पर अडिग रहें।वहीं मुख्य अतिथि विभा गुप्ता (शिक्षा सलाहकार) ने कहा कि साहित्य में संस्कार की शिक्षा के साथ-साथ जीवन उपयोगी भाषा को भी बच्चे सीखें ताकि आत्मनिर्भर बन सके।

प्रांत कार्यवाहिका सुनीता भाटिया ने मकर संक्रांति उत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एक सेविका श्रेया कुमारी को भी सम्मानित किया गया जिनकी हॉकी टीम अभी हाल में नेशनल जीतकर आई है। कार्यक्रम में राधा मेहता, रेखा दीदी, विजया शर्मा सहित अनेक अधिकारी तथा सेविकाएं उपस्थित रहीं।

सातवां वेतन आयोग लागू न करने पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे यहां के एक निजी स्कूल के शिक्षकों सहित 89 कर्मचारियों की एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति और डीएवी पब्लिक स्कूल, रोहिणी से भी जवाब मांगा है। इस सिलसिले में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों ने याचिका दायर कर सातवें वेतन आयोग के मुताबिक संशोधित भत्ता और अन्य लाभ दिए जाने की मांग की है। उन्होंने इसे एक जनवरी 2016 से प्रभावी करने की मांग की। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है।

देशव्यापी हड़ताल: गुरुग्राम में पैदल मार्च करके दिखाया दम

कमला नेहरू पार्क से निकलकर श्रमिकों का जुलूस शहर के कई क्षेत्रों से गुजरा

शहर में जाम की स्थिति बनी

गुरुग्राम में ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होकर पैदल मार्च करते श्रमिक।

सोहना के मुख्य डाकघर के गेट पर लटका ताला।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मंगलवार को गुरुग्राम में ट्रेड यूनियन से जुड़े श्रमिकों ने पैदल मार्च करके अपनी एकता व शक्ति का प्रदर्शन किया। यहां कमला नेहरू पार्क से निकलकर श्रमिकों का जुलूस शहर के कई क्षेत्रों से गुजरा। इस दौरान में शहर में यातायात जाम की स्थिति बन गई।

सुबह 11 बजे से ही कमला नेहरू पार्क में हजारों की संख्या में मजदूर-कर्मचारियों का इकट्ठा होना शुरू हुए। दोपहर एक बजे तक काफी संख्या में मजदूर कर्मचारियों ने कमला-नेहरू पार्क से सेक्टर-12 तक सरकार विरोधी नारों के साथ पैदल मार्च किया और अपनी एकता का परिचय दिया। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के प्रति बदले जा रहे श्रम कानूनों को लेकर मजदूरों, कर्मचारियों और किसानों में भारी रोष को लेकर यह हड़ताल आज बुधवार को भी जारी रहेगी।

इस विशाल मार्च को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की महासचिव ने कहा कि आप लोग बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी एकजुकता पर मुझे गर्व है। इंटक के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. जी संजीवा रेड्डी ने कहा कि जो सरकार मजदूर और कर्मचारियों पर तानाशाही रवैया अपना रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है बस कुछ दिनों में यही मजदूर-कर्मचारी उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

इस हड़ताल में हरियाणा इंटक अध्यक्ष अमित यादव, अनिल पवार एटक, सतबीर सिंह सीटू, जसपाल राणा हिन्द मजदूर सभा, रामकुमार, कुलदीप जांघू, अशोक यादव होंडा यूनियन, मुकेश शर्मा, सत्यपाल गिल, एसएन दहिया, बीएस यादव, नरेश कुमार हेमा यूनियन, बलवान, राजकुमार आदि कई यूनियन नेताओं ने हिस्सा लिया।

सोहना में हड़ताल का मिलाजुला असर

सोहना। सोहना में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिलाजुला असर रहा। डाकघर व बिजली निगम के कार्यालयों पर ताले जड़ रहे। बैंकों में भी असर कम मिला। रोडवेज की बसें सड़कों पर रोजाना की तरफ से दौड़ीं।

मंगलवार को सोहना में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर बैंकों से लेकर डाकघर, जनस्वास्थ्य विभाग, बिजली निगम, नगरपरिषद, हरियाणा रोडवेज आदि विभागों पर नाममात्र रहा। सोहना में 30 फीसदी बैंक बंद रहे। डाकघर के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। मंगलवार सुबह से ही डाकघर में लगा ताला खुला ही नहीं। कर्मचारी सुबह से ही काम पर नहीं आए। सर्वकर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम के एसडीओ कार्यालय में धरना दिया, लेकिन हड़ताल का असर नाममात्र नजर आया। बिजली की सप्लाई रोजाना की तरफ से चली। जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और नगरपरिषद के कर्मचारियों ने रोजाना की तरफसे काम किया। शहर में बिजली और पानी की सप्लाई सामान्य तरीके से उपभोक्ताओं को मिली।

हरियाणा रोडवेज की बसें मंगलवार को हर दिन की तरह से चली। बस स्टैंड पर यात्रियों का किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। रोडवेज के बस स्टैंड के स्थानीय प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश यादव ने बताया कि सभी डिपो की बसें मंगलवार को आई और अपने सही समय से चलती रहीं।

हरियाणा : केंद्र सरकार के खिलाफ बरसे बिजली बोर्ड कर्मचारी

सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हड़ताली कर्मचारी।

पुन्हाना। मंगलवार को एचएसईबी वर्कर यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बिजली बोर्ड पुन्हाना के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसमें केंद्र-प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अध्यक्षता सिराजुद्दीन प्रधान ने की।

संघ के प्रदेश उपप्रधान तारिक हुसैन ने कर्मचारियों को संबोंधित करते हुये कहा कि हरियाणा सरकार ने मानी हुई मांगों अभी भी लागू नहीं किया है। जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, पुरानी पेंशन नीति बहाल करना आदि मांगों को लेकर कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जिसमें देश की सभी ट्रेड यूनियन, बैंक बीमा कंपनियां और मजदूर संगठन किसान हड़ताल में भाग ले रहे हैं। प्रधान सिराजुद्दीन व राजेश कुमार सचिव ने बताया कि बिजली बोर्ड पुन्हाना का प्रत्येक कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर रहेगा और आगे जैसे भी सेंट्रल काउंसिल के आदेश आते हैं उनका पालन करते हुये कर्मचारी हर संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। प्रदर्शन में तेजपाल उपप्रधान, भीम सिंह उपप्रधान, रामेश्वर दयाल, रामवीर सिंह, उमर मोहम्मद, ताहिर, सफी मोहम्मद, हरिश्चंद्र, शौकत अली, युसूफ खान, कुलदीप, असगर खान, बच्चू सिंह, शौकत अली, प्रेम सिंह, शब्बीर, शेर सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

हड़ताल में रोडवेज का नहीं दिखा असर : दो दिवसीय हड़ताल में मेवात में रोडवेज का कोई असर नहीं दिखाई दिया। प्रतिदिन की भांति बसें पुन्हाना बस स्टैंड से निकलीं और अपने गतंव्य तक पहुंचीं। हड़ताल देखते हुये यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई दी।

गैर जरूरी सुविधाओं के रख-रखाव को बने एक्ट

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मंत्री राव नरबीर सिंह को ज्ञापन सौंपते जीसीसी के बैनर तले आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि।

लाइसेंस प्लॉटिड कॉलोनियों का रख-रखाव कंडोमीनियम सोसायटी की तर्ज पर करने के लिए बिल्डर इलाके की आरडब्ल्यूए संगठनों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर सिंह से मुलाकात कर कंडोमीनियम एक्ट बनाने की मांग की है। गुड़गांव सिटीजंस काउंसिल के बैनर तले रविवार को एक दर्जन से अधिक आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के निवास पर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

गुड़गांव सिटीजंस काउंसिल के प्रधान आरएस राठी के मुताबिक लाइसेंस कॉलोनियों में सुविधाओं के रख-रखाव के स्तर को बेहतर रखने के लिए यह एक्ट बनना बेहद जरूरी है। कॉलोनियों में अब तक जरूरी और गैर जरूरी सुविधाओं का रख-रखाव बिल्डर प्रबंधन ही करता था, लेकिन आठ लाइसेंस कालोनियों की ट्रांस्फर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिसके बाद गैर जरूरी सुविधाओं का रख-रखाव स्थानीय निवासियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। जरूरी सुविधाओं में सीवर, सड़क, ड्रेनेज, बागवानी, स्ट्रीट लाइट और पानी शामिल है जिसके रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी लेकिन गैर जरूरी सुविधाओं में सुरक्षा, खाली प्लॉटों की सफाई, बाउंड्रीवॉल एवं अवैध कब्जे रोकना शामिल है। इस एक्ट के बनने से आरडब्ल्यूए इन सुविधाओं का रख-रखाव आसानी से कर सकती है।

आरडी सिटी के पूर्व प्रधान टीएन कॉल, सुशांत लोक आरडब्ल्यूए के सचिव राजेन्द्र भट्ट, डीएलएफ-4 आरडब्ल्यूए के उप-प्रधान विनोद चोपड़ा, बृजमोहन मेहता, डीएलएफ आरडब्ल्यूए के प्रवक्ता ध्रुव बंसल का कहना है कि कालोनियों में सुरक्षा और अवैध कब्जा एक बड़ा विषय है और दोनों के ही रख-रखाव के लिए आरडब्ल्यूए को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है और यह केवल एक्ट बनने के बाद ही संभव है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का मानना है कि टेकओवर के बाद नगर निगम केवल जरूरी सुविधाओं का रख-रखाव कर सकती है लेकिन गैर-जरूरी सुविधाएं नगर निगम के दायरे से बाहर है। ऐसे में इन सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय आरडब्ल्यूए ही पूरी कर सकती है।

गरीब सवर्णों को आरक्षण देना सराहनीय कदम: अजय शर्मा

गुरुग्राम। सामाजिक समरसता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले का ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शर्मा ने स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग वर्षों पुरानी थी जिसका हम लगातार पुरजोर विरोध कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उन गरीब सवर्णों को उनका हक दिया जाए। नहीं तो वह समाज से अलग-थलग हो जाएंगे सरकार ने हमारी मांगों को मानते हुए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला किया है। इस फैसले का समस्त ब्राह्मण समाज स्वागत करता है। ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि गरीब स्वर्ण इस फैसले से खुशी के मारे झूम रहा है। यह ऐतिहासिक फैसला भारत देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है हमारी यह बहुत पुरानी मांग थी। जिस काम कई बैठकों के माध्यम से और स्वर्ण सेना के माध्यम से हम लगातार मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे कि हमारे बच्चों की हालत जो निंदनीय हो गई है। उसकी तरफ ध्यान दिया जाए हमारी मांग को हमारे बड़े नेताओं ने बड़े स्तर पर उठाया। ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष अजय शर्मा, महासचिव सुरेश वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष चिदाम्बर शर्मा, राजकुमार त्यागी, सुरेश कौशिक, गोविंद वशिष्ठ, नरेंद्र भारद्वाज, निर्मल भारद्वाज, ओपी शर्मा आदि मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता 11 से

फर्रुखनगर। खंड के गांव जाटौला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से दो दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 11 जनवरी से किया जाएगा। खेल प्रतियोगिता में 100, 400 मीटर दौड़, वॉलीबाल, कबड्डी, लोंग जंप, हाई जंप प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। यह जानकारी आदर्श यूथ कलब के अध्यक्ष आदर्श शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रुप में जिला परिषद के उप प्रमुख संजीव यादव विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व प्रतीक चिंह देकर सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड लेकर आये। इंटरी 11 जनवरी को सुबह दस से ग्यारह इंटरी दर्ज की जाएगी।

बंदी और सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज

सोहना। भोंडसी थाना जिला जेल अधीक्षक की शिकायत पर बंदी और पुलिस गार्द में शामिल सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला जेल अधीक्षक ने बंदी के पास तलाशी में पाया गया मोबाइल सिपाही द्वारा दिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। भोंडसी जिला जेल से सोमवार दोपहर के बाद ढाई बजे बंदियों को मेडिकल जांच के लिए गुरुग्राम नागरिक अस्पताल ले जाया गया था। गुरुग्राम मेडिकल जांच के लिए गए बंदियों में जिला बदायु के गांव नाडा जोरिफ निवासी आदिल भी शामिल था। अस्पताल से जांच कराने के बाद बंदियों की जेल की ढोढी में तलाशी ली गई। वार्डन सोनू को तलाशी के दौरान बंदी आदिल के दाएं पैर में मोवाइल फोन चिपका मिला। जेल अधीक्षक जयसिंह छिल्लर ने पुलिस को दी शिकायत बताया कि बंदी आदिल को मोबाइल गुरुग्राम अस्पताल में जांच के दौरान पुलिस गार्द में शामिल सिपाही मनीष ने उसे दिया था। जेल अधीक्षक की शिकायत पर भोंडसी थाना पुलिस ने सिपाही मनीष को सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सिपाही को मंगलवार की सुबह अदालत में पेश किया। अदालत ने सिपाही मनीष को जमानत पर छोड़ दिया है।

वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते दो आरोपी पकड़े

नूंह। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देशी कट्टा भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर झिरका थाने की पुलिस को सूचना मिली कि दो अज्ञात युवक इरटीगा गाड़ी में देशी कट्टा लेकर फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र महूं चौपड़ा के समीप घूम रहे हैं। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से नाकाबंदी की तो बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस दोनों आरोपियों को गाड़ी सहित दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम जाहुल पुत्र हनीफ निवासी टूंडलाका व नसीम पुत्र अब्बास निवासी पैमाखेड़ा कबूला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामाल दर्ज कर उन्हें अदालत से दो दिन की रिमांड पर ले लिया है, जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है।

केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के छात्र भिड़े, एक घायल

सोहना। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के छात्र गुटों के झगड़ा होने से एक छात्र घायल हो गया। जिसे सोहना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। मंगलवार को केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के बाहर बना सैनी बाबा पर यूनिवर्सिटी के छात्र चाय पी रहे थे। उसी समय यूनिवर्सिटी के छात्रों का दूसरा गुट वहां पहुंच गया। चाय पी रहे द्वारका दिल्ली निवासी छात्र दीपक की दूसरे गुट के छात्रों से तू-तड़ाक हो गई। यह तू-तड़ाक बढ़ने पर दोनों गुटों के छात्रों के बीच लाठी और डंडे चलने लगे। झगड़े में छात्र दीपक के कपड़े तक फट गए। घायल छात्र को नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। घायल छात्र ने आरोपियों के खिलाफ सोहना सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच करती और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करती, उससे पहले दोषी छात्रों ने अपनी गलती मानते हुए मामले को रफा-दफा कर दिया। सोहना सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भारतेन्द्र कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी दरखास्त वापस ले ली है। जिसके कारण मामला दर्ज नहीं किया है।

आरटीओ ने एक माह में एक करोड़ से अधिक के काटे चालान

गुरुग्राम। गुरुग्राम में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग के चालान और फर्जी रोडवेज की बसे कब्जे में ली गई है। जिनसे एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। गुरुग्राम का आरटीओ विभाग लगातार सीएम फ्लाईंग के रूप में अभियान चलाकर सबसे ज्यादा जुमार्ना वसूले वाला प्रदेश का पहला जिला स्तर का आरटीओ विभाग बन गया है। हर माह एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना ठोक कर सरकार के खजाने को भरने में जुटा हुआ है। साल 2018 में विभाग की तरफ से करीब 12 करोड़ से ज्यादा का जुमार्ना लगाया है, जिनमें ओवर लोडिंग और फर्जी बसे शामिल हैं। गुरुग्राम के एडीसी आरके सिंह ने बताया कि गुरुग्राम के आरटीओ विभाग की तरफ से पूरे साल भर में ये अभियान चलाया गया है।

जन भावना के अनुरूप ही मोदी के निर्णय : भूपेंद्र

भावना को सम्मान और समान अधिकार दे रहे

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

बीजेपी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने कहा है कि देश के सर्वमान्य लोकप्रिय पीएम नरेंद्र भाई मोदी, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले प्रधान सेवक हैं। पीएम मोदी जो भी निर्णरू करते अथवा लेते हैं, उसके पीछे यही भवना होती है कि देश के अधिकाधिक लोगों को निर्णय की सीधा लाभ भी मिलना चाहिये। इन्ही सभी बातों को केंद्र में रखते हुए अब पीएम मोदी के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण की सुविधा की घोषणा की गई है।

यह बात भाजपा नेता भूपेंद्र चौहान ने मंगलवार को पटौदी सब डिवीजन के हेलीमंडी के जाटौली क्षेत्र में हेलीमंडी भाजपा मंडल अध्यक्ष अभय सिंह चौहान के यहां पहुंचने पर कही। इस मौके पर हेलीमंडी पालिका चेयरमैन सुरेश यादव, वाइस चेयरमैन विक्रांत विक्की, परीक्षित, बिजेंद्र, धमेंज्द्र, भागीरथ, सुनील, दानसिंह, ललित, सुनील कुमार, दीपक शर्मा, राहुल शर्मा, सोनू, विकम सिंह चौहान, मनबीर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

पीएम मोदी के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण की सुविधा की घोषणा की खुशी को भाजपाइयों ने आसपास के लोगों को मिठाई बांटकर सांझा की। इसके साथ ही अपील भी की कि आगामी चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करके एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। भूपेंद्र चौहान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी पीएम-प्रधान सेवक देश को मिला है, जो कि केवल और केवल राष्ट्र हित में ही चिंतन करते हैं।

गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने में सभी विभाग करें सहयोग

बैठक में जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से स्वच्छता कार्य में सहयोग की अपील

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम स्थित लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त वाईएस गुप्ता।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार जनवरी से स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 शुरू किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में नगर निगम गुरुग्राम भी भागीदारी कर रहा है। गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलवाने में सभी विभाग अपना सहयोग दें। यह बात नगर निगम के एडीशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर वाईएस गुप्ता ने स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नगर निगम गुरुग्राम स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहा है। नगर निगम द्वारा बनाए गए सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को बेहतर बनाया गया है तथा गुरुग्राम को ओडीएफ प्लस श्रेणी का सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है।

ओडीएफ प्लस श्रेणी का सर्टिफिकेट हासिल करने वाला गुरुग्राम शहर प्रदेश का पहला शहर है तथा तीन लाख से 10 लाख की आबादी वाले देश के अन्य शहरों में भी गुरुग्राम पहला ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाला शहर बना है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने कार्यालयों, शौचालयों को साफ एवं स्वच्छ करवाएं और अगर इस कार्य में किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, तो नगर निगम सहायता उपलब्ध करवाएगा। सभी अधिकारी अपने मोबाइल में स्वच्छता एप डाऊनलोड करें तथा गंदगी संबंधी शिकायत एप के माध्यम से भेजें। प्राप्त शिकायत का समाधान नगर निगम द्वारा 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। इसके साथ ही एप पर स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 से संबंधित फीडबैक भी प्रदान करें। इस प्रकार हम अपने शहर को एक ओर जहां स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में बेहतर स्वच्छता रैंकिंग में शामिल करवाने का भी कार्य करेंगे।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 और कचरे को अलग-अलग करने संबंधी जागरुकता पैंपलेट भी वितरित किए गए और आह्वान किया कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस बारे में जागरूक करें। नगराधीश मनीषा शर्मा ने मौके पर ही अपने मोबाइल में स्वच्छता एप डाऊनलोड की। नगर निगम के आईटी सलाहकार विनोद वर्मा ने अधिकारियों को स्वच्छता एप डाऊनलोड करने और उसका उपयोग करने के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर एवं स्वच्छ भारत मिशन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी इन्द्रजीत कुल्हड़िया, प्रोजेक्ट इंप्लीमैंटेशन यूनिट की सिटी लीडर सोनिया दूहन, आदि अधिकारी उपस्थित थे।

रजिस्ट्रियां भी नहीं रोक पाईं पीले पंजे की रफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

फर्रुखनगर के मुख्य बाजार में पीले पंजे का विरोध करते दुकानदार।

फर्रुखनगर नगरपालिका के पीले पंजे ने दूसरे दिन भी नगर के मुख्य बाजार व बस अड्डे पर जमकर तोड़फोड़ की। कार्रवाई में आई छुट-पुट बाधाओं और जमीन के नक्शे दस्तावेज आदि को दर किनार करके पालिका सचिव केके यादव ने पीले पंजे की गति को थमने नहीं दिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार प्रदीप पहावा के समक्ष लोगों ने अपनी दुकानों, चबूतरों की रजीस्ट्रियां रखीं, लेकिन वहां भी दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिली और असहाय होकर पीले पंजे को खून पसीने से तैयार अपनी ही जमीन पर बने चबूतरों को टूटता देखते रहे। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान असहाय दुकानदार अपने जनप्रतिनिधियों को कौसते नजर आये।

दुकानदारों के बार-बार आग्रह पर भी कोई पार्षद पीले पंजे की गति में बाधा बनना तो दूर दुकानदारों को दिलासा देने भी नहीं पहुंचे। पीले पंजे ने दूसरे दिन भी करीब सात दर्जन दुकानों के सामने बने चबूतरे, टिनशेड हटाये। गुस्साये दुकानदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट में घसीटने की भी धमकी दी, लेकिन सचिव के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया और अपने निर्णय पर ही अडिंग रहे। बतां दे कि पिछले करीब पांच छह दशक से फर्रुखनगर के मुख्य बाजार में दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने पक्के चबूतरे, टिनशेड के नाम अतिक्रमण की शिकायत काफी समय से अधिकारियों को मिल रही थी, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण अधिकांश दुकानदार अपने कब्जा जमाये हुए थे।

नपा प्रशासन ने गत दिनों दुकानदारों को अपने अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी चेताया था, लेकिन पूर्व की भांति उन्होंने उस अपील पर गौर नहीं दिया और नपा प्रशासन की कार्रवाई को हलके में लेकर अपने आकाओं पर आश्रित रहे। पीले पंजे ने जैसे ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की तो दुकानदार सकते में रह गये कि पहले तो आकाओं के फोन से ही पीला पंजा रुक जाता था, लेकिन इस बार पीले पंजे के पीछे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया गया। जिसके चलते छुटपुट विरोध के बाद कार्रवाई आसानी से आगे बढ़ती रही।

नशे में धुत मिला एमरजेंसी का डाक्टर, वीडियो वायरल

पायनियर समाचार सेवा। नूंह

जिले के नागरिक अल-आफिया-अस्पताल मांडीखेड़ा में एमरजेंसी के एक डॉक्टर का ड्यूटी के दौरान बंद कमरे में शराब पीने का मामला प्रकाश में आया है। मामला सोमवार सुबह करीब चार बजे का। शराबी डॉक्टर की पोल तब खुली जब एक दर्द से पीड़ित मरीज ने उसी कमरे का दरवाजा खटखटा दिया, जिसमें डाक्टर साहब शराब के नशे में धुत लेटे थे। इतना ही नहीं मरीज के साथ दूसरे व्यक्ति ने घटना को मोबाइल में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके अलावा शराबी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए वीडियो को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक भी ट्वीट कर दिया।

जावेद पुत्र रुकमुद्दीन निवासी भादस ने बताया कि सोमवार को वह दर्द से पीड़ित एक मरीज को लेकर मांडीखेड़ा के सामान्य अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में गया था। जब उसे डॉक्टर की कुर्सी खाली दिखाई दी, तो उन्होंने डाक्टर को इधर-उधर तलाशा। अचानक युवक ने उसी कमरे को खोल दिया, जिसमें डॉक्टर साहब शराब पीकर लेटे थे। युवक तुरंत अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया और सोशल साइट पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में हडकंप मच गया। जब इस मामले का सिविल सर्जन को पता चला तो उन्होंने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर शराबी डॉक्टर का दूसरी जगह तबादला कर दिया।

आंशिक हड़ताल

जन-जीवन सुस्त दिखा, जरूरी सेवाओं पर सीमित असर, तीन गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर मंगलवार को की गई हड़ताल से शहर में मिश्रित असर दिखाई पड़ा। बिजली एक-दो कटों को छोड़कर सामान्य रही। यात्रियों को रोडवेज की बसें कम मिलीं, तो उन्होंने निजी बसों, मेट्रो और ट्रेनों का सहारा लिया। बैंक की कई शाखाओं में हड़ताल रही, तो कुछ बैंक शाखाओं छुटपुट काम हुआ। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं और ओपीडी भी आशिंक तौर पर चलती दिखी। प्रशासन और सरकार की मुस्तैदी के कारण शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और न ही जन-जीवन पटरी से उतरा दिखाई पड़ा। पुलिस ने तीन रोडवेज कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

फोटो: राजेश पुंजानी

तीन कर्मचारी गिरफ्तार

रोडवेज के बल्लभगढ़ बस अड्डा पूरी तरह छावनी बना हुआ था। रोडवेज की बसों का परिचालन प्रभावित दिखा। हालांकि कुछ सरकारी बसें भी चल रही थीं, लेकिन ज्यादातर निजी बसों से ही यात्रियों ने सफर पूरा किया। सभी बसें खचाखच भरी थीं और युवाजन तो बसों की छतों पर भी बैठे हुए थे। बसों के परिचालन में व्यवधान पहुंचाने पर रोडवेज के नेता बीरेंद्र सिंह, राजू सौरोत वह नाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के साये में कुछ बसों को पुलिस लाइन में ले जाया गया, जिसका वहां मौजूद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा के नेतृत्व में जमकर विरोध किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जीएम रोडवेज विकास यादव का दावा है कि हड़ताल का परिवहन सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमने 50 बसों को सोमवार की रात को ही पुलिस लाइन और एनआइटी बस अड्डे भेज दिया था। अन्य बसों को सुबह निकाल दिया। पूरे दिन में हमने 134 बसों को चलाया है, जो अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा हैं।

बिजली सामान्य रही

हड़ताल के कारण बिजली निगम के लगभग सभी कार्यालय व शिकायत केंद्रों में काम-काज प्रभावित रहा। इन कार्यालयों पर पहुंचे उपभोक्ता हड़ताल की सूचना से मायूस दिखे। बिजली की इतनी मेहरबानी रही कि एक-दो कटों को छोड़कर सारा दिन बिजली व्यवस्था सामान्य रही। बिजली अफसरों ने हड़ताल के बावजूद कुछ कर्मचारियों और ठेके के कर्मियों से बिजली व्यवस्था को सामान्य बनाए रखा। कुछ बिजली दफ्तरों में कर्मचारियों ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता प्रदीप चौहान का दावा है कि अनुबंधित कर्मचारियों ने बिजली व्यवस्था को सामान्य बनाए रखा।

हड़तालियों ने निकाला जुलूस

अधिकांश विभागों के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय पर हड़ताल करके प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी विभागों के हड़ताली कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय बीके चौक पर एकत्रित हुए। यहां कर्मचारियों ने सभा का आयोजन किया और नीलम चौक तक जुलूस निकाला। बुधवार को डीसी आफिस पर प्रदर्शन किया जायेगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री व मुख्य संगठनकर्ता वीरेंद्र सिंह डंगवाल , जिला प्रधान अशोक कुमार व सचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने हड़ताल की सफलता का दावा करते हुए कहा कि अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ निर्णयाक आन्दोलन के लिए तैयार है। सभा को प्रमुख रूप से अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फैडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान, एटक के महासचिव बेचू गिरी,सर्व कर्मचारी संघ के मुख्य संगठनकर्ता वीरेंद्र डंगवाल, नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बड़े पूंजीपतियों, ठेकेदारों की गोदी में खेल रही है। देश की धन संपदा को अपने बड़े कारपोरेट यारों को लुटवा रही है। और कहती है कि मजदूरों-कर्मचारियों के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। मजदूर हितों में बने कानूनों को खत्म कर रही है। यह स्वीकार नहीं होगा। देश का मजदूर व कर्मचारी इसका हिसाब लेगा।

सफाई प्रभावित

नगर निगम के तीनों जोन कार्यालय में अधिकतर कर्मचारी हड़ताल पर रहने के कारण कामकाज ठप रहा। एनआईटी स्थित मुख्यालय पर तो कर्मचारी नेताओं ने ताला ही जड़ दिया। यहां पहुंचे बिल जमा करवाने पहुंचे उपभोक्ताओं ने कहा कि वे हड़ताल के बाद बिल जमा करवा देंगे। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण गलियों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। कुछ स्थानों पर ठेके के कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू चलाते हुए भी दिखाई दिए।

तंदूर ठंडे रहे

कर्मचारी नेताओं का दावा है कि टूरिज्म के बड़खल, सूरजकुंड, मैगपाई, अरावली गोल्फ क्लब, राजा नाहर सिंह महल में भी हड़ताल के कारण तंदूर ठंडे पड़े रहे। यहां पहुंचे ग्राहकों को कुछ केंद्रों से उल्टे पैर लौटना पड़ा, तो कुछ को मैन्यू में कंपोमाइज करना पड़ा। हुडा विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण काम काज बुरी तरह प्रभावित रहा। जन स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण आदि विभागों में भी भारी संख्या में हड़ताल पर रहे। वन, आईटीआई, पशुपालन, पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य आदि विभागों में भी हड़ताल का असर रहा।

संक्षिप्त समाचार

नगर निगम इंजीनियरों को मिले वित्तीय अधिकार

फरीदाबाद। नगर निगम के विकास कार्यों का बजट अब इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे। अभी तक यह अधिकारी संयुक्तायुक्तों के पास थे। सभी जोन में संयुक्तायुक्त नहीं होने के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसके चलते नगर निगम आयुक्त अतुल द्विवेदी ने अब यह अधिकार मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं को दे दिए हैं। नए आदेश के तहत 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए कार्यकारी अभियंता, 25 से 50 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए अधीक्षक अभियंता और 50 लाख रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों के लिए मुख्य अभियंता ठेकेदारों से या विकास कार्य करने वाली कंपनियों के अधिकारियों से मोलभाव कर सकेंगे। इसमें नए विकास कार्य, मरम्मत के कार्य, खरीदारी या फिर सेवा कार्य हों, सभी के लिए यह आदेश लागू होंगे। आयुक्त के इस निर्णय से नगर निगम के विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। अभी तक ठेकेदारों से मोल भाव करने का अधिकार संयुक्तायुक्तों के पास था। सभी बीते कई वर्षों से तीनों जोनों में एक साथ संयुक्तायुक्त नहीं रहे हैं। कभी किसी जोन में संयुक्तायुक्त नहीं है, तो कभी कोई जोन कई महीनों तक बगैर संयुक्तायुक्त के चलता रहा। ऐसे में कई इलाकों में विकास कार्य शुरू नहीं हो सके थे। इसका असर जनप्रतिनिधियों की घोषणाओं पर भी पड़ रहा था।

तिपहिया चालक की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में जीता स्वर्ण

पलवल। शहर की बेटी नीलम चौधरी ने नेपाल के पोखरा में एक जनवरी को आयोजित हुई अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा कर क्षेत्र सहित जिले का नाम रोशन किया है। नीलम की इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर नीलम का गांव ललपुरा स्थित तुलसीराम अखाड़े पर मंगलवार सुबह जोरदार स्वागत किया गया। पलवल के वार्ड नंबर-3 निवासी नीलम के पिता तिपहिया चालक है और उसकी माता मूर्ति देवी गृहणी हैं। सामान्य परिवार से होते हुए भी नीलम ने स्वर्ण जीतकर जिले ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। नीलम ने बताया कि उसको बचपन से ही कुश्ती का शोक रहा है। नीलम ने इस प्रतियोगिता में अंडर-19 आयु वर्ग में हिस्सा लिया और 51 किलोग्राम भारवर्ग में नेपाल की सुजेन को हराकर इस स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा किया। इससे पूर्व नीलम ने गोआ में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। नीलम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप में 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है और वह पढाई में भी अव्वल है। वह गांव ललपुरा मोड़ स्थित तुलसीराम अखाड़े पर पहलवान तुलसी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।

केजीपी: ट्राले से कुचलकर चार मरे,10 बकरियों की भी मौत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

केजीपी (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस वे) पर बीती रात गांव शाहजहांपुर के पास तेज रफ्तार से दौड़ रहे एक ट्राला के चालक ने लापरवाही से सड़क किनारे खड़े भेड़ बकरियों से भरे एक खराब कैंटर में को जोरदार टक्कर मार दी। कैंटर को टक्कर मारने के बाद ट्राला ने वहीं पर खड़े चार अन्य लोगों को कुचल दिया। इस घटना में चारों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों मृतक कैंटर पर भेड़-बकरियां लदवा कर दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बेचने के लिए जा रहे थे। कैंटर पंचर होने के बाद चारों सड़क किनारे खड़े होकर स्टैपनी बदलने का इंतजार कर रहे थे। तीन मृतक फिरोजपुर झिरका और एक यूपी के ऐटा का रहने वाला था। ट्राला की टक्कर से कैंटर में लदी 10 बकरियों की भी मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिए हैं।

थाना छांयसा में दर्ज मामले के मुताबिक फिरोजपुर झिरका के भाकडौजी गांव निवासी रफीक ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह कैंटर चलाता है। सोमवार को उसके कैंटर को गांव के ही कुछ लोगों ने दिल्ली की गाजीपुर मंडी ले जाने के लिए बुक किया था। यह लोग उसके कैंटर में भेड़-बकरी भरकर गाजीपुर मंडी में बेचने के लिए ले जा रहे थे। रात को करीब 12 बजे उसका कैंटर केजीपी से गुजर रहा था। गांव शाहजहांपुर के पास यमुना पुल पर पहुंचने पर कैंटर का पिछला टायर पंचर हो गया। उसने कैंटर को सड़क के किनारे पर रोककर खड़ा कर लिया और कैंटर में रखी स्टेपनी को बदलने लगा। चालक रफीक का कहना है कि जब वह पहिया बदल रहा था, उसी समय गाड़ी में सवार पूरण, तालिम, मौसिम व नईम भी नीचे उतर आए और कैंटर के पास खड़े हो गए। जबकि अन्य 4-5 लोग दूर खड़े होकर धूम्रपान करने लगे।

आरोप है कि तभी पलवल की ओर से तेजगति में आ रहे ट्राला ने खड़े हुए कैंटर को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से कैंटर पलट गया और सड़क के पास खड़े चारों लोगों को ट्राला ने कुचल दिया। इस हादसे में फिरोजपुर झिरका के भाकडौजी गांव निवासी पूरण, तालिम, मौसिम और यूपी के ऐटा में रहने वाले नईम की मौत हो गई। कैंटर पलटने से 10 बकरियां भी मर गईं। जबकि कैंटर चालक रफीक मामूली रूप से जख्मी हो गया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक ट्राला को छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पाकर थाना छांयसा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों लोगों के शवों को बीके अस्पताल पहुंचाया। घायल चालक को सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया।

रहस्यमय हालत में युवक की मौत, हत्या की आशंका

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

पर्वतीय कालोनी के चाचा चौक पर रहने वाले एक युवक की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। मृतक रात को ठीक ठाक सोया था, लेकिन सुबह बिस्तर पर मृत पाया गया। मृतक के ससुराल वालों ने उसके सौतेले पिता और भाई द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पर्वतीय कालोनी निवासी रेखा ने बताया कि उसका परिवार नंगला रोड के भड़ाना चौक पर रहता है। वह निजी अस्पताल में नर्स का काम करती है। उसकी बड़ी बहन मंजू का विवाह करीब ढाई साल पहले चाचा चौक पर रहने वाले आकाश के साथ हुआ था। आकाश राजमिस्त्री का काम करता था और अपनी मां, सौतेले पिता और भाईयों के साथ रहता था। शादी के बाद ससुराल वालों ने उसकी बहन को बुरी तरह परेशान करना शुरू कर दिया। बीमार होने पर ससुराल वाले इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे, जिसके कारण करीब आठ महीने पहले मंजू इलाज करवाने के लिए मायके आ गई थी।

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए बीके भेज दिया

रेखा का आरोप है कि आकाश के सौतेले भाईयों ने दहेज में दी गई बाइक पर कब्जा किया हुआ था। वे लोग अक्सर आकाश के साथ भी मारपीट करते रहते थे। सुबह आकाश के किसी रिश्तेदार ने फोन करके बताया कि उसकी मौत हो गई है। वे उनके घर पहुंचे, तो आकाश जमीन पर मृत हालत में पड़ा हुआ था। उसके परिजनों का कहना था कि ज्यादा शराब पीने के कारण आकाश की मौत हुई है। पीड़िता ने संदेह जताया कि आकाश की किसी ने हत्या की है। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सरपंच परिवार के हमलावरों पर एससी-एसटी केस दर्ज

फरीदाबाद। गांव पाखल में रविवार देर शाम सरपंच परिवार पर लाठी-डंडों से हमला मामले में पुलिस ने दो नामजद सहित सात-आठ अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मारपीट के अलावा एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं।

हमले में गांव की सरपंच वर्णिका के जेठ बिसन व देवर होशियार को बुरी तरह पीटा गया था। उनके हाथ-पैर तोड़ डाले गए थे। बिसन को मेट्रो अस्पताल में आइसीयू में भर्ती कराया गया, वहीं होशियार को भी काफी चोटें आई हैं। होशियार सिंह ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर गांव में अवैध कब्जों को हटावाया था। इससे गांव के कुछ लोग खफा थे। उन्होंने सरपंच को भी बुरा-भला कहा था। ये लोग किसी ना किसी बहाने से उनके परिवार को निशाना बना रहे थे। रविवार को नितिन, बिट्टू के अलावा सात-आठ अन्य लोगों ने सरपंच के परिवार पर हमला कर दिया। धौज थाना प्रभारी सुभाष का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

फर्जी जमानत देने वाले नपेंगे

फरीदाबाद। नाइजीरियाई नागरिकों की फर्जी पहचान पत्रों से जमानत लेने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार की अदालत ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायाधीश के रीडर रतिराम ने बताया कि ड्रग्स रखने के मामले में नाइजीरियाई नागरिकों नामडी इनोसेंट और अजीवेका ओनिश्ठा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। डबुआ कॉलोनी निवासी राहुल और सुरेंद्र ने अदालत से इनकी जमानत ली। जब अदालत ने पेश किए गए पहचान पत्रों की जांच की, तो वे फर्जी मिले। अदालत ने राहुल और सुरेंद्र के साथ दोनों नाइजीरियाईयों पर केस दर्ज करवाया है।

अस्पतालों में बढ़ रही बालों में रूसी के मरीजों की संख्या

कविता। फरीदाबाद

सर्दियों के मौसम में बालों में रूसी पैदा होने की समस्या आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। इसके कारण से सिर में खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याएं सामने आ रही है। इस बदलते मौसम में महिलाओं व पुरुषों के अलावा बच्चे भी रूसी की परेशानी से जूझ रहे हैं। शहर में मौजूद निजी व सरकारी अस्पतालों में मौजूद त्वचा रोग विशेषज्ञों के पास बालो में रूसी से परेशान मरीजों की भरमार है।

जानकारी के मुताबिक बालों में रूसी होने की समस्या सर्दियों के मौसम मे होना आम बात हो गई है। इसके प्रभाव में बच्चे व युवा भी आ रहे हैं। इसके कारण से सिर में खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। बीके अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष गुप्ता ने बताया कि इस मौसम में रोजाना करीब 20 मरीज इस समस्या से ग्रस्त होकर इलाज के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में सिर में पसीना कम निकलता है, जिसके कारण से सिर व बालों में रूखापन आ जाता है, जिसके कारण से सिर में रूसी हो जाती है। उन्होंने बताया कि इससे बचने के लिए चार महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला सिर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन सिर को किटोकोनाजो पाना जेल नामक शैंपू से धोना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस शैंपू का इस्तेमाल करीब एक महीने तक करना चाहिए। इसके अलावा खाना समय पर व भरपूर खाना चाहिए, शरीर की शक्तिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। पूरी नींद लेनी चाहिए और मॉर्निंग वॉक अवश्य करना चाहिए। डॉ. गुप्ता का कहना है कि रूसी के चांस सर्दियों में अधिक बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए बालों का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए।

बालों को रखें ढंककर

डॉ. गुप्ता ने बताया कि शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करना बालों के लिए जरूरी होता है। सर्दियों के दौरान बालों की अच्छे से कंडीशनर करना चाहिए, इससे बाल रूखे नहीं होंगे। उलझे बालों से छुटकारा पाने के लिए सप्ताह में दो दिन बाल धोएं। सर्दी के महीनों में बालों को जितना हो सके उतना ढककर रखें, अन्यथा बाल रूखे हो जाएंगे।

तहसीलदार पर रजिस्ट्री के लिए रिश्वत मांगने का आरोप

बल्लभगढ़। तहसीलदार द्वारा बयनामा करने के नाम पर 40 हजार रुपये मांगने पर एक वकील ने डीसीपी से शिकायत की है। बार के पूर्व प्रधान स्वर्ण सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि वे तहसीलदार सुशील शर्मा से बयनामा कराने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने बयनामा करने के बदले 40 हजार रुपये देने की पेशकश की। जब रुपये देने से मना कर दिया, तो तहसीलदार ने काम छुड़वाने की धमकी दी। तहसीलदार को बताया कि उन्हें काम करने के बदले सरकार वेतन देती है। वकील को कोई वेतन नहीं मिलता। ये बात सुनने पर तहसीलदार ने काम छुड़वाने की धमकी दी। तहसीलदार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

स्वाइन फ्लू मरीजों को मिलेंगे रोजाना आठ हजार

फरीदाबाद। प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू के गंभीर रोगियों (आईसीयू) का अपने खर्च पर निजी अस्पताल में उपचार कराएगी। इसके लिए ऐसे मरीज को रोजाना आठ हजार रुपये दिए जाएंगे। ऐसे गंभीर रोगी का बीके अस्पताल से रेफर करना होगा। जिले के राजकीय अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं होने के कारण प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों से करेगा अनुबंध दरअसल, स्वाइन फ्लू के गंभीर मरीज के लिए आईसीयू की जरूरत पड़ती है और बीके अस्पताल में इसकी सुविधा नहीं है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वाइन फ्लू के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए निजी अस्पताल से अनुबंध करने जा रही है। आईसीयू केयर की जरूरत पड़ने पर रेफर किए गए मरीज को विभाग रोजाना आठ हजार रुपए मुहैया कराएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए अनुबंध की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जिले के कुछ नामचीन अस्पतालों से संपर्क किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू को लेकर विभाग हुआ गंभीर जिले में एक सप्ताह के दौरान 14 संभावित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से चार मरीजों की पहचान बीके अस्पताल की ओपीडी में हुई है।

मजदूर संघों की हड़ताल का रहा मिला जुला असर

पश्चिम बंगाल में हड़ताल के दौरान उपद्रव की छिटपुट घटनाएं

एजेंसी। कोलकाता

केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय मजदूर संघों द्वारा आहूत 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल के दौरान मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में उपद्रव की छिटपुट घटनाएं हुईं। उत्तर 24 परगना जिले में बारासात के चंपाडाली इलाके में एक स्कूल बस पर पथराव किया गया और हड़ताल समर्थकों ने एक सरकारी बस में भी तोड़फोड़ की। हड़ताल समर्थकों ने कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके और टायर जलाए।

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हड़ताल समर्थकों को जबरन हड़ताल लागू करने से रोकने की कोशिश की। इसके कारण हावड़ा, सिलीगुड़ी, वर्द्धमान, बीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हड़ताल समर्थकों के बीच झड़पें हुईं। हिंसा की घटनाओं के बावजूद कुछ इलाकों को छोड़कर कोलकाता एवं उसके आसपास और राज्य के अन्य हिस्सों में जनजीवन दोपहर 12 बजे तक कमोबेश सामान्य रहा। इस बीच, बसें और अन्य वाहन सड़कों पर चलते दिखे लेकिन यात्रियों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में बहुत कम थी। पश्चिम वर्द्धमान जिले के जमुरिया में प्रदर्शनकारियों ने एक बस में तोड़फोड़ की। राज्य के कुछ इलाकों में पुलिस और हड़ताल समर्थकों के बीच हाथापाई भी हुई। दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके में वरिष्ठ माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती के साथ कई अन्य हड़ताल समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी ट्रेनों को रोकने के लिए कुछ स्थानों पर पटरियों पर बैठ गए और सड़कों पर टायर जलाए। माकपा सहित कई राजनीतिक दलों के नेता हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने हड़ताल का विरोध किया है।

सीटू के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने मालदा में मंगलवार को हड़ताल के दौरान एक ट्रेन को रोक दिया।

भुवनेश्वर में देशव्यापी आम हड़ताल के दौरान एनएच -16 पर जलते टायर को बुझाता एक पुलिसकर्मी

केरल में ट्रेनें रोकी गईं, बस, ऑटो-रिक्शा सड़कों से नदारद

तिरुवनंतपुरम। केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय मजदूर संघों द्वारा आहूत 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल के दौरान राज्य में मंगलवार को ट्रेनों को रोका गया और बसें एवं ऑटो रिक्शा के सड़कों से नदारद रहने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। इस दो दिवसीय हड़ताल का विभिन्न क्षेत्र के कर्मचारियों ने समर्थन किया है। तिरुवनंतपुरम, त्रिपुनिथुरा और शोरनुर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोका गया। भारतीय मजदूर संघ के अलावा सभी मजदूर संघ हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। रजस्वला आयुवर्ग की दो महिलाओं के सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने के बाद दक्षिणपंथी समूहों द्वारा बुलाए गए बंद के पांच दिन बाद यह हड़ताल की जा रही है। सबरीमला मंदिर के श्रद्धालु हड़ताल से प्रभावित ना हों इसलिए केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) विभिन्न स्थानों से पम्बा के लिए बसें चला रही है। हालांकि केएसआरटीसी की बसें अन्य मार्गों पर नहीं चल रही हैं। राज्य में कई स्थानों पर दुकानें खुली रहीं। मजदूर संघों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वे दुकानें बंद करने के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाएंगे और ना ही व्यापारियों को निशाना बनाया जाएगा। केरल व्यापारी व्यावसाई एकोपना समिति ने कहा था कि वे अपने व्यावसायिक संस्थापन खुले रखेगा।

हड़ताल का कर्नाटक में दिखा मिलाजुला असर

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर संघों द्वारा आहूत 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का मंगलवार को कर्नाटक में मिलाजुला असर देखने को मिला। राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें राज्य में अधिकतर स्थानों पर सड़कों से नदारद रहीं, जिससे लोगों को यात्रा करने के लिए निजी बसों, ऑटो, टैक्सी और मेट्रो का इस्तेमाल करना पड़ा। मैसूर बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़ सहित अन्य स्थानों पर हड़ताल का मिलाजुला असर रहा। कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई और परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) की कुछ ही बसें सड़क पर नजर आईं।

अधिकारियों ने बताया कि यात्री भी थोड़े ही थे क्योंकि अधिकतर लोगों को हड़ताल की जानकारी थी और उन्होंने अन्य साधनों का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने बताया कि मल्लेश्वरम में कुछ असामाजिक तत्वों ने बीएमटीसी की दो बसों पर पथराव भी किया। ऑटो चालकों के अधिक किराया लेने की शिकायतें भी मिलीं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होटल, दुकानें और मॉल तथा सिनेमा हॉल जैसे अन्य संस्थानों के मालिकों ने मजदूर संघों की हड़ताल के समर्थन में इन्हें बंद रखा। बैंक सेवाओं के भी प्रभावित होने की संभावना है। मजदूर संघ ने मंगलवार को शहर के टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक और बुधवार को टाउन हॉल से राज भवन तक विरोध मार्च निकालने का फैसला लिया है।

पुलिस ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस हड़ताल को हताश तत्वों द्वारा आहूत अतार्किक, तर्कहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उसने कहा कि लोगों ने इसे नाकार दिया है और वे अपनी दैनिक गतिविधियों में सामान्य रूप से लगे हैं।

ओडिशा में रेल और सड़क यातायात प्रभावित

भुवनेश्वर। केंद्र सरकार की कथित मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय मजदूर संगठनों द्वारा आहूत 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल के दौरान मंगलवार को ओडिशा में रेल और सड़क यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने बताया कि मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बंद के पहले दिन भुवनेश्वर, कटक, पुरी, बालेश्वर, जलेश्वर, भद्रक, संबलपुर, बरहामपुर और पारादीप सहित कई स्थानों पर रेल रोको आंदोलन किया।

उन्होंने बताया कि हड़ताल समर्थकों के रेल पटरियों को जाम करने से एक दर्जन से अधिक ट्रेनों में देरी हुई जिससे बड़ी संख्या में यात्री कई स्थानों पर फंस गए। इस दौरान दुकानें, बाजार, व्यापारिक संस्थान, शिक्षण संस्थान और कार्यालय बंद रहे। सड़कों पर से वाहन नदारद रहे। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में कई स्थानों और पूरी तरह से व्यस्त इलाकों में मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और टायर जलाकर सड़कों को जाम किया। उन्होंने मास्टर कैंटीन स्क्वायर पर धरना भी दिया। कटक में भी रेल रोको आंदोलन चलाने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने सड़कों को जाम किया और धरना दिया। भुवनेश्वर-कटक के पुलिस आयुक्त सत्यजीत मोहंती ने कहा कि हड़ताल के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अभी तक हड़ताल शांतिपूर्ण रही है। सत्तारूढ़ बीजद और उसके मजदूर संगठन बीजू श्रमिका सौख्य (बीएसएस) ने 10 मजदूर संघों द्वारा आहूत बंद का समर्थन किया है।

छत्तीसगढ़ में हड़ताल का मिलाजुला असर

रायपुर। केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रमुख ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का छत्तीसगढ़ में मिलाजुला असर रहा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के राज्य सचिव धर्मराज महापात्र ने मंगलवार को यहां भाषा को बताया कि दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन डाकघर, प्रमुख बैंक और बीमा कंपनियों में कामकाज प्रभावित हुआ।

महापात्र ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों में यूनियन के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। यूनियन प्रति माह 18 हजार रुपए न्यूनतम मजदूरी की मांग तथा सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में इस्पात, बिजली, बैंकिंग, बीमा और अन्य संगठित क्षेत्रों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक और कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राइस मिल मजदूर तथा मंडी मजदूरों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। महापात्र ने कहा कि बुधवार को हड़ताल के दूसरे दिन अधिक समर्थन मिलने की संभावना है।

वामपंथी सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक पेश

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में वाम दलों के सदस्यों के विरोध के बीच ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया जिसमें 1926 के कानून में संशोधन का प्रावधान है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक पेश किया जिसमें नीति निर्माण में श्रमिक संगठनों की भागीदारी के लिए कानूनी रूपरेखा बनाने का प्रावधान है।

देश में विभिन्न केंद्रीय श्रमिक संगठनों की दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल मंगलवार को शुरू होने के बीच कामगारों से संबंधित विधेयक पेश किए जाने का वामपंथी दलों के सदस्यों ने विरोध किया। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने विधेयक पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए सदन के कामकाज के कुछ नियमों और संविधान के कुछ अनुच्छेदों का हवाला दिया। माकपा के ए संपत ने कहा कि सदस्यों को आज सुबह ही विधेयक की प्रति मिली है। इससे पहले कामकाज की सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि जब लाखों लोग सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध हड़ताल करके कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह का विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक असंवैधानिक है। माकपा के एम बी राजेश और कांग्रेस के शशि थरूर ने भी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। थरूर ने कहा कि सरकार को बिना पूर्व सूचना के इतनी जल्दबाजी में विधेयक पेश करने के विशेष कारण बताने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि अभी केवल विधेयक पेश किया जा रहा है। बाद में इस पर चर्चा हो सकती है। श्रम मंत्री गंगवार ने कहा कि अभी तक नीति निर्माण में ट्रेड यूनियनों की भागीदारी का कोई मानदंड नहीं था। श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधित्व के लिए कानूनी रूपरेखा बनानी जरूरी थी जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है। इस पर विस्तृत चर्चा करके इसे पारित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मजदूर संगठन और इन्टक का एक धड़ा समेत छह श्रमिक संगठन मंगलवार को शुरू हुई हड़ताल में भाग नहीं ले रहे। इसलिए इस हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने वाम दलों के सदस्यों के विरोध के बीच विधेयक पेश किया। इस दौरान माकपा समेत वाम दलों के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। गौरतलब है कि विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल मंगलवार को शुरू हुई। इन यूनियनों ने सरकार पर श्रमिकों के प्रतिकूल नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है।

सीबीआई मामले में प्रधानमंत्री को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो: स्वामी

नई दिल्ली। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सीबीआई के निदेशक पद पर आलोक वर्मा को बहाल करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए मंगलवार को कहा कि वर्मा को कार्यमुक्त करने की सलाह देने वाले लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कार्रवाई करना चाहिए। स्वामी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, उच्चतम न्यायालय के फैसले का मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। वर्मा जैसे ईमानदार अधिकारी को इस तरह से बेइज्जत करना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार के लिए करारा झटका है क्योंकि वर्मा को कार्यमुक्त करने का फैसला सरकार का था। सरकार को इसमें विहित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। हालांकि, स्वामी ने प्रधानमंत्री की ईमानदारी को संदेह से परे बताते हुए कहा मेरा प्रधानमंत्री के साथ पत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद होता है। उसके आधार पर मेरा पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार के मामले में वह बिल्कुल साफ हैं।

गुजरात में पूर्व भाजपा विधायक की ट्रेन में गोली मारकर हत्या

एजेंसी। अहमदाबाद

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जयंतीलाल भानुशाली की सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब दो बजे भुज-दादर एक्सप्रेस ट्रेन में हुई जब भानुशाली (53) कच्छ जिले के भुज से अहमदाबाद लौट रहे थे। भानुशाली ने पिछले साल जुलाई में बलात्कार के आरोप लगने के बाद गुजरात भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने अगस्त 2018 में महिला के शिकायत वापस लेने के बाद केस रद्द कर दिया था। मोरबी जिले के पुलिस अधीक्षक कननराज वघेला ने कहा कि उन्हें कच्छ जिले के नजदीक गांधीधाम और सूरजबाड़ी स्टेशन के बीच गोली मारी गई। उन्होंने कहा, भुज-दादर ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिस ने मोरबी पुलिस को सूचित किया कि भानुशाली की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्रेन मोरबी के मालिया स्टेशन पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वघेला ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक उन्हें दो गोलियां मारी गईं।

उन्होंने कहा, हमें ट्रेन के डिब्बे से कारतूस के खोखे मिले हैं जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। रेलवे पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी। भानुशाली 2007 से 2012 के बीच अबदासा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे।

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में तृणमूल सांसदों का संसद भवन परिसर में धरना

एजेंसी। नई दिल्ली

तृणमूल कांग्रेस और एआईयूडीएफ सांसदों ने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में संसद भवन परिसर में मंगलवार को धरना दिया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। लोकसभा में सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें तृणमूल समेत कुछ दलों असहमति का नोट दिया था। मंगलवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले तृणमूल सांसदों एवं एआईयूडीएफ के बदरूद्दीन अजमल ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और नारेबाजी की। तृणमूल सांसदों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था मुझे मेरे देश से मत निकालो, मैं भारत का नागरिक हूं।

तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किए जाने के खिलाफ है। इसके कारण 30 लाख लोग प्रभावित होंगे। यह लोगों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। अन्नाद्रमुक सांसदों ने भी कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने के विरोध में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। वे अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और बांध बनाने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। वहीं, तेदेपा सांसद आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में मुख्य गेट के सामने नारेबाजी कर रहे थे। अन्नाद्रमुक और तेदेपा सांसद 11 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही अपनी मांग के समर्थन में सदन में नारेबाजी कर रहे हैं।

हंगामा करने और कामकाज में बाधा डालने के कारण स्पीकर अब तक 49 सांसदों को संसद के कामकाज की शेष अवधि के लिए निलंबित कर चुकी हैं।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

एजेंसी। नई दिल्ली

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने वाले कानून में संशोधन वाला एक विधेयक सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार को बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। विधेयक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन किया गया है।

विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़नों और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों पर नजर रखने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषांगिक विषयों के लिए इसे लाया गया है। इसमें कहा गया है कि विधेयक लिंग निरपेक्ष है और बालकों के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व से संबंधित है ताकि बालक के अच्छे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। उद्देश्यों में कहा गया है कि हाल ही में देश में अमानवीय मानसिकता दर्शाने वाले बाल यौन अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है, इसलिए उक्त अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि के नाते उपबंध करने के लिहाज से संशोधन प्रस्तावित हैं। उद्देश्यों के अनुसार इसमें केंद्र सरकार को बालक को किसी भी रूप में शामिल करने वाली अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट करने के संबंध में नियम बनाने के लिए भी सशक्त किया गया है।

क्विक न्यूज

माकपा, भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर फेंके गए बम

कोझिकोड (केरल)। केरल में सबरीमला मामले को लेकर लगातार जारी हिंसा के बीच कोझिकोड जिले में मंगलवार तड़के माकपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर देशी बम फेंके गए। पुलिस ने बताया कि कोयिलान्डी इलाके में पहला बम माकपा के समिति सदस्य शिजू के घर पर फेंका गया। इसके बाद भाजपा नेता वी के मुकुंदन के घर पर देशी बम फेंका गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कोयिलान्डी में सोमवार को भी एक भाजपा कार्यकर्ता के घर पर देशी बम फेंका गया था। वहीं कन्नूर से 18 देशी बम बरामद किए गए थे।

श्रीलंकाई नौसेना ने चार मछुआरों को गिरफ्तार किया

रामेश्वरम (तमिलनाडु)। श्रीलंकाई नौसेना ने मंगलवार सुबह तमिलनाडु के चार मछुआरों को नेदुंतीवु तट से कुछ दूर उसके जल-क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मत्स्य पालन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक कुमारेसन ने कहा कि पुदुकोट्टई जिले के कोट्टईपट्टिनम के रहने वाले ए मछुआरे कल रात समुद्र में गए थे और नेदुंतीवु से कुछ दूर मछली पकड़ रहे थे, जहां श्रीलंकाई नौसेना के कर्मी आए और उन्हें पकड़कर अपने देश के कराईनगर ले गए। इस घटना के एक दिन पहले ही उसी जिले के चार मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने अपनी समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के लिए गिरफ्तार किया था।

ठाणे में फर्जी चिकित्सक गिरफ्तार

ठाणे (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति को चिकित्सा परिषद में आवश्यक पंजीकरण के बिना चिकित्सक के तौर पर सेवाएं देने और उस दौरान एक मरीज की मौत होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपनिरीक्षक योगेश गायकर ने बताया कि 49 वर्षीय प्रवेश शर्मा ने उल्हासनगर में अपने निजी क्लीनिक में 17 वर्षीय एक लड़की का उपचार किया था। लड़की के पेट में दर्द था। उन्होंने बताया कि लड़की की हालत गंभीर हो गई और उसे एक अन्य अस्पताल में ले जाया गया।

मत्स्य मामले के लिए अलग मंत्रालय पर फिलहाल विचार नहीं

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि मत्स्य मामलों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान माकपा के ए. संपत के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने सवाल किया कि क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अलग मत्स्य मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? इसके जवाब मंत्री ने कहा, मंत्रालय अलग करने के संदर्भ में अभी कोई विचार नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण भारत के मत्स्य संगठन और राजनीतिक दल भी मत्स्य मामलों के लिए अलग मंत्रालय की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। रामचंद्र हांसदा और एनके प्रेमचंद्रन के पूरक प्रश्नों के उत्तर में सिंह ने कहा कि 2014 में कुल 55 विदेशी नौकाएं भारतीय जलक्षेत्र में जब्त की गई थीं।

बस हड़ताल से ऑफिस जाने वालों को हुई दिक्कत, सरकार ने मेस्मा लगाया

एजेंसी। मुंबई

मुंबई के परिवहन विभाग के 32 हजार से अधिक कर्मचारी वेतन बढोत्तरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके बाद, राज्य सरकार ने उनके खिलाफ महाराष्ट्र आवश्यक सेवा बहाली कानून (मेस्मा) लगाया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात (बेस्ट) के कर्मचारियों की हड़ताल संयोग से ऐसे दिन है जब श्रम संगठनों ने सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों तथा एकपक्षीय श्रम सुधार के विरोध में दो दिवसीय राष्ट्रस्तरीय हड़ताल आहूत की है।

हड़ताल से करीब 25 लाख दैनिक यात्रियों के प्रभावित होने के बाद राज्य सरकार ने मेस्मा कानून लगाया। कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि ऑटोरिक्शा चालक स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और सामान्य दरों से पांच गुना तक पैसे ले रहे हैं। बृहन्मुंबई महानगर आयुक्त अजय मेहता और हड़ताल बुलाने वाले श्रम संगठन के नेताओं के बीच बैठक में कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला। एक वरिष्ठ प्रशासनक अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, हड़ताल अवैध है और लाखों यात्रियों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए आंदोलनरत कर्मचारियों से देरी किए बिना काम पर लौटने को कहा गया है। उन्हें (कर्मचारी) समझना चाहिए कि सरकार ने मेस्मा लगाया है। उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रशासन के शीर्ष अधिकारी गतिरोध खत्म करने के लिए श्रम संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने चेताया, इसके बाद, बेस्ट प्रशासन के लिए कार्रवाई करने के रास्ते खुल जाएंगे। बेस्ट के कर्मियों के यूनियन नेता शशांक राव ने कहा कि चूंकि मेहता के साथ उनकी बैठक में कोई सकारात्मक हल नहीं निकला, उनकी हड़ताल जारी है।

एआइएडीएमके के सदस्यों ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कावेरी नदी पर नए बांधों के निर्माण के खिलाफ मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदर्शन किया।

गरीबों को आरक्षण संबंधी विधेयक संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए: पासवान

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने के सरकार के कदम का स्वागत करते हुए मंगलवार को कहा कि विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए ताकि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए। पासवान ने लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इससे पहले एससी-एसटी कानून को लेकर दलित समाज की शंकाओं का समाधान किया, ओबीसी आयोग बनाया, पदोन्नति में आरक्षण लागू किया और अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया कि इन सारे कदमों के कारण मोदी सरकार फिर से सत्ता में आएगी।

पासवान ने कहा कि अगर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण का हक मिल जाए और पिछड़े वर्ग को कोई नुकसान नहीं हो तो इस कदम को लेकर लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य के नाते मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे और आरक्षण से जुड़े सभी प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इन्हें अदालत में नहीं ले जाया जा सके।

पासवान ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। उन्होंने भारतीय न्यायिक सेवा की शुरूआत करने की भी मांग करते हुए कहा कि इससे न्यायिक क्षेत्र में भी सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मीडिया में एक साक्षात्कार में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद देखेंगे, प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की भी मांग की।

केंद्र ने 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ एक विनाशकारी खेल शुरू किया है : द्रमुक

चेन्नई। द्रमुक ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्गों और अन्य लोगों के साथ एक विनाशकारी खेल शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत के आरक्षण को मंजूरी दे दी। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण देने का यह कदम उठाया गया है और राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक से तमिलनाडु विधानसभा में इस मामले पर केंद्र के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की मांग की। विस में विपक्ष के नेता स्टालिन ने मंगलवार को सदन के पटल पर इस मुद्दे को उठाया और तमिलनाडु में दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की ओर से किए गए 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के बारे में सरकार को याद दिलाया।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करते हुए कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर

सवर्ण आरक्षण जाति के आधार पर बांटने की कोशिश: माकपा

नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के निर्णय को माकपा ने चुनावी लाभ के लिए किया गया फैसला बताते हुए मोदी सरकार पर समाज को धार्मिक आधार पर बांटने के बाद अब जातिगत आधार पर बांटने का आरोप लगाया। लोकसभा में माकपा के नेता मोहम्मद सलीम और पार्टी के महासचिव सीताराम एचुरी ने मंगलवार को कहा कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने के बाद सरकार अब सवर्णों को आरक्षण देने की आड़ में जाति के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण करना चाहती है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस फैसले को लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सलीम ने कहा कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी विधाई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कार्यसूची में न तो संविधान संशोधन को सूचीबद्ध किया गया और ना ही सदस्यों को विधेयक की प्रति मुहैया कराई गई।

उन्होंने कहा कि मंगलवार को भोजनावकाश से पहले जारी होने वाली संशोधित कार्यसूची में विधेयक को शामिल करने से साफ है कि सरकार बिना सर्वानुमति कायम किए, इसे सदन से पारित कराना चाहती है। इस दौरान एचुरी ने आरक्षण को महज चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि आरक्षण के दायरे में जब तक निजी क्षेत्र को नहीं लाया जाएगा, तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि माकपा मंडल आयोग के समय से ही आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करती रही है।

21वीं सदी के आंबेडकर है मोदी : त्रिवेंद्र रावत

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर से की। रावत ने कहा कि केन्द्र के दस प्रतिशत आरक्षण के फैसले से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए रावत ने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के आंबेडकर हैं। वह खुद गरीब माता पिता के बेटे हैं और उन्होंने समाज के सभी वर्गों के गरीबों के बारे में सोचा। देशभर में लंबे वक्त से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही थी। उन्हें इस फैसले से बहुत लाभ होने जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़े फैसले में, केन्द्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी।

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उत्थान के लिए बजट आवंटन में भारी वृद्धि

एजेंसी। नई दिल्ली

सरकार ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक उत्थान के लिए बजट आवंटन 2014-15 से 2018-19 की अवधि में बढ़ कर 11,833.35 करोड़ रुपए हो गया है जो 2009-2010 से 2013-14 के दौरान 7017.66 करोड़ रुपए था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा को अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक उत्थान के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की जानकारी देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक बालिकाओं को 50 फीसदी से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि कई राज्यों के लिए शैक्षिक अवसंरचना से संबंधित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं भी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-2010 से 2013-2014 के बीच 1889 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं लेकिन 2014-12015 से 2018-2019 के दौरान कुल 3470 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश में 33.66 करोड़ खाते

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 33.66 करोड़ खाते हैं जिनमें 86,321 करोड़ रुपए की राशि जमा है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राज्यसभा को बताया कि पिछले साल 26 दिसंबर की स्थिति के मुताबिक पीएमजेडीवाई के तहत मौजूद कुल 33.66 करोड़ खातों में से 19.92 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में हैं तथा 17.84 करोड़ खाते (करीब 53 प्रतिशत) महिलाओं द्वारा खोले गए हैं।

अगस्त्यार्कूदम चोटी पर महिलाओं को चढ़ाई की अनुमति देने से नाखुश हैं केरल के आदिवासी

एजेंसी। तिरुवनंतपुरम

केरल की दूसरी सबसे ऊंची मनोरम दृश्यों वाली चोटी अगस्त्यार्कूदम की ओर जाने वाला दुर्गम मार्ग पहली बार महिलाओं के लिए खुलने के लिए तैयार है जिससे कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज हैं। नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य के दुर्गम जंगलों में स्थित 1,868 मीटर ऊंची चोटी पर महिलाओं के चढ़ाई करने पर लगी रोक हटाने के राज्य सरकार के फैसले की खबर उनके लिए राहत भरी रही। महिलाएं भी मनोरम दृश्य वाली इस पहाड़ी स्थल का आनंद उठा सकेंगी।

गिरिपीठ में रहने वाली कानी जनजाति के अनुसार यह पर्वत उनके देवता अगस्त्य मुनि का निवास स्थान है जो यहां रहने वाले लोगों के संरक्षक माने जाते हैं और महिलाओं को पारंपरिक रूप से इस चोटी पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी। चोटी पर ही अगस्त्य मुनि की प्रतिमा स्थापित है। जनजातीय महिलाएं चिरकाल से इस पाबंदी का पालन करती रही हैं और वे चोटी से करीब छह किमी दूर स्थित आधार शिविर आथिरामाला से आगे नहीं जाती थीं। उनकी यह भी आशंकाएं है कि ट्रेकर्स की संख्या बढ़ने से उनके पूजा का पवित्र स्थल प्रदूषित होगा जो पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। ट्रेकर्स के लिए यह स्थान स्वर्ग माना जाता है। इसके अलावा यह उन हिंदू श्रद्धालुओं के लिए प्रतिष्ठित तीर्थस्थल है जो मानते हैं कि पुराणों के सात ऋषियों में से एक माने जाने वाले अगस्त्य मुनि ने इस पर्वत की चोटी पर ही ध्यान लगाया था। आदिवासी महासभा के राज्य अध्यक्ष मोहनन त्रिवेणी ने पीटीआई-भाषा से कहा, हम महिला ट्रेकर्स को अनुमति देने वाले वन विभाग के फैसले से बहुत दुखी और हताश हैं।

उन्होंने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कमजोर और हाशिए पर पड़े लोग हैं। हमारे पास उनके फैसले के खिलाफ लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने की शक्ति नहीं है। पूरा समुदाय दुखी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और ट्रेकर्स के लिए यह रोमांचक स्थल है लेकिन हमारे लिए यह हमारी जिंदगी और आस्था है। अगस्त्यर्कूदम मंदिर कानीक्कर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहनन ने कहा, यह वाकई बहुत दुर्गम इलाका है। हमें डर है कि अत्यधिक ट्रेकर्स के आने से वहां प्लास्टिक कचरा और शराब की बोतलें एकत्रित हो जाएगी जबकि ये वस्तुएं वहां प्रतिबंधित हैं। इससे पूरा जैव विविधता तंत्र बर्बाद हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम से करीब 70 किमी दूर अगत्स्यर्कूदम की गिरिपीठ पर करीब 2,000 कानीक्कर आदिवासी रह रहे हैं। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि ट्रेकिंग का मौसम 14 जनवरी से शुरू होगा और एक मार्च तक चलेगा तथा हर दिन केवल 100 ट्रेकरों को ही अनुमति दी जाएगी।

पेज एक का शेष

बंधे हाथ...

पद पर बहाल होने के उपरांत समिति से ऐसी कार्रवाई या निर्णय लेने की अनुमति मिलने तक कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला लेने से परहेज करेंगे। इस अंतरिम अवधि के दौरान और इस आदेश के अनुसार, सीबीआई निदेशक के रूप में आलोक कुमार वर्मा कोई नई पहल जिसका कोई बड़ा नीतिगत या संस्थागत प्रभाव हो, के बगैर ही खुद को रोजमर्रा के काम तक सीमित रखेंगे। यह फैसला प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने लिखा है किंतु, आज वह उपस्थित नहीं थे इसलिए न्यायमूर्ति कौल ने यह निर्णय सुनाया।

आलोक वर्मा को उच्चाधिकार प्राप्त प्रवर समिति के फैसले के आधार पर 19 जनवरी 2017 को दो साल के लिए सीबीआई निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। सीबीआई निदेशक पद पर आलोक वर्मा का दो वर्ष का कार्यकाल आगामी 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। वर्मा ने सरकार की ओर से खुद को जबरन छुट्टी पर भेजने और एक अंतरिम प्रमुख नियुक्त करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि सीबीआई प्रमुख का कार्यकाल दो साल का होता है और उन्हें उच्चाधिकार प्राप्त प्रवर समिति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

यह पूरा मामला सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के साथ आलोक वर्मा के विवाद के इर्दगिर्द सिमटा हुआ है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने एक-दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वर्मा ने उन्हें निदेशक के अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन अस्थाना ने शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मांगी। भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच ब्यूरो द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कराने के लिए वे दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे थे।

पीठ ने अपने फैसले में विनीत नारायण प्रकरण में दी गई अपनी व्यवस्था और इसके बाद कानून में किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि विधायिका की मंशा सीबीआई निदेशक के कार्यालय को हर तरह के बाहरी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने और संस्था के रूप में सीबीआई प्रतिष्ठा और निष्पक्षता बरकरार रखने की रही है। शीर्ष अदालत द्वारा 1997 में विनीत नारायण प्रकरण में सुनाया गया फैसला देश में उच्च पदों पर आसीन लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से संबंधित था। पीठ ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के एक प्रावधान का भी जिक्र किया जिसके अनुसार, प्रवर समिति की सहमति के बगैर सीबीआई निदेशक का तबादला नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि विधायिका की मंशा इस तरह की स्थिति में सीबीआई निदेशक के खिलाफ सरकार को अंतरिम उपाय करने के लिए कोई अधिकार देने की नहीं थी। यदि तबादला शब्द को सामान्य बोलचाल के नजरिए से समझा जाए और इसे एक पद से दूसरे पद पर भेजने तक सीमित रखा जाए तो इस तरह समिति से पहले सहमति लेने की अनिवार्यता का प्रावधान विधायिका की ऐसी मंशा को निष्फल करता है। कोर्ट के अनुसार, यही कल्पना की गई है कि सीबीआई जैसी संस्था को हर तरह के बाहरी प्रभाव से दूर रखना जरूरी है ताकि वह जनहित में बगैर किसी भय और पक्षपात के प्रमुख जांच एजेंसी और अभियोजन एजेंसी की अपनी भूमिका निभा सके। न्यायालय ने कहा कि संस्थान के मुखिया या निदेशक को अपने आप में स्वतंत्रता और निष्ठा की मिसाल होना चाहिए जो उसे संसद की अपेक्षाओं के अनुरूप हर तरह के नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त रखना सुनिश्चित कर सके। सभी प्राधिकारियों को जांच ब्यूरो के निदेशक के कामकाज में हस्तक्षेप करने से दूर रहना चाहिए।

सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पड़ने जैसी स्थिति के बारे में पीठ ने कहा कि ऐसी आवश्यकता की पृष्ठभूमि में जनहित प्रमुख होना चाहिए और इस तरह की आवश्यकता को सिर्फ समिति की राय से ही परखा जा सकता है। संबंधित कानून में जांच ब्यूरो के निदेशक के अंतरिम निलंबन या पद से हटाने का प्रावधान नहीं है और ऐसा कोई भी निर्णय उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सहमति के बाद ही लिया जा सकता है।

सरकार की...

विश्वसनीयता और निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित जांच के व्यापक हित को देखते हुए इन अधिकारियों को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने के लिए मामले को प्रवर समिति के पास भेज दिया है।

जेटली ने कहा कि सीबीआई की निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित कार्यशैली के व्यापक हित को देखते हुए न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सीबीआई निदेशक को मिली सुरक्षा को मजबूत किया है। साथ ही जवाबदेही की व्यवस्था का रास्ता भी निकाला है। न्यायालय के निर्देशों का निश्चित तौर पर अनुपालन होगा। जेटली ने इस बात पर भी जोर दिया कि मामले पर सरकार का फैसला किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था। सरकार ने सीवीसी अनुशंसाओं को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया था। उच्चतम न्यायालय ने मामले की आज फिर से नई व्याख्या की है। सरकार उसके आदेश के अनुरूप ही कार्रवाई करेगी।

राफेल से...

वह (प्रधानमंत्री) इस मामले की जांच से भाग नहीं सकते। यह असंभव है। उधर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि वह (मोदी) सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया। अब वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है। लोस में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, कल कोई और ऐसा करेगा। ऐसे में लोकतंत्र का क्या होगा?

वहीं माकपा महासचिव सीताराम एचुरी ने कहा कि अदालत के फैसले से साबित होता है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने इस फैसले को सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह आदेश इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को सीधे दोषी ठहराता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और सलाह दी है कि केंद्र सरकार को अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए।

गरीबों को...

सदन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद दें। गहलोत ने कहा कि पूरे विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया है। हम देर से लाए, लेकिन अच्छी नीयत से लाए। इसलिए आशंका करने की जरूरत नहीं है। गहलोत ने कहा कि यह विधेयक अमीरी और गरीबी की खाई को कम करेगा। इससे लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। इससे सबको फायदा होगा चाहे वह किसी वर्ग या धर्म के हों। उन्होंने विधेयक को नरेन्द्र मोदी सरकार के लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास की दिशा में अहम कदम करार दिया। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने 3 के मुकाबले 323 मतों से विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने के बावजूद न्यायिक समीक्षा में इसके टिक पाने की आशंका जताई गई और पूर्व में पीवी नरसिंह राव सरकार द्वारा इस संबंध में लाए गए कदम की मिसाल दी गई। कई विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार इस विधेयक को लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लाई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधेयक में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए इस संबंध में विपक्ष के आरोपों को निर्मूल करार देते हुए कहा कि यह न्यायिक समीक्षा में इसलिए टिकेगा क्योंकि इस विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल प्रस्तावना में सभी नागरिकों के विकास के लिए समान अवसर देने की बात कही गई है और यह विधेयक उसी लक्ष्य को पूरा करता है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने अपने घोषणापत्र में इस संबंध में वादा किया था कि अनारक्षित वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों को शिकवा-शिकायत छोड़कर बड़े दिल के साथ इस विधेयक का समर्थन करने को कहा। कांग्रेस नेता के वी थामस ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी में लाने की कवायद करार दिया और कहा कि इसमें कानूनी त्रुटियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी विधेयक की अवधारणा का समर्थन करती है। केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए ताकि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए।

एचआरडी मंत्रालय...

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2017-18 के अनुसार, देश में कुल 903 विश्वविद्यालय, 39000 से अधिक कॉलेज और 10,000 से अधिक संस्थान हैं। यह प्रस्तावित आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राप्त 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा और इससे कुल आरक्षण 60 फीसदी हो जाएगा। बिल में इस आरक्षण को पाने के लिए सालाना आय आठ लाख से कम तथा पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न होने जैसी श्रेणियां शामिल की जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह के अंत में परीक्षा और उससे जुड़े दबावों पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे, जैसा कि पिछले साल उन्होंने किया था। इस संवाद सत्र में न केवल पूरे देश से बल्कि विदेश से भी लोग वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भाग ले सकेंगे।

देशभर में...

हड़ताल के दिन ही शुरू हुई। इससे करीब 25 लाख दैनिक यात्री प्रभावित हुए। इस बीच, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हड़ताल पर जाते हैं और काम पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दो प्रमुख बैंक यूनियनों आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) तथा बैंक एम्पलाइज फेडरेशन आफ इंडिया (बीईएफआई) ने हड़ताल का समर्थन किया है। हड़ताल से उन बैंकों का परिचालन प्रभावित हुआ है जहां इन दोनों यूनियनों का ज्यादा प्रभाव है। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की सात अन्य यूनियनें हड़ताल में भाग नहीं ले रही हैं।

दो देशों...

दो देशों के प्रधानमंत्रियों के संगम स्नान के मद्देनजर सरकार के स्तर पर तैयारियों पर विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं। कुंभ में कुल 192 देशों को आमंत्रण भेजा गया है। जिसमें 71 देशों के आने की सहमति आ चुकी है और इन देशों के राजनयिक प्रयागराज में आकर कुंभ की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। इसके अलावा अन्य आमंत्रण स्वीकारे जाने की अन्य देशों की स्वीकृतियां आ रही हैं।

नागरिकता विधेयक...

पंजी (एनआरसी) का जिक्र करते हुए कहा कि इसे उचित ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत शिकायत करने का प्रावधान किया गया है। हम प्रक्रिया पूरी करने को प्रतिबद्ध हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सिंह ने कहा कि 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन नहीं होता तो अच्छा होता। अखंड भारत रहता। विडंबना रही कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। भारत, पाकिस्तान सबको इस बात की चिंता थी कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की तत्कालीन सरकारों के बीच समझौतों के बावजूद पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अधिकार नहीं मिल पाए। सिंह ने कुछ सदस्यों के सवालों पर कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। उन्हें दीर्घकालीन वीजा दिया जा सकता है। भारत में पाकिस्तान के लोगों को न केवल दीर्घकालीन वीजा देने के उदारहण हैं, बल्कि नागरिकता भी दी गई। उन्होंने कहा, धार्मिक आधार पर नागरिकता के आरोप निराधार हैं। बड़ी संख्या में बहुसंख्यक लोगों को भी भारत में नागरिकता मिलती रही है। सिंह ने नागरिकता दिए जाने के समर्थन में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन नेता सुचेता कृपलानी के बयानों को भी उद्धृत किया। सिंह ने कहा कि भारत का जो भी मूल निवासी है भले ही वह ईसाई रहा हो अगर उसका पाकिस्तान आदि देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बोडो समुदाय की मांगों के बारे में न केवल चिंता करती है बल्कि इसके लिए प्रतिबद्ध भी है।

वर्मा-अस्थाना के झगड़े से सीबीआई की छवि को पहुंचा काफी नुकसान

एजेंसी। नई दिल्ली

सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच अभूतपूर्व झगड़े से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। दोनों के बीच झगड़ा पिछले साल तब शुरू हुआ था जब वर्मा ने कुछ अधिकारियों को एजेंसी में शामिल करने की सिफारिश की जबकि अस्थाना ने इस पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त वर्मा ने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को एजेंसी में शामिल करने की सिफारिश की थी लेकिन 1984 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी अस्थाना ने इस पर आपत्ति जताई।

वर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई मामले देखे जिनमें से कम से कम आधा दर्जन मामलों में अस्थाना की कथित भूमिका थी। उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग की बैठक में भी इन मामलों को उठाया। आयोग को अस्थाना की पदोन्नति पर फैसला लेना था। उन्हें विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त कर एजेंसी में नंबर दो का दर्जा दिया जाना था। इन मामलों में गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक से अस्थाना समेत कई अधिकारियों को कथित रुपए देने की जानकारियां शामिल हैं। बैंक डिफॉल्ट के मामलों का सामना कर रही कंपनी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी के दौरान बरामद एक डायरी से ये जानकारियां मिली। इसके प्रोमोटर्स अब भी फरार हैं। आयोग ने इस पर संज्ञान लिया लेकिन सर्वसम्मति से अस्थाना को विशेष निदेशक के पद पर पदोन्नति दे दी गत वर्ष जुलाई में सीवीसी ने कई अधिकारियों की पदोन्नति पर फैसला लेने के लिए अस्थाना को बुलाया था क्योंकि वर्मा देश से बाहर थे लेकिन सीबीआई निदेशक ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उनकी गैरमौजूदगी में अस्थाना उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

इस बीच, विजय माल्या बैंक धोखाधड़ी मामला, अगस्ता वेस्टलैंड घूसखोरी कांड, पूर्व सीबीआई निदेशक से जुड़े मोइन कुरैशी रिश्वत मामले जैसे संवेदनशील मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे अस्थाना ने जुलाई में सरकार का रुख कर आरोप लगाया कि एक आरोपी सतीश बाबू सना की मदद करने के लिए वर्मा को दो करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। सना मोइन कुरैशी से जुड़े रिश्वत मामले में जांच के घेरे में है। अक्टूबर में सना ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अपने बयान में उसने आरोप लगाया कि दुबई में दो कारोबारी बंधुओं ने उसकी मदद के बदले में पांच करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश दी थी। उसने दावा किया कि दोनों भाई अस्थाना को जानते थे और अस्थाना ने दोनों बंधुओं को भुगतान की जानकारियां भी दी। निगरानी के दौरान सीबीआई ने व्हाट्सएप संदेशों, फोन इंटरसेप्ट और बैठकों की जानकारियां का खुलासा किया जिससे कथित तौर पर यह संकेत मिलता है कि अस्थाना इसमें शामिल थे।

आस्ट्रेलिया में विजय

बदलेगा भारतीय खेल का भविष्य

स्वतंत्रता के बाद क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए शानदार अवसर था कि सिडनी में बरसात के कारण अंतिम टेस्ट मैच अनिर्णीत समाप्त हुआ। इससे कोहली के नेतृत्व में नौजवानों को 2-0 से सीरीज़ में विजय मिली जो पिछले 71 वर्षों में मिली किसी अन्य विजय के समान नहीं है। हालांकि, इसे ऐतिहासिक या उल्लेखनीय कहा जा सकता है, पर तथ्य यह है कि पर्थ जैसे ग्राउंड पर मिली विजय एक बड़ी उपलब्धि से भी अधिक है। हालांकि, कुछ लोग तर्क दे सकते हैं स्टीव स्मिथ व डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों के टैंपरिंग प्रकरणों में क्रिकेट से बाहर हो जाने के कारण आस्ट्रेलिया टीम कमजोर हो गई थी। लेकिन प्रतियोगिता के क्षेत्र में ऐसे किन्तु परन्तु वाले तर्कों का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही भारत की अपनी टीम भी बहुत युवा, तुलनात्मक रूप से अनुभवहीन तथा विदेशों में अपने प्रति अविश्वास की पुरानी सोच से ग्रस्त थी। हालांकि, इसमें ऋषभ पंत जैसे उभरते नायक थे जिन्होंने सिडनी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 रन बनाए थे। इसमें टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा थे जिन्होंने तीन सेंचुरी बनाईं। इसके साथ ही जसप्रीत बूमरा के सीरीज़ में लिए 21 विकेटों ने कुलदीप की स्पिन की तरह विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्किपर विराट कोहली ने ऐसे देश में विजय पताका फहराई जहां पहली बार 1947 में भारत ने लाला अमरनाथ के नेतृत्व में 4-0 से विजय पाई थी और डॉन ब्रेडमैन व उनकी अविजेय समझे वाली टीम को हराया था। इसकी तुलना

में टिम पेन काफी कमजोर व हतोत्साहित दिखे। कोहली की क्षमता न केवल स्किपर, बल्कि बेहतरीन टीम संचालक के रूप में सामने आई। वे एम.एस. धोनी के अच्छे व सक्षम वारिस सिद्ध हुए हैं जिन्होंने आधुनिक क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट के लिए सोच के नए आयाम खोले थे। कोहली को काफी प्रशंसा मिली है जिन्होंने एक वर्ष में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड व आस्ट्रेलिया में रिकार्ड चार टेस्ट विजय प्राप्त की हैं।

गावस्कर की लोकप्रिय सीरीज़ तक पहुंचने वाली क्रिकेट टीम की इस सफलता से भारतीय क्रिकेट को नए आयाम मिले हैं। बैटिंग, पेस बालिंग, स्पिन बालिंग व फील्डिंग आदि सभी शानदार भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट को नए अर्थ दिए हैं और कोहली व कोच रवि शास्त्री की सहायता से इतिहास बनाया है। वर्तमान विजय से भारत ने विश्व कप सीरीज़ में नया स्थान बनाया है। भारत ने आस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलिया को पहली बार हराया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण से अधिक भविष्य की संभावनायें खोलने वाली विजय है। यह उस युवा टीम के लिए बहुत अच्छी है जो क्रिकेट के सर्वाधिक सम्मानित व लंबे फार्मेट में विजय के प्रति आश्वस्त नहीं थी। इसमें ऐसा साहस, आत्मविश्वास व दृढ़ता प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी जो दबाव में न झुकता तथा आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का आधार तैयार करता। सिडनी ने हमारे सामने जो परिदृश्य उपस्थित किया है उसमें लगता है कि हिमा दास, मानिका बत्रा व मैरी काम को आए बहुत लंबा समय नहीं बीता है। इस विजय से भारतीय खेलों को नई संभावनायें मिली हैं जिनके साथ भारतीय खेल टीमें टोकियो और लंदन जा सकती हैं।

कटुतापूर्ण होगा 2019 का चुनाव प्रचार

पिछले कुछ महीनों से संकेत मिल रहे हैं कि 2019 का आम चुनाव प्रचार कटुतापूर्ण हो सकता है। यह चुनाव प्रचार मैदान के साथ ही सोशल मीडिया और मैसेजिंग समूहों के माध्यम से भी किया जाएगा।

कुषाण मित्रा
(लेखक दि पायनियर के प्रबंध संपादक हैं)

सतही तौर से देखने पर पश्चिमी ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष एक मनमानी तारीख है। ऐतिहासिक रूप से इसका दुनिया की किसी संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। कहा जा सकता है कि मानव जाति द्वारा धरती पर आधा-अधूरा कैलेंडर थोपने से पहले शीत-संक्रान्ति नव वर्ष का पहला दिन होती थी और उस तिथि को दिन बड़ा होना शुरू हो जाता था। लेकिन धरती के परिभ्रमण तथा शताब्दियों तक कैलेंडर ठीक न कर पाने के कारण नव वर्ष की कोई स्पष्ट तिथि निश्चित नहीं हो सकी। यह समस्या चंद्र-चक्र पर आधारित पुराने कैलेंडरों से उलट थी जिनको बार-बार ठीक करना पड़ता था। लेकिन तिथियों के मनमानेपन के अलावा हम ऐसे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं जो भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इस वर्ष 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे।

भारतीय लोकतंत्र को काम करते देखना उल्लेखनीय है। चुनाव अत्यधिक सुसंगठित लाजिस्टिक कार्यक्रम है जिसमें अधिकारी, अर्धसैनिक बल, राजनेता और पत्रकार देश भर में सक्रिय होते हैं। यह भी अत्यन्त उल्लेखनीय है कि लगभग 50 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसे एकदम सही नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक शहरी का मत समान महत्व का नहीं होता है। दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों का प्रतिनिधित्व कम होता है तथा अल्पसंख्यकों व महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है। यह बात उम्मीदवारों व चयनित प्रतिनिधियों, दोनों के मामले में सही है। इसके साथ ही निरंतर राजनीतिक भ्रष्टाचार जारी है जहां मतदाताओं को सीधे-सीधे नकदी या शराब की रिश्वत देकर ललचाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी सीमा तक भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से बेदाग तथा वैश्विक मानकों की तरह है। वास्तव में, अमेरिका की समस्याओं से भरी चुनाव प्रणाली को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय व्यवस्था अत्यधिक स्वच्छ है। लेकिन इन सारी बातों के साथ ही एक चीज पहले ही लोगों को स्पष्ट है और यदि ऐसा नहीं भी है तो जल्द ही सबको स्पष्ट हो जाएगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव बहुत कटुतापूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें अधकचरी अफवाहें तथा भद्दे आरोप-प्रत्यारोप सभी जगहों से सामने आएंगे। इसका एक कारण यह है कि फिलहाल इस चुनाव में किसी एक नेता के खिलाफ कोई 'लहर' नहीं है।

इस चुनाव में नरेन्द्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष केवल इस कारण मैदान में उतरेगा क्योंकि वे सभी मोदी व भाजपा को अपना दुश्मन मानते हैं। यह चुनाव एक या दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत सुसंगत आर्थिक या रक्षा नीतियों पर नहीं लड़ा जाएगा। यह भारत की त्रासदी है। यह ऐसा चुनाव होगा जिसका विमर्श एक व्यक्ति की सफलता या अक्षमता पर केन्द्रित होगा और यह इतना विखंडित होगा जितनी विखंडित हमारी वर्तमान राजनीति है।

अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस चुनाव के बाद राजनीतिक स्थायित्व बढ़ेगा या नहीं। हालांकि, मोटेतौर से भारत उन अराजक स्थितियों से बचने में सफल रहा है जो 80 के दशकांत या 90 के दशकारंभ में व्याप्त थीं। लेकिन सबसे ज्यादा

इस चुनाव में नरेन्द्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष केवल इस कारण मैदान में उतरेगा क्योंकि वे सभी मोदी व भाजपा को अपना दुश्मन मानते हैं। यह चुनाव एक या दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत सुसंगत आर्थिक या रक्षा नीतियों पर नहीं लड़ा जाएगा। यह भारत की त्रासदी है।

चिन्ता की बात है कि आगामी चुनाव सोशल मीडिया पर पूर्णत: बेलगाम हो सकता है। मीडिया आमतौर से एक या दूसरे पक्ष का समर्थक बन गया है और इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने पत्रकार होने का दावा करते हैं। निश्चित रूप से हम में से बहुत से लोगों का एक राजनीतिक दृष्टिकोण है और वे देश को किसी खास दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे देश में राजनीति के प्रति एक मध्यमार्गी व तार्किक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। ऐसा अधिकांश लोकतंत्रों में हुआ है और उन्होंने हाशिए के निकट वाली चरमपंथी पार्टियों को धीरे-धीरे खारिज कर दिया है। परिस्थितियों में बदलाव का कारण अधिकांशत: बेलगाम सोशल मीडिया है। जैसी कि कहावत है कि यदि भानुमती का पिटारा एक बार खुल जाए तो आप उसे बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि, इस लेखक का विश्वास है कि नियंत्रण का एक तत्व होना चाहिए, पर यह तर्क उस समय तक नहीं दिया जा सकता है जब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही लगाम न लगाई जाए।

इसके साथ ही तुलनात्मक रूप से निष्पक्ष समझे जाने वाले इंटरनेट के कारण घृणापूर्ण अभिव्यक्ति का ऐसा स्तर पैदा हुआ है जो तार्किक सोच वाले किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से अतार्किक है। इस अभिव्यक्ति में महिलाओं को यौन धमकियां देना तक शामिल है। इसके साथ ही आनलाइन किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ घृणा व हिंसा भड़काने के प्रयास बेलगाम होते जा रहे हैं। 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की अवधारणा किसी व्यक्ति को धमकी देने का अधिकार नहीं हो सकती है। आशंका पैदा हो गई है कि अपनी पहुंच बढ़ाने के नाम पर इंटरनेट के मध्यस्थ ऐसी घृणा व हिंसा से भरी भाषा प्रचारित कर रहे हैं, हालांकि दुनिया भर के कानून स्पष्ट रूप से ऐसी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं।

भारत में जब कोई पत्रकार, पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा की तरह आनलाइन व्यंग्य करता है या मणिपुरी पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की तरह राजनेता की आलोचना करता है तो राज्य तेजी से उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आनलाइन हिंसा या बाल-यौन उत्पीड़न की खुलेआम पैरवी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के मामले में वह हिचकता है। इससे आशंका पैदा होती है कि क्या ऐसे तत्वों को उच्च स्तर से संरक्षण प्राप्त है।

भारत में घृणापूर्ण अभिव्यक्ति का प्रसार रोकने के लिए समुचित कानून और सुरक्षा उपाय हैं। लेकिन राजनीति में मध्यमार्गी धारा सूखने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव लोगों पर पड़ा है जो स्वयं एक-दूसरे के प्रति अत्यधिक क्रूर एवं असभ्य हो गए हैं। तथ्य यह है कि सोशल मीडिया साइटों की गणना ने ऐसे दृष्टिकोणों की धारा बहा दी है जो स्वयं अपने को ही पसंद करते हैं। इससे लोग आश्चर्यजनक रूप से कठोर हो गए हैं। यह 'माई वे आर द हाईवे' जैसा मामला हो गया है, यानी अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं तो भाड़ में जाएं। दूसरे की बात या दूसरा दृष्टिकोण सुनते समय अनेक लोग अत्यन्त कटु हो जाते हैं। वे यह सोच भी नहीं पाते हैं कि इससे उनको कोई लाभ हो सकता है।

निश्चित रूप से यह समस्या केवल भारत की नहीं है। यह समस्या दुनिया भर में सामने आ रही है। अनेक लोगों को मशीनों की संख्या बढ़ने से चिन्ता है जब रोबोट विनिर्माण और परिवहन क्षेत्रों पर नियंत्रण करेंगे। मशीनें काफी सीमा तक यह तय करने लगी हैं कि हमें कैसी सूचनायें मिल रही हैं और हम उनका प्रसंस्करण कैसे करते हैं। हमारे सामने यह गंभीर समस्या है और यदि हम इसके समाधान के लिए जल्दी से कोई कदम नहीं उठाते हैं तो यह दिन पर दिन और गंभीर होती जाएगी।

भयग्रसित अभिव्यक्तियों की कुटिल राजनीति

संजीव कुमार तिवारी
(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

अब एक और मुसलमान को इस देश में भय महसूस होने लगा है। भारत में अवने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचकर नसीरुद्दीन शाह को चिंता होती है। ऐसा ही कुछ उनके भाई और भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टीनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह द्वारा अपनी आत्मकथा, 'दि सरकारी मुसलमान' में व्यक्त किया गया है। जमीर शाह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक रोल आफ दि स्टेट गवर्नमेंट में लिखा है, पहले दंगा भड़काने और कारसेवकों से भरे रेलगाड़ी के डिब्बे को जलाए जाने के बाद भड़क उठे दंगों के निबटने के बारे में।

जमीर शाह को दंगा प्रभावित अहमदाबाद में सेना की टुकड़ियों की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा गया था। उनके बयानों में जो और भी ज्यादा अवमाननापूर्ण है वह यह कि दायित्व निर्वहन के समय तथा कई वर्षों तक खामोश रहकर, क्या यह दायित्व की शपथ से ज्यादा अपने व्यक्तिगत विचारों को महत्व देना नहीं है, जिसका कारण वही बेहतर जानते होंगे? कुछ समय पूर्व, आमिर खान ने भी भारत में असुरक्षित महसूस करने को लेकर ऐसा ही भय व्यक्त किया था। इन दोनों कलाकारों की अभिव्यक्तियां समान हैं, और समानताएं आगे भी नजर आती हैं। दोनों की पत्नियां हिन्दू हैं, अब या तो उनके निजी जीवन के बारे में मेरी जानकारी के अभाव के कारण, अथवा उनके निजी जीवन में दखल देने से परहेज करने के कारण, मुझे इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि उनके बच्चे मंदिर जाते हैं या मस्जिद अथवा इन चीजों की परवाह नहीं करती और इंसान ही बने रहना चाहते हैं, जिस विषय को फिल्म पीके में काफी प्रभावशाली ढंग से फिल्माया गया है जो मनोरंजन में लिपटा हुआ विशुद्ध सामाजिक संदेश है।

शाह और खान दोनों ही गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आए थे लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में फलने-फूलने के लिए हिन्दू अथवा इहलौकिक नामों का सहारा नहीं लेना पड़ा। नसीरुद्दीन शाह की पत्नी रत्ना पाठक शाह ने भी उद्योग में अपना महत्व बनाए रखा है जो पहले से था जब वो शाह उपनाम नहीं लगाती थीं। वे एक ऐसे उद्योग का हिस्सा हैं जिसमें मुसलमानों की अच्छी खासी मौजूदगी है, परदे पर और परदे के पीछे वे अपनी फिल्मों की सफलताओं से जाने जाते हैं अपने मजहब से नहीं।

इन दोनों अभिनेताओं ने सिलसिलेवार फिल्में दी हैं जो बाक्स आफिस पर हिट रही हैं और जिन्होंने काफी पैसा कमाने में सफलता प्राप्त की है, जो कदापि संभव न होता यदि हिन्दू दर्शकों में उनके प्रति कोई तिरस्कार भाव होता। उन्हें सच्चे कलाकार

माना गया और लोगों ने उन्हें हिन्दू अथवा मुसलमान के तौर पर कभी नहीं देखा। दोनों को ही पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साथ में आमिर को मानद उपाधि समेत अन्य कई सम्मान दिए गए हैं। आगे और भी समानताएं हैं, दोनों शहर के आलीशान घरों में रहते हैं और आमतौर से सुरक्षा कारणों के चलते समाज से अलग-थलग रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे दुख होता है ऐसे बयान सुनकर जो सेलेब्रिटीज की ओर से आते हैं अथवा उन लोगों की ओर से जिनका सार्वजनिक जीवन में उच्च स्थान है। जब तक हिन्दू नदीम-श्रवण की धुनों पर नाच रहे थे तब तक कुछ गलत नहीं था, भारत में मुसलमानों के प्रति खतरा तब उन्हें लगने लगा जब उन्हें यहां पर दर्ज एक आपराधिक मामले में यूके से प्रत्यर्पण कराने से बचना था। ऐसी प्रतिक्रियाएं देना, खासकर कोई सार्वजनिक प्रस्थिति छोड़ने के बाद अथवा अपने क्षेत्रों में प्रमुख स्थान पर रहने के बाद, असलियत में सुरक्षा कारणों से नहीं बल्कि कुटिलता व द्वेषपूर्ण भावना का परिचायक है। उन्होंने अपनी ही उसी जनता द्वारा पलकों पर बिठाए जाने के बल पर अपने सपनों को उड़ान दी है और अब ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो जब सोशल मीडिया और टेलीविजन बहसों में आती हैं तो विनाशकारी आवेग पैदा होता है। यह आवेग ही भयानक होता है, वे छुटपुट घटनाएं नहीं, जो दुर्भाग्य से मगर यथार्थरूप में, कोई भी समाज इससे मुक्त नहीं है।

स्वयं तथा अपने बच्चों के लिए किसी यूटोपियन समाज की खोज करने से पहले, उन्हें इस धरती पर उपलब्ध स्थानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुंह खोलने से पहले, उन्होंने अपने इर्द-गिर्द देखने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने उन अफ्रीकी देशों के बारे में नहीं सुना है जहां भ्रष्ट हुकूमतें चलाने के लिए शासक जनता की आवाज को दबा देते हैं और जवाबदेही के भय के बगैर प्रतिद्वंद्वी नृजातीय जनजातीय समूहों के नरसंहर का आदेश जारी कर देते हैं। लाखों की संख्या में लोग अकारण मारे गए हैं।

जब हमारे देश के संभ्रांतजन खतरों के बारे में बोलते हैं, तो वे ऐसा इसलिए करने में सक्षम हैं क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि लाखों वंचितों की तुलना में हमारे देश में उन्हें ऐसा बोलने का अधिकार है। वे आंतरिक तथा वाह्य क्षेत्रों में विस्थापित लाखों लोगों को अनदेखा करते हैं जिनकी पीढ़ियां अंतत: शरणार्थी शिविरों अथवा उनके बोझ से डूब जाने वाली नौकाओं में नजर आती हैं। ये शरणार्थी यूरोप में बढ़ती अति-दक्षिणपंथी पार्टियों का कारण हैं, और पहले से ही, वे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हैं। वे भूल जाते हैं कि इस देश में सामूहिक रूप से विस्थापित लोग केवल कश्मीरी पंडित हैं, जिन्हें बाहर खदेड़ दिया गया उस राज्य से जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। यदि उनकी निगाह में यूरोप अथवा अमेरिका हैं, तो यदि वहां प्रवास करने की अनुमति दे दी जाए, तो वहां भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उन्हें समाज में अनियंत्रित हिंसा की खबरों पर नजर डालनी चाहिए, चाहे वह रंग आधारित हो अथवा किसी विद्यालय परिसर में उन्माद में डूबकर की गई गोलीबारी और अमेरिका में श्वेत पुलिसवालों द्वारा अश्वेत अमेरिकियों के साथ भेदभाव किया जाना सर्वज्ञात है।

यद्यपि हमें हमारे बीच होने वाली हिंसा की छुटपुट घटनाओं से इनकार नहीं करना चाहिए लेकिन वे कानून-व्यवस्था के मुद्दे हैं नियाजित हत्याएं नहीं। ऐसी घटनाओं की समाज में बारंबार निंदा की गई है और यदि दोषी बचकर भाग निकले, तो ऐसा विधि के शासन के कारण होता है किसी साजिश के तहत नहीं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भारतीय सेना पृथक होकर काम करती है और आतंकियों के संरक्षण की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। हमें शांति तथा अहिंसा का पालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हमारा ध्येय रहे - सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। शाह और खान ऐसा बोलते हैं बावजूद इसके कि यह देश अपने चारों ओर फैली अशांति के बीच शांति और सद्भाव का मरुद्यान बना हुआ है। ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, जो पूर्णत: कायम है।

आप की बात

जवाबदेही का अभाव

एमपीलैड्स के अंतर्गत सांसदों को प्रति वर्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में पैसा लगाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं जिनका खर्च संसद द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन अनेक सांसदों द्वारा मानकों का उल्लंघन होने के कारण यह योजना शुरुआत से ही विवादों में घिरी रही है। लेकिन इस विचार के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करने के कारण सरकार को हर वर्ष इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,000 करोड़ रुपये का आबंटन करना होता है। यह धनराशि जिला कलेक्टरों को भेज दी जाती है जो सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पर अनेक सरकारी संस्थानों ने नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। अब केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां की हैं। लेकिन इस योजना पर विभिन्न क्षेत्रों से आ रही कठोर टिप्पणियों के बावजूद संसद द्वारा इस योजना में धन के दुरुपयोग तथा विसंगतियां दूर करने के कोई स्पष्ट प्रयास नहीं दिख रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति ही ईमानदार साबित नहीं होते।

- **अमित वर्मा,** सीतापुर

अनवरत चुनावी चक्र

लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होने के कारण देश में केंद्र के स्तर पर सरकार बनने के बाद भी पांच वर्ष तक चुनावी मौसम बना रहता है। कहीं एक तो कहीं दूसरे राज्य में चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में केंद्र में सत्तासीन सरकारों के नेताओं को अपने काम छोड़कर चुनाव प्रचार व राजनीतिक समीकरण बिठाने पर ध्यान देना पड़ता है। बार-बार चुनाव होने से न केवल मानव संसाधनों तथा सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है बल्कि देश के जिस भी हिस्से में चुनाव होते हैं वहां आचार संहिता लागू होने के कारण विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती है। प्रधानमंत्री, जिन्होंने एकसाथ चुनाव कराने की व्यवस्था की ओर वापस लौटने की वकालत की है, वह स्वतंत्र भारत में दो दशकों तक कायम रही थी, और प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की एक बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता दोहराई थी। कुछ राजनीतिक दल, स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा नागरिक समाज कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस कदम का विरोध किया है। क्योंकि उन्हें डर है कि संपूर्ण चुनाव मोदी के नाम पर होंगे और विपक्षियों को नुकसान होगा।

- **सुजीत कौशिक**, नोएडा

नकल व्यापार कब तक

बहुत से लोगों को याद होगा कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल की बढ़ती हुई समस्या को महसूस करके, 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह, ने एक नकल विरोधी अध्यादेश पारित कराया था, जिसके तहत नकल को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया था। कक्षा 10 और 12 के परिणाम गिरकर क्रमश: 13.7 प्रतिशत और 30.4 प्रतिशत पर आ गए थे। उनके राजनीतिक विरोधियों ने अवसर का लाभ उठाया, और घोषणा की कि यदि वे सत्ता में आए, तो एक घंटे के भीतर इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा। अंतत: वे सत्ता में आ गए और, वादे के मुताबिक, अध्यादेश को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अनैतिक किस्म के तत्वों ने कई दशकों से विभिन्न प्रांतों में भारत के युवाओं के साथ बर्बादी का नाटक खेला है। नकल करके पास होने वाले छात्र देश के तकनीकी व आर्थिक विकास में क्या योगदान दे पाएंगे। अत: शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए नकल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है चाहे स्वार्थी नेताओं द्वारा कितना भी विरोध क्यों न हो।

- **नमिता त्रिपाठी**, कानपुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

फरमाया

सीतारमण सिद्ध करें कि मोदी सरकार ने रक्षा पीएसयू एचएएल को एक लाख करोड़ के आर्डर दिए हैं या वे इस्तीफा दें।
- **राहुल गांधी**
कांग्रेस अध्यक्ष

हमें राहुल से नैतिक मूल्यों की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वे संसद में गरिमा बनाए रखेंगे।
- **स्मृति ईरानी**
केन्द्रीय मंत्री

इंदिरा गांधी को प्रतिभा दिखाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस में पुरुष नेताओं की तुलना में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी।
- **नितिन गडकरी**
केन्द्रीय मंत्री

पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की तीसरी बैठक सम्पन्न

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार असंगठित कर्मकारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें खुशहाल बनाने के लिए कल्याणकारी व बीमा योजनाओं से लाभान्वित करेगी। इसके लिए प्रदेश के 4.5 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीयन इसी माह से शुरू किया जाएगा और प्रतिमाह इसका 10 प्रतिशत अर्थात 45 लाख मजदूर श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। यह निर्देश श्रम सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री ने मंगलवार को विधान भवन स्थित तिलक हॉल में असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गठित 'उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' की तीसरी बैठक में दिए। इस मौके पर उन्होंने निर्देशित किया कि कर्मकारों की यथास्थिति जानने के लिए बोर्ड के सदस्यों को भी प्रदेश का दौरा करना होगा ताकि पंजीकरण कार्य को समय से पूरा किया जा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि असंगठित कर्मकारों का पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल पर स्वप्रमाणन के आधार पर किया जाए इसके लिए मजदूर से 50 रुपये लेकर उसका पंजीयन 5 वर्ष के लिए करें। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए असंगठित कर्मकारों की वार्षिक आय को 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दिया गया है तथा 2.5 एकड़ या इससे कम कृषि भूमिधर या कृषक श्रमिक को भी असंगठित कर्मकार ही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण संबंधी भारत सरकार की गाइडलाइन प्राप्त हो जाने के बाद शीघ्र ही इन श्रमिकों को लाभान्वित करने के कार्यों की शुरुआत की जाएगी तथा पंजीकृत मजदूरों को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर आश्रित को मिलेगा तथा विकलांग हो जाने पर एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि अटल पेंशन योजना के तहत ऐसे कर्मकारों को वृद्धावस्था के दौरान 1 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत 'उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016' बनाई और इसी के तहत ही 'उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' का गठन किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष श्रम एवं सेवायोजन मंत्री होंगेए सदस्य सचिव प्रमुख सचिव श्रम होंगे तथा इस बोर्ड में 28 सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड असंगठित कर्मकारों के हितार्थ क्रियान्वित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार को युक्तिसंगत सिफारिशें देगा। बैठक में बोर्ड के सदस्य के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

यूपीडा व डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन के लिए आरक्षित किये जायेंगे नौ खनन क्षेत्र

कैबिनेट के फैसले

- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के लिए उप समिति गठित
- राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 स्वीकृत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्य सरकार उप्र एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) एवं डेडीकेटेड फ्रे ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. द्वारा संचालित निर्माण कार्यों के लिए 9 खनन क्षेत्रों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने पूर्व में विकास एजेंसियों को खनन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया था लेकिन इसमें से 13 खनन क्षेत्र विकास एजेंसियों ने वापस कर दिए हैं। इसके अलग-अलग कारण बताए गए है। मसलन विकास परियोजना से खनन क्षेत्र का एप्रोच नहीं था। वापस किए गए 13 खनन क्षेत्रों में से 9 खनन क्षेत्र यूपीडा और डीएफसीसीआईएल को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा की अचल/चल सम्पत्तियां नोएडा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान को हस्तान्तरित की जाएंगी। सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा को पूर्ण रूप से संचालित किए जाने तथा एमसीआई मानकों के अनुरूप स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श कर संस्तुति देने के लिए एक उपसमिति गठित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू करने से पूर्व उनके विधिक, व्यावहारिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं अन्य बिन्दुओं पर समिति निर्णय लेगी। समिति में नगर विकास मंत्री, पंचायती राज, वित्त और ग्राम्य विकास मंत्री सदस्य होंगे। समिति के निर्णय लेने और कार्यवाही ज्ञापन (एक्शन टेकन रिपोर्ट) मंत्रिपरिषद से अनुमोदित कराकर आयोग की रिपोर्ट सहित विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उप्र का गठन सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आनन्द मिश्र की अध्यक्षता में किया गया था। पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रारम्भ होने वाले आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए रिपोर्ट दी जानी थी। आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन 31 अक्टूबर 2018 को प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को प्रस्तुत किया गया था। आयोग द्वारा प्रदेश की ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के लिए विभिन्न विषयों पर 64 संस्तुतियां की गयी हैं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें अनुभाग अधिकारी पद पर प्रमोशन यूडीए और अनुसचिव पद पर प्रमोशन अनुभाग अधिकारी के पद से होंगे। इसके अतिरिक्त बन्द पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड हरपुर-गजपुर गोरखपुर की 50 एकड़ भूमि को एथनॉल प्लाण्ट की स्थापना के लिए इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को 30 वर्ष की लीज पर हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है। इसमें भूमि के कुल मूल्य का 2.5 प्रतिशत धनराशि कंपनी राज्य सरकार को देगी। पहले दस साल के लिए यह धनराशि 65 लाख, 11 से 20 साल के लिए 97.50 लाख और 21 से 30 साल के लिए 130 लाख होगा।

गरीब सवर्णों को आरक्षण का फैसला राजनैतिक स्टंट

- निर्णय सही नियत व नीति से नहीं लिया गया, फिर भी बसपा करेगी समर्थन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मोदी सरकार की कैबिनेट में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत करते हुए समर्थन किया है। आरक्षण का समर्थन करते हुए मायावती ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला सही नीयत व नीति से नहीं लिया गया है। यह एक राजनीति स्टंट और छलावा है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि यह फैसला कार्यकाल खत्म होने से पहले लिया गया होता ताकि इसको सही ढंग से लागू कर लाभ देने के लिए संसद व संसद के बाहर कोर्ट में भी बीजेपी सरकार मार्ग प्रशस्त करके दिखाती। लेकिन फिर भी बीएसपी इस सम्बंध में लाये जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी।

मंगलवार को एक बयान जारी कर मायावती ने कहा कि बीएसपी सवर्ण समाज के गरीबों के साथ-साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी इसी ही आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने की माँग लम्बे समय से कर रही है। इसके लिये संसद व संसद के बाहर भी लगातार संघर्ष करने के साथ-साथ इस सम्बंध में औपचारिक तौर पर पत्र भी केन्द्र की सरकारों को लिखा है। लेकिन दु:ख की बात है कि केन्द्र की वर्तमान बीजेपी सरकार ने अपना संकीर्ण व साम्प्रदायिक रवैया अपनाते हुये समाज के केवल एक वर्ग के ग़रीबों को ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिये संविधान संशोधित करना स्वीकार किया है,। यह समाज के अन्य गरीबों के साथ न्याय नहीं बल्कि उनकी घोर अनदेखी है। उन्होंने कहा कि जनविरोधी नीतियों व घोर चुनावी वादाखिलाफियों के कारण विश्वासघात के आरोपों से घिरी केन्द्र की बीजेपी सरकार द्वारा सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बंध में घोषणा वास्तव में लोगों को एक चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है।

मायावती ने कहा कि संविधान में सामाजिक, शैक्षणिक व अर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने की जो वर्तमान व्यवस्था है, वह अब काफी पुरानी है जबकि देश की जनसंख्या के साथ ही इन वर्गों की जनसंख्या भी अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिये अब इस बात की भी आवश्यकता है कि एससी/एसटी व ओबीसी वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा की सही तरीके से समीक्षा की जाये तथा उन्हें इनकी बढ़ी हुई आबादी के अनुपात में आरक्षण को भी समुचित तौर पर बढ़ाकर दिये जाने की नई संवैधानिक व्यवस्था की जाये। साथ ही इन वर्गों के लिये उन क्षेत्रों में भी आरक्षण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये जहां अब तक आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू ही नहीं की गई है।

पैकफेड घोटाले में करोड़ों की मनी लांड्रिग का मामला

ईडी की विशेष अदालत ने किया बाबू सिंह कुशवाहा समेत 22 आरोपियों को तलब

- ईडी ने आरोपियों की 89 करोड़ से ज्यादा की संपति जब्त की है

विधि संवाददाता। लखनऊ

सूबे की 174 सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए पैकफेड से जारी धनराशि में करोड़ों का घोटाला करने के मामले में ईडी की विशेष अदालत ने मनी लांड्रिग एक्ट के तहत तत्कालीन काबीना मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा समेत 22 मुल्जिमों को बतौर समन मुकदमे के विचारण के लिए पांच फरवरी को तलब किया है।

वर्ष 2010-11 में पैकफेड को सूबे के प्रत्येक सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए एक-एक करोड़ की धनराशि एनआरएचएम फंड से आवंटित की गई थी। इस घोटाले में सरकार को 89 करोड़ 74 लाख 62 हजार 478 रुपए की आर्थिक क्षति हुई। 16 जुलाई, 2018 को ईडी ने इस मामले में सूबे के तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा नाथूराम कुशवाहा व गया प्रसाद कुशवाहा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने इसके साथ ही नोएडा की कम्पनी मेसर्स डिगी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड व इस कम्पनी के निदेशक सौरभ जैन तथा इसकी पत्नी रजनी जैन, अमरोहा की कम्पनी मेसर्स सीएनसी मेटल फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड व इस कम्पनी के निदेशक सुनीत सिंघल, मुंबई की कम्पनी मेसर्स दर्पण मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ की कम्पनी मेसर्स ब्लूम्स रियलटर्स एंड हास्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विन्ध्य शक्ति सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, भगवत प्रसाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर्स ट्रस्ट व तथागत शिक्षा समिति तथा सोनीपत की कम्पनी मेसर्स सर्जिकान मेडिक्यूप प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक नरेश ग्रोवर, नई दिल्ली की कम्पनी मेसर्स अनुजय एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़ के केके जैन एजूकेशनल ट्रस्ट जबकि कानपुर की कम्पनी मेसर्स एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफलर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सांघवी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स क्वाद फैशन प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस एजुकेशन सोसाइटी तथा देवरिया की एक कम्पनी मेसर्स श्याम गंगा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने आरोप पत्र में इन सभी को मनी लांड्रिआ एक्ट की धारा 3/4 का आरोपी बनाया था। जिला जज सुरेंद्र कुमार यादव ने मंगलवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कुशवाहा समेत सभी 22 मुल्जिमों को मुकदमे के विचारण के लिए तलब कर लिया।

यह है मामला

दो जनवरी, 2012 को सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश से एनआरएचएम घोटाले के मामले में एफ्आईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरु की थी। ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक 14 अप्रैल, 2012 को ईडी ने भी करोड़ों के इस घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत सूचना दर्ज कर जांच शुरु की। विवेचना के बाद कुशवाहा समेत सभी 22 मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। ईडी ने इस मामले में बाबु सिंह कुशवाहा की करीब 60 करोड़ 70 हजार की चल-अचल संपति जब्त की है। जबकि मेसर्स सर्जिकान मेडिक्यूप की 22 करोड़ व सौरभ जैन व उसकी एसोसिएट कम्पनी की करीब सात करोड़ 12 लाख की संपति जब्त की है।

बाढ़ से बचाव को मोटर बोट का नया बेड़ा खरीदने का फैसला

- एनडीआरएफ, सेना व नेवी के जवान लोकल होमगार्ड को मोटर बोट चलाने का प्रशिक्षण देंगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार ने बाढ़ में तबाही पर नियंत्रण के ठोस प्रयास शुरू कर दिये हैं। जिसके तहत सरकार ने बाढ़ प्रभावित 41 जिलों में मोटर बोटों का बेड़ा खरीदने का निर्णय लिया है। अधिकतर जिलों के पास अभी अपनी मोटर बोट नही हैं और बाढ़ के दौरान किराये की मोटर बोट के काम से जैसे-तैसे काम चलाया जाता रहा है। इसके अलावा सरकार ने सभी जिलों में आपदा प्रबंध प्राधिकरणों को कागजों से बाहर निकाल कर अस्तित्व में लाने का निर्णय लिया है।

बाढ़ के चलते हर साल होने वाली तबाही से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर चिन्तित है और वह चाहत हे कि बाढ़ की वजह से कम से कम नुकसान हो। पिछले साल बाढ़ग्रस्त जिलों में सीएम योगी ने खुद सघन दौरा करके पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाया था और अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये थे। इस काम को अंजाम देने के लिये सीएम योगी ने राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण में पहली बार लेफ्टीनेंट जनरल आरपी साही की नियुक्ति की थी। इससे पहले इस पद पर मुख्यसचिव अथवा विभागीय मंत्री पदेन उपाध्यक्ष हुआ करते थे। सेना के अफसर को उपाध्यक्ष बनाने के पीछे सीएम की सोच राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को सक्रिय करने की थी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि लम्बी कवायद के बाद आपदा पर पुख्ता कदम उठाने का काम शुरू हो गया है। जिसके तहत बाढ़ प्रभावित जिलों में मोटर बोट का बेड़ा खरीदने का निर्णय हुआ है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंड़ा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, फरुर्खाबाद, बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती तथा महाराजगंज के लिये दो-दो मोटर बोट खरीदे जा रहे हैं जबकि गाजीपुर, उन्नाव, लखनऊ, बुलंदशहर, कासगंज, बरेली, बांदा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतमबुद नगर, रामपुर, हरदोई, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और शहजहांपुर के लिये एक-एक मोटर बोट खरीदी जा रही है। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टीनेंट जनरल आरपी साही का कहना है कि इन मोटर बोटों को चलाने के लिये एनडीआरएफ, सेना तथा नेवी के जवान लोकल होमगार्ड जवानों को प्रशिक्षण देंगे। बाढ़ की दशा में होमगार्ड के ये जवान बचाव और राहत कार्य करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार आपदा प्रबंधन नीति को तैयार कर चुकी है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिये रखा जाएगा। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरणों को भी सक्रिय किया जा रहा है। इसके लिये सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

पांच अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले

लखनऊ। राज्य सरकार ने अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के पांच पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी सर्वेश मिश्रा को हटाकर उनके स्थान पर उन्नाव में तैनात अष्टभुजा प्रसाद सिंह को तैनात किया गया है। सर्वेश मिश्रा को अपर पुलिस अधीक्षक सचिवालय सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। सचिवालय सुरक्षा में तैनात विनोद कुमार पांडेय को अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव बनाया गया है। 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के उपसेनानायक प्रेमचंद्र का तबादला अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली के पद पर किया गया। 11 वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के उपसेनानायक रमेश प्रसाद गुप्ता को अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के पद पर आगरा में तैनाती प्रदान की गई है। बीते सोमवार की देर रात ये तबादला आदेश जारी किए गए।

सिंचाई समस्याओं के निराकरण के लिए टोल फ्री नम्बर जारी

लखनऊ। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने एवं किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैयया कराने के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किया है। टोल फ्री नम्बर के माध्यम से कृषक अपनी समस्या सीधे सरकार तक पहुंचा सकेगा। मंत्री ने कहा कि उक्त टोल फ्री नम्बर पर आने वाली शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टोल फ्री नं. 18001805450 प्रदेश के किसानों की सेवा में निशुल्क प्रत्येक दिवस में प्रात: छह बजे से रात्रि दस बजे तक उपलब्ध रहेगा। यह टोल फ्री नम्बर प्रदेश के किसानों के लिए समस्त राजकीय नलकूपों व नहरों की सिंचाई सम्बधी समस्याओं के समुचित व त्वरित निराकरण के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है।

भाजपा सरकार की खामियों को उजागर करने को सपा का अभियान शुरू

लखनऊ। समाजवादी पार्टी का समाजवादी विकास विज़न एवं सामाजिक न्याय के लिए जन अभियान मंगलवार से प्रदेश की समस्त 403 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो गया। यह अभियान 20 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों की सभी ग्राम सभाओं में मुख्य रूप से पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जन सम्पर्क व बैठके करके उनको जानकारी देना है। सपा प्रवक्ता एवं सचिव राजेन्द्र चौधरी ने बताया भाजपा के नेताओं द्वारा किस प्रकार देश की जनता को वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव के समय तथा उसके बाद वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में लोक लुभावने व जनता को गुमराह करने वाले वायदे किये थे जो लगभग पौने पॉच वर्ष के कार्यकाल में पूरे नहीं हो सके। नौजवान इन्तजार कर रहे हैं कि कब 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। जनता इन्तजार कर रही है कब उनके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचेगा। गरीब किसान अपने कर्ज की मॉफी के लिए राह देख रहा है। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित समाजवादी विकास विज़न एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम के अन्तर्गत गॉव-गॉव जनसम्पर्क के पहले दिन 7 जनवरी को विधानसभावार सैकड़ों सभाओं में बैठकें व जनसम्पर्क कार्यक्रम सम्पन्न हुए। सपा प्रवक्ता के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत लगभग एक लाख गॉवों तक जनसम्पर्क का कार्य किया जायगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत जनता को समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार के समय किये विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जायगी। जनता तक यह संदेश भी पहुॅचाया जा रहा हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य ऐजण्डा प्रदेश के विकास का न होकर समाज को बांटना है जबकि यूपी में सपा सरकार के दौरान सीएम रहे अखिलेश यादव का मुख्य लक्ष्य प्रदेश का विकास था।

पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने की बैठक

लखनऊ। आगामी 16 जनवरी को प्रस्तावित पिछड़े वर्ग सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने बैठक की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर अनिल सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक का संचालन प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रान्तीय संयोजक चौधरी सत्यवीर सिंह ने किया। अनिल सैनी ने तैयारी बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों से आए प्रतिनिधियों से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश भर में एक-एक पदाधिकारी को पांच-पांच जनपदों का प्रभार सौंपा है जो अपने-अपने सम्बन्धित जनपदों का दौरा कर पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष पद के लिए पिछड़े वर्ग के तीन-तीन नामों का पैनल तैयार करेंगे। साथ ही साथ आगामी 16 जनवरी को प्रान्तीय सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति तय करेंगे।

पुलिस प्रशिक्षण वर्ष के संकल्प को पूरा करने में जुटा ट्रेनिंग निदेशालय

अस्थायी आटीसी स्थापित करने के साथ ही दूसरे राज्यों व अर्द्धसैनिक बलों के ट्रेनिंग सेंटर की भी ली जा रही मदद

विवेक श्रीवास्तव। लखनऊ

पुलिस महकमे में एक लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती करके वर्ष 2019 को प्रशिक्षण वर्ष के रूप में मनाने के योगी सरकार के संकल्प को पूरा करने में प्रशिक्षण निदेशालय जोर-शोर से जुटा हुआ है। प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर क्षमता से दोगुना ज्यादा का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले सिपाहियों को प्रशिक्षित करना निदेशालय के लिए बड़ी चुनौती है। इससे पार पाने के लिए अधिकारियों ने प्रशिक्षण का पूरा खाका तैयार कर लिया है। पुलिस लाइन और पीएसी में बड़ी संख्या में अस्थाई रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के साथ ही दूसरे प्रदेशों और अर्द्धसैनिक बलों के ट्रेनिंग सेंटरों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी आने वाले समय में पुलिस और पीएसी में भारी संख्या में भर्ती होने जा रहे सिपाहियों के प्रशिक्षण को सकुशल संपन्न कराने की दिशा में पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। प्रशिक्षण निदेशालय के पास नौ प्रशिक्षण संस्थान हैं। जिनकी कुल क्षमता सिर्फ 5820 पुलिस कर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की है। निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में होने वाली भर्तियों को देखते हुए व्यापक तैयारी की गई है।

योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महकमे में सिपाहियों के 56 हजार से अधिक पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। जिसके तहत बीते दिसंबर माह से भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस साल के अंत तक सभी भर्तियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस महकमे में पहले से ही 41 हजार 520 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। योगी सरकार ने वर्ष 2019 को पुलिस प्रशिक्षण वर्ष के रूप में मनाने का भी ऐलान कर रखा है। इसे देखते हुए प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा पुलिस लाइन और पीएसी की वाहिनियों में स्थापित स्थायी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटरों की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया गया है। यूपी में 13 स्थायी जनपदीय आरटीसी की क्षमता 2400 और 18 स्थायी पीएसी आरटीसी की क्षमता 3550 है। इनके अलावा 42 अस्थायी जनपदीय आरटीसी और 11 अस्थायी पीएसी आरटीसी स्थापित किए जा रहे हैं। निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा उत्तराखंड में एक, राजस्थान में तीन, सीआरपीएफ के आठ, सीआईएसफ के तीन और एसएसबी के प्रशिक्षण सेंटर में भी नए भर्ती होने वाले सिपाहियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की तैयारी है। एसआई टीचर की भारी कमी को देखते हुए 200 उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण निदेशालय एक कोर्स कराने जा रहा है। एक माह का प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद इनकी तैनाती एसआई टीचर के रूप में की जा सकेगी।

वर्चुअल क्लास रूम से जुड़ चुके हैं 30 सेंटर

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय की महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रथम चरण में 30 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को वर्चुअल क्लास रूम से जोड़ा जा चुका है। पुलिस की ट्रेनिंग को आधुनिक बनाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने बीते साल मई महीने में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में वर्चुअल क्लास रूम की शुरुआत की थी। इसके जरिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता के साथ संख्या के नजरिए से भी हजारों प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को एक प्लेटफार्म पर बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले स्थाई और फिर पुलिस लाइन व पीएसी वाहिनियों में स्थापित अस्थाई ट्रेनिंग सेंटरों को इससे जोड़ा जा रहा है।

इस महीने ही मिल जाएंगे 31 हजार नए सिपाही

वर्तमान में महकमे के नौ प्रशिक्षण संस्थानों के सहित कुल 101 स्थाई-अस्थाई ट्रेनिंग सेंटरों पर 31 हजार रिक्रूट कांस्टेबल का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि छह महीने का यह व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा होने वाला है। 24 जनवरी को पासिंग आउट परेड के साथ ही फोर्स की कमी झेल रहे पुलिस महकमे को 31 हजार नए सिपाही मिल जाएंगे।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 9 जनवरी, 2019

भारत, नॉर्वे सहयोग बढ़ाने पर सहमत

● दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का संकल्प भी लिया

एजेंसी। नई दिल्ली

नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अपने औपचारिक स्वागत समारोह के दौरान नॉर्वेजियन के प्रधान मंत्री एर्ना सोलबर्ग से हाथ मिलाते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की उनकी समकक्ष एर्ना सोलबर्ग के साथ बातचीत के बाद, भारत और नॉर्वे मंगलवार को सागरीय अर्थव्यवस्था पर करीबी सहयोग तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का संकल्प भी लिया। मोदी और सोलबर्ग ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा और दिशा देने के तौर तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों ने भारत-नॉर्वे सागरीय वार्ता आयोजित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सोलबर्ग सोमवार को यहां पहुंची थीं। उनका मंगलवार सुबह राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया। मोदी ने सोलबर्ग के साथ बातचीत के बाद एक बयान में कहा, हमने अपने सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा तथा दिशा देने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सागरीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर सार्थक चर्चा की।

भारत और नॉर्वे के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहयोग है। दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर करीबी समन्वय है। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में मोदी ने कहा कि वे भारत के विकास लक्ष्यों से पूरी तरह से तालमेल बनाए हुए हैं। सतत विकास लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवोत्कर्ष, सतत उपभोग और शांति एवं न्याय जैसे क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय 17 वैश्विक लक्ष्यों का समूह है।

मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे आपसी साझेदारी के तहत जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलतापूर्वक सहयोग कर रहे हैं। मोदी ने कहा, जब मैं 2017 में जी-20 शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री सोलबर्ग से मिला था तो उन्होंने मुझे उपहार में फुटबॉल दिया था उसका अर्थ अलग था। यह फुटबॉल खेल के गोल के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रतीक था।

नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के महत्व और इसकी जनसंख्या को देखते हुए, जब तक भारत को साथ नहीं लाया जाता , विश्व सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, मैंने भारत में, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य में शानदार सुधार देखा है। सोलबर्ग ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति तेज करने तथा संबंध और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत के विकास और प्रगति के लिए सागरीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सागरीय वार्ता सागरीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को दिशा देगी। सोलबर्ग ने कहा कि नॉर्वे और भारत समुद्र से संबंधित मुद्दों पर सहयोग बढाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई।

मोदी, ट्रंप ने की फोन पर बातचीत

● व्यापार घाटा एवं अफगानिस्तान पर हुई चर्चा

एजेंसी। नई दिल्ली/वाशिंगटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टेलीफोन पर बातचीत में भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे के मामले तथा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोमवार शाम हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और वर्ष 2018 में भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझीदारी लगातार बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया। व्हाइट हाउस ने बातचीत की जानकारी देते हुए कहा, नेताओं ने 2019 में भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई और भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटा कम करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार 2017 में भारत के साथ अमेरिका का वस्तु एवं सेवा व्यापार कुल करीब 126.2 अरब डॉलर था। निर्यात 49.4 अरब डॉलर और आयात 76.7 अरब डॉलर रहा। भारत के साथ अमेरिकी वस्तु एवं सेवा व्यापार घाटा 2017 में 27.3 अरब रहा। व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-प्रशांत में सुरक्षा एवं समृद्धि बढ़ाने और अफगानिस्तान में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई।

अफगानिस्तान में लाइब्रेरी के लिए वित्तीय मदद को लेकर ट्रम्प ने पिछले सप्ताह मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि युद्धग्रस्त देश में इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। युद्धग्रस्त देश की सुरक्षा के लिए और ज्यादा कदम नहीं उठाने पर उन्होंने भारत तथा अन्य देशों की आलोचना की थी। भारत युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत अफगानिस्तान को तीन अरब डॉलर की मदद देने को लेकर प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने नई 22 वार्ता व्यवस्था की शुरूआत और भारत, अमेरिका एवं जापान के बीच पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की भी प्रशंसा की। दोनों देशों के बीच 2 2 वार्ता का पहला दौर सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय बनाने के साथ ही रक्षा, आतंकवाद रोधी और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ रहे द्विपक्षीय सहयोग पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। इससे पहले, दोनों नेताओं ने अर्जेंटीना में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर नवंबर में त्रिपक्षीय शिखर बैठक में वार्ता की थी। दोनों नेताओं और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ब्यूनस आयर्स में त्रिपक्षीय बैठक की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की और आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने का संकल्प जताया।

रास में बार-बार स्थगन का टूटा चार सत्रों का रिकार्ड

● छह बार हुई स्थगित

एजेंसी। नई दिल्ली

सीबीआई के कथित दुरुपयोग, राफेल सौदे की जेपीसी से जांच की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और राजद सदस्यों के भारी विरोध के कारण राज्यसभा की बैठक मंगलवार को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तक छह बार स्थगित करनी पड़ी। यह पिछले चार सत्रों में सर्वाधिक स्थगन का रिकार्ड है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार सभापति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल में पिछले चार सत्र के दौरान उच्च सदन में एक दिन में सर्वाधिक बार स्थगन का यह रिकार्ड है। सभापति कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभापति नायडू और उपसभापति हरिवंश ने सदन की बैठक सुचारु बनाने के हरसंभव उपाय करते हुए सभी दलों के नेताओं से बातचीत भी की। लेकिन विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही लगातार बाधित रही।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को नायडू ने सदन की बैठक पहली बार 11 बजकर आठ मिनट से दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की। इसके बाद हरिवंश को सदन की बैठक पांच बार, दो बजकर छह मिनट पर, फिर दो बजकर 22 मिनट पर, दो बजकर 46 मिनट पर, तीन बजकर सात मिनट पर और फिर तीन बजकर 32 मिनट पर स्थगित करनी पड़ी। सदन में लगातार गतिरोध कायम रहने के कारण बैठक नौ जनवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक को सुचारु बनाने के लिए स्थगन के दौरान हरिवंश ने विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं के साथ कई दौर की बैठक की। इस दौरान दो अध्यादेशों के स्थान पर लाए गए भारतीय चिकित्सा परिषद और कंपनी संशोधन कानून से संबंधित विधेयकों को पारित करने पर सहमति बनी थी।

रेलवे के केवल 23 प्रतिशत श्रमिकों को मिल रही न्यूनतम मजदूरी

एजेंसी। नई दिल्ली

देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भारतीय रेल के 463 ठेकों की समीक्षा के बाद पाया कि मात्र 23 प्रतिशत श्रमिकों को ही न्यूनतम वेतन मिलता है। कैग ने मंगलवार को इस संबंध में अपनी रपट संसद में रखी है। उल्लेखनीय है कि कैग की रपट उस दिन आई है जिस दिन श्रम अधिकारों को लेकर देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों की दो दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हुई है। कैग ने भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिकों के मामले में वैधानिक अनिवार्यताओं का अनुपालन रपट में रेलवे के 463 ठेकों की समीक्षा की और पाया कि मात्र 105 मामलों में ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। रपट में कहा गया है कि 129 समझौतों के तहत संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित नहीं है। ऑडिट आकलन के अनुसार 3,310 संविदा श्रमिकों को 9.23 करोड़ रुपए का कम भुगतान किया गया। अत: पाया गया कि मात्र 23 प्रतिशत मामलों में ही संविदा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

इंदौर में बोरों के वजन को लेकर पल्लेदारों और कारोबारियों में ठनी

एजेंसी। इंदौर

मध्यप्रदेश की करीब 260 कृषि उपज मंडियों में जिंसों के भरे बोरों का वजन 50 किलोग्राम तक सीमित किए जाने की मांग को लेकर पल्लेदारों और कारोबारियों के बीच फिर खींचतान शुरू हो गई है। पल्लेदारों का कहना कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्ष 2017 के उस आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए जिसमें कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय आदर्श श्रम मानकों के मुताबिक पल्लेदारों से 50 किलोग्राम से ज्यादा वजनी बोरा नहीं उठवाया जा सकता। मध्यप्रदेश हम्माल तुलावटी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक राजू प्रजापति ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को बताया, हम इस मांग को लेकर पिछले साल हड़ताल भी कर चुके हैं। इसके बाद भी भरे बोरों का वजन अधिकतम 50 किलोग्राम रखे जाने की नई व्यवस्था के लिए कारोबारी तैयार नहीं हैं।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने छह मई 2017 को सभी मंडी समितियों को जारी आदेश में कहा था, अंतरराष्ट्रीय आदर्श श्रम मानकों में किसी सक्षम वयस्क व्यक्ति द्वारा 50 किलोग्राम से अधिक भार उठाना अनुपयुक्त माना गया है। अत: प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में हम्मालों द्वारा उठाए जाने वाले बोरों का वजन 50 किलोग्राम से अधिक न रखा जाए। पल्लेदार नेता प्रजापति ने कहा, इस आदेश को जारी हुए डेढ़ बरस से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, इसके बावजूद हमसे अब भी मंडियों में अनाजों, दलहनों और तिलहनों के 85 किलोग्राम से लेकर 95 किलोग्राम वजन के बोरे उठवाए जा रहे हैं। बोरों का यह वजन तय मानकों के मुकाबले लगभग दोगुना है।

उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक इतने भारी वजन के बोरे उठाने के बाद ज्यादातर पल्लेदारों को 40 साल की उम्र के बाद गर्दन, कन्धों, कमर और घुटनों की स्वास्थ्यगत समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उधर, कारोबारियों का कहना है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संबंधित आदेश सरासर अव्यावहारिक है। इंदौर की संयोगितागंज अनाज मंडी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष मनोज काला ने कहा, अगर कृषि मंडियों में जिंसों के भरे बोरों का वजन 50 किलोग्राम तक सीमित किया जाता है, तो यह व्यवस्था उपज की तुलाई, भण्डारण और परिवहन के मामले में किसानों और व्यापारियों के साथ उद्योग जगत के लिए भी दिक्कतों का सबब बन जाएगी। इस बीच, राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सारा मामला स्थानीय मंडी समितियों के विवेक पर छोड़ दिया है।

क्विक न्यूज

जम्मू-कश्मीर में चार वर्षों में 838 आतंकी मारे गए

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर मे 2014 से 838 आतंकवादी ढेर कर दिए गए और इस दौरान 183 आम लोग भी मारे गए। लोकसभा मे एक प्रश्न के लिखित उत्तर मे गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि 2014 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर मे।,213 आतंकी घटनाएं हुईं। अहीर ने कहा, इन घटनाओ मे 183 आम लोगो की जान गई और 838 आतंकवादियो को ढेर किया गया।

मोदी 29 जनवरी को छात्रों और शिक्षकों से चर्चा करेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को छात्रो, शिक्षको और अभिभावको से परीक्षा एवं उससे संबंधित तनाव पर चर्चा करेगे। सरकार ने छात्रो को माईजीओवी डॉट इन पर स्वयं को रजिस्टर कर परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता मे हिस्सा लेने और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम मे प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का मौका पाने के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, प्रतियोगिता केवल कक्षा 9 से 12 वी तक के छात्रो, ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट कॉलेज छात्रो, उनके माता-पिता एवं शिक्षको के लिए है। चयनित प्रतिभागियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत मे भाग लेने का अवसर मिलेगा। परीक्षा पे चर्चा के प्रथम संस्करण मे पिछले साल प्रधानमंत्री ने देशभर के अनेक छात्रो से बातचीत की थी।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समिति गठित

मुंबई। देश मे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता मे एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसका मकसद डिजिटल भुगतान की मजबूती और सुरक्षा को लेकर सुझाव देना है। उल्लेखनीय है कि नीलेकणि ने ही आधार कार्ड जैसी योजना को अमलीजामा पहनाया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान मे बताया कि इस समिति मे पांच सदस्य होगे। यह समिति देश मे डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा, समिति अपनी पहली बैठक के बाद 90 दिन मे रपट सौपेगी। समिति का काम देश मे डिजिटल भुगतान की मौजूदा स्थिति की समीक्षा, व्यवस्था मे कमियो की पहचान और उन्हे ठीक करने के लिए सुझाव देना होगा।

सैन्य, असैन्य क्षेत्रों के लिए समेकित साइबर सुरक्षा प्रणाली जरूरी

● बोले पूर्व वायुसेना प्रमुख अरूप राहा

एजेंसी। कोलकाता

भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत) अरूप राहा ने साइबर आतंकवाद को अपनी तरह का बदतरीन आतंकवाद करार देते हुए मंगलवार को कहा कि सैन्य एवं असैन्य क्षेत्रों के लिए कोई समेकित साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के मामले में भारत अब भी चीन से बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि साइबर युद्ध के मामले में भारतीय सेना बेहतर स्थिति है, लेकिन उन्होंने अन्य क्षेत्रों में साइबर हमलों के बढ़ते खतरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनका कामकाज चाहे किसी भी प्रकृति का हो, वे ऐसे हमलों को लेकर संवेदनशील हैं।

राहा ने कहा, साइबर अपनी तरह का बदतरीन आतंकवाद है, क्योंकि इसमें आपको गोलियां चलाने के लिए प्रशिक्षित लोगों और हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती और न ही ढेर सारे लोगों की हत्या करनी पड़ती है। इसमें हिंसा तो नहीं होगी, लेकिन बगैर फायरिंग के ही इसमें काफी मौतें और बर्बादी हो जाएगी। उन्होंने कहा, चीन ने काफी हद तक एक साइबर युद्ध प्रणाली विकसित की है। हम असल में काफी पीछे हैं और हम अब भी चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्षेत्र अहम है।

ईरान में परमाणु संयंत्रों की हैकिंग पर राहा ने कहा ने कहा कि उनके परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैक किए गए थे और वे परमाणु संयंत्रों के कामकाज पर नियंत्रण नहीं रख सके, वे असहाय थे। उन्होंने कहा, विस्फोट होगा - नाभिकीय होगा - आप ऊर्जा का उत्पादन या वितरण भी नहीं कर सकते। प्रभाव तो काफी होता है।

केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को नई दिल्ली में अपनी बैठक से पहले अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पायने से हाथ मिलाते हुए

मोदी सोलापुर में 3,150 करोड़ की ढांचागत परियोजनाओं का करेंगे ऐलान

एजेंसी। मुंबई

लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलापुर में बुधवार को 3,168 करोड़ रूपए मूल्य की ढांचागत और आवासीय परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मोदी साथ ही शहर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के बयान के अनुसार, मोदी प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 1811.33 करोड़ रूपए की आवासीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे जिसके तहत 30 हजार मकान मुहैया कराए जाने की योजना है। इसके अलावा वह कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 211 - नया राष्ट्रीय राजमार्ग 52 - पर सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद खंड में चार लेन के सड़क मार्ग का उद्घाटन करेंगे।972.50 करोड़ रूपए की यह परियोजना आईआरबी इंफ्रा को दी गई है।

चार लेन के सोलापुर-उस्मानाबाद राजमार्ग से सोलापुर और मराठवाड़ा क्षेत्र के बीच संपर्क में सुधार होगा। पीआईबी के अनुसार, आवासीय परियोजना से मुख्य रूप से बेघर लोगों को फायदा होगा जिनमें कचरा बीनने वाले, रिक्शाचालक, कपड़ा और बीड़ी मजदूर तथा अन्य ऐसे ही लोग शामिल हैं। इस परियोजना में 188.33 करोड़ रूपए के निवेश की जरूरत है जिसमें से 750 करोड़ रूपए केंद्र द्वारा राज्य सरकार को सहायता के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

मोदी महाराष्ट्र के पश्चिमी शहर सोलापुर में एक भूमिगत सीवरेज प्रणाली और तीन सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की भी शुरूआत करेंगे। इसके अलावा, मोदी सोलापुर स्मार्ट सिटी इलाके में एक जलापूर्ति और सीवेज प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगे। इससे उजनी बांध से शहर को जलापूर्ति में सुधार होगा। इस योजना पर एक अनुमान के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 244 करोड़ रूपए का खर्च आएगा। इससे उम्मीद की जाती है कि सेवा प्रदाता प्रणाली में व्यापक सुधार आएगा। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 2014 के बाद से सोलापुर के दूसरे दौरे पर आ रहे हैं। उस समय उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के महाराष्ट्र . कर्नाटक सीमा संभाग के चार लेन के सड़क मार्ग की आधारशिला रखी थी। उस समय उन्होंने 765 केवी सोलापुर .रायचूर बिजली पारेषण लाइन की भी शुरूआत की थी। वह शहर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे।

सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायक को 100 करोड़ का प्रलोभन दे रही भाजपा : दिग्विजय

एजेंसी। भोपाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेताओं पर मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के एक विधायक को 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव देने का आरोप लगाया है। प्रदेश विधानसभा परिसर में सिंह ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, मैहर से भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुरैना जिले के संबलगढ़ से कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाह से संपर्क किया और उन्हें एक ढाबे पर ले गए। वहां भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग ने कुशवाह से मुलाकात की और कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोनों ने भाजपा की बनने वाली नई प्रदेश सरकार में मंत्री पद देने का लालच भी कुशवाह को दिया।

कांग्रेस के कई विधायकों को इस प्रकार का लालच देने का दावा करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने कुशवाह से तैयार खड़े चार्टर हवाई जहाज में साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कुशवाह ने इससे इंकार कर दिया। उन्होने कहा, शिवराज सिंह चौहान विचलित हैं क्योंकि वह अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। सिंह के आरोपों के सवाल पर मिश्रा ने कहा, वह काफी समय से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। छपास रोग के कारण किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं किसी ढाबे पर नहीं गया। यदि उनके पास सबूत है तो उन्हें इस मामले में कानूनी कार्वाई करना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह के बयानों को गंभीरता से नहीं लेने की बात कही। भार्गव ने कहा, इतनी बड़ी राशि आपने सूनी नहीं होगी। दिग्विजय के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वह गप्पबाजी करते हैं। आप जानते हैं केन्द्र में भाजपा की अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। इसलिए भाजपा इस तरह के हथकंडों में विश्वास नहीं करती है। वहीं विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता को चुनौती दी कि सिंह अपने आरोप साबित करें। सारंग ने कहा, यह शिगुफेबाजी है। अब वे साबित करें कि हम किसी ढाबे में गए थे। कांग्रेस की सरकार है, कार्रवाई करे। वीडियो दिखाए। अगर यह साबित होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत एनडीए सरकार द्वारा सवर्णों में गरीबों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि इन परिवारों को आरक्षण देने का कांग्रेस हमेशा से समर्थन करती रही है।

राहुल, सोनिया के आयकर मामलों में आदेश पारित लेकिन अमल नहीं

● आयकर विभाग ने न्यायालय को बताया

एजेंसी। नई दिल्ली

आयकर विभाग ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 2011-12 के कर मामले में निर्धारण संबंधी आदेश पारित किया गया है लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के मामले में कर मांग संबंधी 31 दिसंबर, 2018 का निर्धारण आदेश रिकार्ड में पेश करने को कहा। इससे पहले, आयकर विभाग ने यह रिकार्ड में पेश करने पर जोर दिया था। पीठ ने कहा कि इसके आधार पर वह मामले के गुणदोष पर कोई राय नहीं बनाएगा। पीठ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक हलफनामा दाखिल करने और 31 दिसंबर 2018 के जारी सीबीडीटी का एक सर्कुलर चार सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया जिसमें संपत्ति के मूल्यांकन पर करों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था परंतु चार जनवरी को इसे वापस ले लिया गया था। न्यायालय ने आय कर विभाग को कांग्रेस नेताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे और सर्कुलर का इसके बाद एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 29 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। यह मामला नेशनल हेराल्ड से संबंधित है जिसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है।

भाजपा विधायकों के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान स्पीकर चुनाव के मुद्दे पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन की ओर जाते हुए

अब आसान होगा किसी भी व्यक्ति की पहचान करना

एजेंसी। नई दिल्ली

अपराधियों, संदिग्धों, विचाराधीन कैदियों, लापता बच्चों और लोगों, आपदा पीड़ितों एवं अज्ञात रोगियों की पहचान के उद्देश्य से डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करने के नियमन संबंधी विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने पारित कर दिया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में डीएनए प्रौद्योगिक (उपयोग और लागू होना) नियमन विधेयक, 2018 पेश करते हुए कहा कि विधेयक की नींव 2003 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में पड़ी थी और तब से लगभग 15 साल में यह विभिन्न स्तरों पर हर पहलू पर विस्तृत अध्ययन और पड़ताल से गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि न्यायिक निर्णयों में डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग दुनिया के कई देशों में पहले से हो रहा है।

हर्षवर्धन ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य डीएनए प्रयोगशालाओं की मान्यता का मानकीकरण करना है। नई प्रयोगशालाएं बनाना है और डीएनए डेटा बैंक स्थापित करना है। इसके अलावा देश में लावारिस शवों, लापता बच्चों की पहचान में भी डीएनए प्रोफाइलिंग कारगर होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश में क्रूर अपराधियों को पकड़ने में भी यह तकनीक काम आएगी और कानूनी उद्देश्यों से डीएनए प्रोफाइल का उपयोग किया जा सकेगा। हर्षवर्धन ने बताया कि इसके तहत एक डीएनए नियामक बोर्ड बनाया जाएगा जो उक्त विषय पर केंद्र और राज्यों को सुझाव देगा। उन्होंने कहा कि गृह, विदेश, रक्षा और महिला

● अपराधियों, संदिग्धों, विचाराधीन कैदियों, लापता बच्चों और लोगों, आपदा पीड़ितों एवं अज्ञात रोगियों की पहचान के लिए डीएनए तकनीक के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पारित

एवं बाल विकास मंत्रालय समेत छह मंत्रालयों को इस विधेयक के पारित हो जाने से लाभ होगा। सीबीआई, एनआईए जैसी जांच एजेंसियों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को भी यह सीधा लाभ पहुंचाएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इसमें निजता, गोपनीयता और डेटा संरक्षण का गहराई से ध्यान रखा गया है। विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने मांग की कि विधेयक को वापस लिया जाए और स्थाई समिति को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मामले में निजता के अधिकार पर दिए गए फैसले के अनुरूप विधेयक में कुछ भी नहीं लाया गया है।

थरूर ने मांग की कि इस तरह के किसी भी विधेयक को लाने से पहले सरकार को डेटा संरक्षण कानून बनाना चाहिए। उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग का देश में दुरुपयोग होने की आशंका व्यक्त की। थरूर ने कहा कि इन सबको देखते हुए विधेयक को वापस लिया जाए और स्थाई समिति को वापस भेजा जाए। भाजपा के संजय जायसवाल ने कहा कि यह विधेयक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को भी शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि डीएनए जांच की प्रक्रिया स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन को पूरी तरह बाबुओं पर नहीं छोड़ा जाए क्योंकि ऐसा करने से इसका मकसद पूरा नहीं होगा। जायसवाल ने कहा कि इससे जुड़े नियामक बोर्ड का चेयरमैन जिसे भी बनाया जाए उसे डीएनए प्रौद्योगिकी की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि देश के लोगों को महसूस होना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं और इसमें इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि इससे न्यायिक मामलों में मदद मिलेगी। माकपा के पीके बीजू ने कहा कि सरकार को इस विधेयक में सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग नहीं हो और लोगों की निजता के साथ समझौता नहीं हो। टीआरएस के वी एन गौड़, जदयू के कौशलेंद्र कुमार और एसडीएफ के पीडी राय ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि जहां तक दुरुपयोग की बात है तो डॉक्टरों के पास दिए जाने वाले सभी रक्त नमूनों के दुरुपयोग की भी गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है। मंत्री ने कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो इसमें संशोधन किया जाएगा।

जद(एस) ने सामान्य वर्ग में गरीबों के लिए आरक्षण का किया समर्थन

बेंगलुरू। जद(एस) सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराने के केंद्र के कदम का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जद(एस) सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, हम समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए हमेशा खड़े हुए और खड़े होते रहेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दे दी।

चेन्नई में मंगलवार को आगामी पोंगल के त्योहार के लिए मिट्टी के घड़े बनाता एक कुम्हार

सीबीआई मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा

एजेंसी। नई दिल्ली

सीबीआई के कथित दुरूपयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर सपा एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर बाधित रही और पांच बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजकर करीब 30 मिनट पर कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाए। बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और कहा कि उन्हें कुछ सदस्यों की ओर से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं लेकिन उन्होंने ये

● बैठक दिन भर के लिए स्थगित

नोटिस स्वीकार नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

इसी बीच सदन में हंगामा शुरू हो गया। सपा सदस्यों ने अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर और कांग्रेस, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपने अपने मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। नायडू ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया। हंगामा थमते न देख उन्होंने 11 बज कर करीब 10 मिनट पर बैठक को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा। सपा, तृणमूल कांग्रेस, राजद आदि दलों के सदस्य आसन के समक्ष आ गए और नारे लगाने लगे। उधर कांग्रेस के कुछ सदस्य राफेल विमान सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। बाद में कांग्रेस के सदस्य भी आसन के समक्ष आ गए। हंगामे के बीच ही जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 चर्चा के लिए रखा। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से शांत होने और सदन चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश यह सब (हंगामा) देख रहा है और शीतकालीन सत्र में गंभीरता से काम नहीं हुआ है।

रास की एक दिन बैठक सर्वानुमति से नहीं बढ़ाई गई

विपक्ष का आरोप

● सरकार एक के बाद एक मनमाने फैसले कर रही है : कांग्रेस

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्यसभा की बैठक एक दिन के लिए बढ़ाए जाने के निर्णय को सत्तापक्ष का एकपक्षीय फैसला बताते हुए इसका विरोध किया। विपक्ष का आरोप है कि संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आसन से सत्र की कार्य अवधि बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई। उच्च सदन में मंगलवार को जब उपसभापति हरिवंश ने बुधवार तक के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की तो उसके बाद विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य सदन में ही बैठे रहे। स्थगन के बाद लगभग 20 मिनट तक सदन में ही रहने के बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में संसद भवन परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के आनंद शर्मा ने बताया अवधि बढ़ाने पर विपक्षी दलों से कोई बातचीत नहीं की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बिना औपचारिक घोषणा किए सदन की अवधि बढ़ा दी गई है। शर्मा ने कहा कि विपक्ष का विरोध आरक्षण संबंधी विधेयक पर नहीं है बल्कि सरकार के मनमाने तरीके पर है। आजाद ने बताया कि सरकार ने विपक्ष से चर्चा किए बिना ही सदन की बैठक एक दिन के लिए बढ़ा दी। इतना ही नहीं आसन से इसकी सूचना सदन को दिए जाने की संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक के बाद एक मनमाने फैसले कर रही है। इसके विरोध में विपक्ष को बैठक की कार्यवधि बढ़ाए जाने की आसन से घोषणा किए जाने के इंतजार में स्थगन के बाद भी सदन में अतिरिक्त समय तक बैठना पड़ा। ऐसा नहीं होने पर विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा सपा, राकांपा और तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, माकपा और भाकपा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राकांपा के माजिद मेनन ने कहा कि सदन की अवधि बढ़ाने के लिए विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई और ना ही इसकी सदन में औपचारिक घोषणा हुई। यह संसदीय परंपरा और नियमों के विरुद्ध है।

इस बीच संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा नागरिकता विधेयक और सामान्य वर्ग को आरक्षण देने संबंधी दो अहम विधेयक पारित कराने के लिए सदन की बैठक एक दिन के लिए बढ़ाई गई है। विपक्ष से चर्चा नहीं करने का आरोप सरासर गलत है। सभापति महोदय और सरकार की तरफ से लगातार इस पर चर्चा हुई।

पटना में मंगलवार को सरकार विरोधी नीतियों के विरोध में बुलाई गई 48 घंटे की हड़ताल के दौरान पुलिस के साथ झड़प करतीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने से रोकने का नियम नहीं

एजेंसी। पणजी

गोवा सरकार के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में बैठने के लिए कोई विशिष्ट ड्रेस कोड नहीं है। हिजाब पहनने के कारण एक छात्रा द्वारा नेट में बैठने से रोकने का आरोप लगाने के बाद गोवा सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को पत्र लिखकर कहा कि छात्रा को परीक्षा में बैठने दिया जाना चाहिए था।

दरअसल, पिछले महीने सफीना खान सौदागर ने कहा था कि पणजी में एक परीक्षा केंद्र में सुपरवाइजर ने उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा था और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया

● नेट परीक्षा में बैठने के लिए कोई विशिष्ट ड्रेस कोई नहीं : गोवा सरकार

गया। गोवा के उच्च शिक्षा निदेशक प्रसाद लोलिएनकर ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को लिखे पत्र में कहा, छात्रा को परीक्षा में बैठने दिया जाना चाहिए था। लोलिएनकर ने एक जनवरी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि पहली नजर में यह स्पष्ट है कि संबंधित वेबसाइट या किसी अन्य जगह परीक्षा के लिए ड्रेस के नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

नर्मदा प्रसाद बने मध्य प्रदेश विस के अध्यक्ष भाजपा का बहिर्गमन

● शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने लगाए नारे

एजेंसी। भोपाल

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बहिर्गमन के बीच कांग्रेस विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति मंगलवार को प्रदेश की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कांग्रेस सदस्य नर्मदा प्रसाद प्रजापति को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसका पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने समर्थन किया। इसके बाद प्रजापति के पक्ष में तीन अन्य विधायकों ने तीन अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए गए और उनका समर्थन किया गया।

इसके बाद भाजपा ने अपनी पार्टी की ओर से पार्टी विधायक कुंवर विजय शाह का नाम अध्यक्ष पद के लिए पेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने यह कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दी कि पहले प्रथम प्रस्ताव का निराकरण मिल जाए। भाजपा सदस्यों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और आसन के पास जाकर नारे लगाए, जिसके बाद सदन में हुए हंगामे के बीच प्रोटेम स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दो बार 10-10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। जब तीसरी बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सदस्य आसन के पास जाकर फिर नारे लगाने लगे लोकतंत्र की हत्या बंद करो। इसी बीच, चौहान ने कहा, एक वरिष्ठ आदिवासी नेता का नाम प्रस्तावित नहीं करने दिया गया। यह लोकतंत्र एवं सदन का अपमान है। हम सदन का बहिष्कार करते हैं। भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, विपक्ष अपना प्रस्ताव भी रखें। उनके पास बहुमत नहीं है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वाकआउट कर रहे हैं। सदन में आकर अपना प्रस्ताव रखें। हम वोटिंग के लिए तैयार हैं।

नागरिकता विधेयक के खिलाफ असम, पूर्वोत्तर के कई राज्य बंद

एजेंसी। गुवाहाटी

विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ आसू के 11 घंटे के बंद के दौरान असम में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को कई जगहों पर बंद कर दिया और वाहनों में तोड़फोड़ की। डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के पैतृक स्थल पर उनके आवास का घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। डिब्रूगढ़ में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ का प्रयास करने पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 का मकसद नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन कर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक अत्याचार की वजह से भागकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हिन्दू, सिख, बौद्ध जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। आसू ने राज्य व्यापी बंद का आयोजन किया और असम गण परिषद (अगप) ने इसे समर्थन दिया। अगप ने सोमवार को भाजपा नीत असम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। विपक्षी कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) द्वारा आहूत पूर्वोत्तर बंद से ब्रह्मपुत्र घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ और बराक घाटी में आंशिक असर देखने को मिला। एनईएसओ क्षेत्र में छात्र संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। आसू भी इसका घटक है। इसी मुद्दे पर एनईएसओ द्वारा आहूत बंद

● डिब्रूगढ़ में आसू के कार्यकर्ताओं का भाजपा कार्यालय जलाने का प्रयास

● एनईएसओ की ओर से आहूत बंद का असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में 100 से ज्यादा संगठनों ने किया समर्थन, जनजीवन प्रभावित

का असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में 100 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन किया। विधेयक के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने डिब्रूगढ़ में सोनोवाल के आवास का घेराव किया। उन्होंने नारे लगाए कि मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि वह राज्य के लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया और कई स्थानों पर ट्रक, कार अन्य वाहनों के शीशे तोड़ दिए। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ जिले में पटरियों को भी कुछ देर के लिए जाम किया गया हालांकि जीआरपी के प्रदर्शनकारियों को पटरियों पर से हटाने के बाद दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों की आवाजाही बहाल हो गई।

केएमएसएस द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालवाहक ट्रकों की आवाजाही नहीं हो पाई। आसू और एनईएसओ के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने कहा, अगर मेघालय और मिजोरम विधेयक का विरोध करते हुए कैबिनेट प्रस्ताव ला सकता है तो असम ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आसू के अध्यक्ष दीपांकर नाथ ने कहा इसपर व्यापक विरोध के बावजूद केंद्र में भाजपा सरकार ने हमपर अलोकतांत्रिक तरीके से विधेयक थोपा है, क्योंकि वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के वोट के सहारे (लोकसभा) चुनाव जीतना चाहते हैं। राज्यों से मिली खबरों के मुताबिक, बंद से मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और नगालैंड में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेतृत्व में 70 संगठनों ने विधेयक के खिलाफ अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की शुरूआत की। संगठनों ने कहा है कि तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, वन उत्पाद तथा अन्य सामानों को राज्य से बाहर नहीं ले जाने लेंगे। केएमएसएस के सलाहकार अखिल गोगोई ने पीटीआई-भाषा से कहा, विधेयक के खिलाफ आज से हमने अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी शुरू की है। हम राज्य से अपने संसाधनों को बाहर नहीं ले जाने देंगे।

आप छोड़ने के बाद खैरा ने बनाई नई पार्टी

एजेंसी। चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने के दो दिन बाद सुखपाल सिंह खैरा ने नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया। खैरा ने बताया, नई पार्टी का नाम पंजाबी एकता पार्टी रखा गया है और यह पूरी तरह पंजाब केंद्रित और क्षेत्रीय दल होगा।

इस दौरान आप के छह विधायक (कंवर सिंह संधू, जगदेव सिंह कमालु, जगतार सिंह हिस्सोवाल, पीरमल सिंह खालसा, मास्टर बलदेव सिंह और नाजर सिंह मानशहिया) मौजूद थे। पंजाब विस में विपक्ष के नेता पद से हटाए जाने के छह महीने बाद रविवार को खैरा ने आप छोड़ दी थी। खैरा ने हालांकि, विस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। खैरा 2017 में हुए विस चुनाव में कपूरथला जिले के भुलत्थ से चुने गए थे। खैरा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, उनके तानाशाही रवैए ने भारतीयों और पंजाबियों के दशकों पुराने सड़े गले प्रणाली के विकल्प के सपने को चकनाचूर कर दिया।

गुवाहाटी में मंगलवार को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से बुलाई गई हड़ताल के चलते बस अड्डे पर गाड़ियों का इंतजार करते यात्री

केंद्रीय मजदूर यूनियनों की दो दिन की हड़ताल शुरू

एजेंसी। नई दिल्ली

विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल मंगलवार को शुरू हुई। इन यूनियनों ने सरकार पर श्रमिकों के प्रतिकूल नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है।

हड़ताल में शामिल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की महासचिव अमरजीत कौर ने पीटीआई से कहा कि , असम, मेघालय, कर्नाटक, मणिपुर, बिहार, झारखंड, गोवा, राजस्थान, पंजाब , छत्तीसगढ़ और हरियाणा में- खास कर औद्योगिक इलाकों में हड़ताल का काफी असर दिख रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में परिवहन विभाग के कर्मचारी और टैक्सी और तिपहिया आटो चालक भी हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में परिवहन विभाग पूरी तरह बंद है। हरियाणा राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं।

एटक नेता के अनुसार रेलकर्मियों ने काले फीते पहन कर अपने अपने कार्यस्थल के बाहर बैठकें कर इस हड़ताल को अपना समर्थन जताया है। इस हड़ताल को 10 केंद्रीय श्रम संघों का समर्थन है। इनमें एटक , इंटक, एचएमएस, सीटू, एआईटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा,एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी शामिल हैं। इन यूनियनों का दावा है कि हड़ताल में 20 करोड़ मजदूर शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) इस हड़ताल में शामिल नहीं है।

अमरजीत कौर ने कहा कि दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली, बैंक, बीमा और परिवहन क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इन यूनियनों ने हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को राजधानी में मंडी हाउस से संसद की ओर विरोध रैली निकालने की घोषणा की है। उनका कहना है कि देश में अन्य स्थानों में भी जुलूस निकाले जाएंगे।

ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बैंकों का कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित

नई दिल्ली। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से देश के कुछ हिस्सों में बैंकों का कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आठ और नौ जनवरी को दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक कर्मचारियों के एक वर्ग ने हड़ताल का समर्थन किया था। आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) तथा बैंक एम्पलाइज फेडरेशन आफ इंडिया (बीईएफआई) ने हड़ताल का समर्थन किया है। हड़ताल से उन बैंकों का परिचालन प्रभावित हुआ है जहां इन दोनों यूनियनों का ज्यादा प्रभाव है।

हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की सात अन्य यूनियनें हड़ताल में भाग नहीं ले रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को सूचित कर चुके हैं कि हड़ताल की स्थिति में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। चूंकि इन दो यूनियनों के कर्मचारी हड़ताल पर थे, इस वजह से बैंकों की कई शाखाओं में काउंटर सेवाएं मसलन जमा और निकासी, चेक समाशोधन आदि कामकाज प्रभावित हुआ।

लखनऊ में मंगलवार को विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सदस्य 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन करते हुए।

गीता गोपीनाथ ने संभाला मुद्राकोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री का पद

एजेंसी। वाशिंगटन

गीता गोपीनाथ ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री का पद-भार संभाल लिया है। वह यह दायित्व संभालने वाली पहली महिला हैं। मैसूर (भारत) में जन्मी गीता गोपीनाथ ने पिछले सप्ताह अपना यह नया कार्य-भार संभाला। उन्हें ऐसे समय इस बहुपक्षीय वित्तीय संगठन के मुख्य आर्थिक सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है जब यह अनुभव किया जा रहा है कि आर्थिक वैश्वीकरण की गाड़ी उल्टी दिशा में मुड़ रही है और उससे बहुपक्षीय संस्थाओं के सामने भी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। गीता गोपीनाथ (47) हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाती रही हैं। वह मुद्राकोष में मौरिस आब्स्टफेल्ड की जगह लाई गई हैं जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे।

चाबहार बंदरगाह जल्द ही पूरी तरह चालू होगा

ईरान का बैंक मुंबई में शाखा खोलेगा: गडकरी

एजेंसी। नई दिल्ली

सरकार को ईरान में भारत की मदद से बने रणनीतिक चाबहार बंदरगाह को जल्द ही पूरी तरह चालू किए जाने की उम्मीद है। यह बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। साथ ही भारत ने ईरान के एक बैंक को मुंबई में अपनी शाखा स्थापित करने की स्वीकृति भी दी है जो जल्द ही शुरू की जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत यात्रा पर आए ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ राजधानी में मंगलवार को बैठक के बाद यह जानकारी दी। गडकरी के पास जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग जैसे विभागों की जिम्मेदारी है। गडकरी ने कहा, चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। कुछ समस्याएं थी, लेकिल ईरान की सरकार और मंत्री भी जल्द से जल्द इनके समाधान करने की प्रक्रिया में है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द चाबहार बंदरगाह को पूरी तरह परिचालन में लाने की स्थिति में होंगे।

दक्षिणी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित यह बंदरगाह रणनीतिक रुप से बेहद अहम है। देश के पश्चिमी तट से यहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जा रहा है जो चाबहार से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। भारत ने इस बंदरगाह के लिए 8.5 करोड़ डॉलर की मशीनों की खरीद का आर्डर जारी कर रखा है। इससे पहले गड़करी ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दी है। गडकरी ने बताया कि पसरगाद अगले तीन महीने में यह शाखा चालू करेगा। भ्रारतीय रिजर्व बैंक इस शाखा को खोलने के लिए सारी अनुमतियां पहले ही दे चुका है। जरीफ ने कहा, हमें खुशी है कि भारत के यूको बैंक और ईरान के पसरगाद बैंक ने आपस में काम करना शुरू कर दिया है।

दोनों बैंक चाबहार बंदरगाह के परिचालन से जुड़े लेनदेन के लिए सेवा प्रदान करेंगे। गडकरी ने कहा कि ईरान के मंत्री के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई। चाबहार का आंशिक परिचालन हमने पहले शुरू कर दिया है और यहां माल आना शुरू हो गया है। पहला जहाज ब्राजील से माल लेकर आया। वहां परिचालन के लिए वित्त का प्रबंध पूरा किया जा चुका है। यह पहली दफा है जब भारत अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन कर रहा है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को ईरान में चाबहार त्रिपक्षीय समझौता बैठक के दौरान शहीद बेहेश्ती बंदरगाह (चाबहार बंदरगाह) के एक हिस्से के परिचालन का दायित्व संभाल लिया है।

ईरान को उम्मीद, अमेरिकी प्रतिबंधों से एक और छूट मांगेगा भारत

नई दिल्ली। ईरान ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि भारत उससे कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से एक और छूट मांगेगा। ईरान ने कहा कि वह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला दुनिया का सबसे विश्वसनीय देश है। भारत को पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने ईरान से कच्चे तेल की खरीद के मामले में छह महीने की रियायत दी थी। इसके लिए भारत ने आयात घटाने तथा एस्क्रो रुपए भुगतान की सहमति दी थी। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने यहां एक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, चुनौतियों से पार पा लिया जाएगा, इसका तरीका निकल आएगा। आप ऐसे देश की ओर देख रहे हैं जिसने 40 साल से लागू प्रतिबंधों के बावजूद समृद्धि प्राप्त की है और प्रगति की है। उन्होंने अपने देश के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को शुद्ध रूप से गैरकानूनी करार दिया।

ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ का स्वागत करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी।

बैंकिंग शेयरों में तेजी का रुख सेंसेक्स 130 अंक चढ़ा

एजेंसी। मुंबई

निफ्टी 10,800 से ऊपर निकला

बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी का रुख रहा। विदेशी कोषों का प्रवाह बढ़ने और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में लिवाली से कारोबार की समाप्ति के समय बाजार में तेजी बन गई।

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 130 अंक बढ़कर 35,980.93 अंक पर बंद हुआ जबकि व्यापक आधार वाला निफ्टी सूचकांक 30.35 अंक की बढ़त के साथ 10,802.15 अंक पर बंद हुआ। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अग्रिम अनुमान व्यक्त किया है। इससे बाजार को सहारा मिला।

कारोबार की शुरुआत में ज्यादातर समय दोनों ही सेंसेक्स नकारात्मक दायरे में रहे। शुरू में निवेशकों का उंचे भाव पर मुनाफा वसूली का जोर रखा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और डालर के मुकाबले रुपए में गिरावट से कारोबारी धारणा नरमी की रही। कंपनियों के तीसरी तिमाही के परिणाम को देखते हुए भी सतर्कता बरती गई। हालांकि, समाप्ति के समय विदेशी कोषों की लिवाली निकलने से बाजार में तेजी बन गई। सेंसेक्स एक समय 36,037.35 अंक की उंचाई को छू गया लेकिन अंत में हल्की मुनाफा वसूली से यह 130.00 अंक यानी 0.36 प्रतिशत गिरकर 35,980.93 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50-शेयरों पर आधारित निफ्टी सूचकांक कारोबार के दौरान उंचे में 10,818.45 अंक और नीचे में 10,733.25 अंक के बीच रहने के बाद अंत में 30.35 अंक यानी 0.28 प्रतिशत बढ़कर 10,802.15 अंक पर बंद हुआ। बीएनपी पारिबा के शेयरखान सलाहकार के प्रमुख हेमंग जानी के मुताबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करने के बाद मंगलवार को बैंकिंग शेयरों में तेजी का रुख रहा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि विशेषतौर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित राशि में कमी आई है।

त्विक न्यूज

जेएसपीएल ने भारतीय रेलवे के 55 प्रतिशत आर्डर पूरे किए: नौशाद अंसारी

नई दिल्ली। जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपीएल) ने भारतीय रेलवे से मिले एक लाख टन रेल की आपूर्ति के आर्डर मे से 55 प्रतिशत की आपूर्ति कर दी है। जेएसपीएल के संयुक्त प्रबंध निदेशक नौशाद अंसारी ने कहा, हमने 97,400 टन मे से 54,302 टन रेल की आपूर्ति कर दी है। हमे उम्मीद है कि समय से पहले फरवरी तक हम आर्डर को पूरा कर देगे। जुलाई, 2018 मे जेएसपीएल को भारतीय रेलवे के 2,500 करोड़ रुपए के लंबी रेल आपूर्ति आर्डर की वैश्विक निविदा का 20 प्रतिशत हिस्सा मिला था। जेएसपीएल को करीब एक लाख टन रेल लाइन आपूर्ति का आर्डर मिला था। इस्पात राज्यमंत्री विष्णु देव साईं ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि रेलवे ने कहा है कि 2018-19 मे उसे 14 लाख टन और 2019-20 मे 17 लाख टन रेल लाइन की जरूरत होगी।

इंफोसिस के एक और शीर्ष अधिकारी का इस्तीफा

बेंगलुरू । देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी इंफोसिस मे शीर्ष अधिकारियो के पद छोड़ने का सिलसिला अभी थमा नही है। कंपनी के एक और शीर्ष अधिकारी ने लगभग दो दशक तक काम करने के बाद अपना त्यागपत्र दिया है। कंपनी के ऊर्जा, यूटिलिटी, संसाधन और सेवा इकाई संबंधी कामो के वैश्विक प्रमुख सुदीप सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है। हालाकि कंपनी ने उनके इस्तीफे पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। सिंह कंपनी मे जिस इकाई की कमान संभालते थे उसका कारोबार करीब डेढ़ अरब डॉलर का है।

कोष आकार पर जालान समिति की पहली बैठक

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता मे गठित उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक मंगलवार को हुई। समिति रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले आरक्षित कोष के उचित आकार और सरकार को दिए जाने वाले लाभांश के बारे मे अपनी सिफारिश देगी। सूत्रो ने बताया कि छह सदस्यो वाली यह समिति संभवतः अप्रैल मे अपनी रिपोर्ट सौप देगी। यह उच्चस्तरीय समिति दुनियाभर मे केन्द्रीय बैंको द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवहारो की समीक्षा कर अपना

अप्रैल-दिसंबर में यात्री वाहन की खुदरा बिक्री दो प्रतिशत घटी : एफएडीए

एजेंसी। नई दिल्ली

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री दो प्रतिशत गिरकर 19,17,750 वाहन रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 19,65,630 वाहन था।

वाहन विक्रेताओं के संघ एफएडीए ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एफएडीए देशभर में स्थित 1,431 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से 1,072 कार्यालयों से वाहन पंजीकरण के आंकड़े जुटाता है। वाहन डीजल संघों के परिसंघ (एफएडीए) ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री बेहतर रहने की उम्मीद जताई। एफएडीए के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने कहा, अप्रैल-दिसंबर यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़ी है। इसलिए यदि हम चौथी तिमाही में वृद्धि में गिरावट को दूर करने में कामयाब रहते हैं तो हमें उम्मीद है कि पूरे वित्त वर्ष 2018-19 में हम सकारात्मक रुख के साथ अंत करेंगे। कम से कम इकाई अंक में ही उंची वृद्धि हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी के कुछ शुरुआती दिनों में शोरूम में लोगों का आना-जाना बढ़ा है जो ग्राहकों के खरीद धारणा में बेहतरी का संकेत है। दिसंबर में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 2,02,585 वाहन रही जो दिसंबर 2017 की 2,17,922 इकाई बिक्री के बदले तीन प्रतिशत कम है।

अप्रैल से दिसंबर में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री पांच प्रतिशत बढ़कर 1,10,71,352 वाहन रही। वहीं दिसंबर में यह यह आंकड़ा 11 प्रतिशत बढ़कर 11,41,209 वाहन रहा।

दोपहिया पर जीएसटी घटाया जाए: टीवीएस

नई दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने भी अब दोपहिया पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आमजन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दोपहिया को विलासिता का सामान नहीं माना जाना चाहिए। पिछले सप्ताह देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटरों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी। श्रीनिवासन ने बयान में कहा, आम लोगों के लिए दोपहिया का काफी महत्व है। निश्चित रूप से दोपहिया के लिए जीएसटी दर पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

विश्व बैंक के प्रमुख किम एक फरवरी को पद छोड़ेंगे

वॉशिंगटन। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने अचानक इस्तीफा देने की घोषणा की है जबकि उनका वर्तमान कार्यकाल पूरा होने में अभी करीब तीन साल बाकी है। किम एक फरवरी को यह पद छोड़ देंगे। उन्होंने सोमवार को इसकी जानकारी दी। विश्वबैंक की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) क्रिस्तालिना जार्जिएवा एक फरवरी को संस्था के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी। सूत्रों ने कहा कि किम ने अचानक यह निर्णय किया है और यह उनका निजी निर्णय है। विश्वबैंक ने कहा है कि वह नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने जा रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अमेरिका और विकास सहायता देने के लिए गठित इस बहुपक्षीय वित्तीय संगठन के अन्य सदस्य देशों के बीच दावपेंच फिर शुरू होने की संभावना है।

2018 में आठ बड़े शहरों में आवास बिक्री 6 प्रतिशत बढ़ी : नाइट फ्रैंक रपट

एजेंसी। नई दिल्ली

देश में मकानों की बिक्री 2018 में बढ़ी है और इस दौरान आठ प्रमुख शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री में सालाना आधार पर छह प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यह जानकारी बाजार का अध्ययन करने वाली एक प्रमुख फर्म की ताजा रपट में दी गई है।

संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की रपट के अनुसार इन आठ शहरों दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में आवासीय बिक्री बढ़ी है। वहीं कोलकाता और पुणे में गिरावट दर्ज की गई है।

इंडियन रीयल एस्टेट(जुलाई-दिसंबर 2018) शीर्षक यह रपट यहां सोमवार को जारी की गई। रपट के अनुसार ग्राहकों को लुभाने के लिए कई डेवलपरों ने मकानों की कीमत कम करने के अलावा कुछ और अप्रत्यक्ष रियायतों की भी पेशकश की। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सात साल के बाद 2018 में भारतीय आवास बाजार में बिक्री सुधरी है। इसकी अहम वजह सस्ते मकानों की मांग बढ़ना है। रपट के अनुसार बिक्री बढ़ने से बिना खड़े नए मकानों का स्टॉक कम हुआ है। ऐसे मकानों की संख्या 11 प्रतिशत घटकर 4.7 लाख इकाई पर आ गई है।

अन्य संपत्ति सलाहकार कंपनियों की तुलना में नाइट फ्रैंक की पट में आवासीय बिक्री में बढ़ोतरी की छह प्रतिशत की दर सबसे कम है। नाइट फ्रैंक के विपरीत जेएलएल इंडिया ने सात शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री में 47 प्रतिशत, एनारॉक ने 16 प्रतिशत और प्रॉप टाइगर ने नौ बड़े शहरों में बिक्री में 25 प्रतिशत बढ़ने का आंकड़ा पेश किया है। नाइट फ्रैंक के अनुसार वर्ष 2018 में 2,42,328 मकान बिकने का अनुमान है। जबकि 2017 में यह आंकड़ा 2,28,072 मकान का था। इसमें सालाना आधार पर सबसे अधिक वृद्धि बेंगलुरू में 27 प्रतिशत दर्ज की गई।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन में खामियों से सरकार को हुआ नुकसान

स्पेक्ट्रम आवंटन बाजार नीलामी के जरिए किया जाए

एजेंसी। नई दिल्ली

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने दूरसंचार मंत्रालय द्वारा स्पेक्ट्रम प्रबंधन में कई खामियां पाई हैं। कैग का कहना है कि स्पेक्ट्रम प्रबंधन में खामियों की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है।

आडिटर ने पाया कि एक दूरसंचार आपरेटर को 2015 में समिति की सिफारिशों के उलट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुछ स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया, जबकि सरकार के पास माइक्रोवेव (एमडब्ल्यू) स्पेक्ट्रम के 101 आवेदन लंबित थे।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दूरसंचार विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के स्पेक्ट्रम प्रयोगकर्ताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए एक समिति का गठन किया था। साथ ही विभाग ने प्रस्ताव किया था कि माइक्रोवेव बैंड में सभी आपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटन बाजार आधारित प्रक्रिया यानी नीलामी के जरिए किया जाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति की सिफारिशों के उलट एमडब्ल्यू एक्सेस स्पेक्ट्रम का आवंटन पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर किया जा रहा है जैसा 2009 तक 2जी और एक्सेस स्पेक्ट्रम के मामले में किया जाता था।

उच्चतम न्यायालय ने 2012 में 2008-09 के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पहले आओ पहले पाओ नीति को रद्द कर दिया और 122 दूरसंचार परमिट निरस्त कर दिए थे। माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम आपरेटरों को छोटी दूरी के लिए मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किए जाते हैं।

कैग ने कहा, यह सामने आया है कि दूरसंचार विभाग ने जून, 2010 से एक्सेस सेवाप्रदाताओं को एमडब्ल्यूए का आवंटन रोका हुआ है। दिसंबर, 2015 में सिर्फ एक आवेदक को आवंटन किया गया। नवंबर, 2016 तक एमडब्ल्यूए आवंटन से संबंधित 101 आवेदन लंबित थे। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम प्रबंधन में खामियों की वजह से सरकार को करीब 560 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें से 520.79 करोड़ रुपए का नुकसान बीएसएनएल को सरकारी कंपनी बीएसएनएल से वह स्पेक्टरम वापस न लेने के कारण है जो उसने लौटाने की पेशकश की थी।

कैग ने बरसों से पड़े खतरनाक सामान को लेकर चिंता जताई

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सीमा शुल्क विभाग के विभिन्न अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) में सामान की खेप (कार्गो) में वर्षों से जीवित बम और युद्ध सामग्री का कबाड़ पड़े होने पर चिंता जताई है। इन कार्गो को उठाया नहीं गया है।

संसद में मंगलवार को पेश कैग की रिपोर्ट में राजस्व विभाग से एक रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करने को कहा गया है ताकि ऐसे सामान या कंटेनर जिसे उठाया नहीं गया है, उसकी स्वतंत्र रूप से निगरानी की जा सके। कैग द्वारा 31 मार्च, 2017 को 85 आईसीडी और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) की गई परीक्षण जांच के अनुसार इनमें एक से लेकर 17 साल तक के खतरनाक कबाड़ के 469 कंटेनर पड़े हैं और इनका निपटान नहीं किया जा सका है।

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में तीन आईसीडी में जीवित बम, युद्ध सामग्री का कबाड़ पड़ा है। मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र दो में इस्तेमाल किए जा चुके टायरों, धातु का कबाड़ और खतरनाक रसायनों के 92 कंटेनर हैं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के तुगलकाबाद एनसीडी में नुकसान पहुंचाने वाले सामान के 15 कंटेनर हैं और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के आईसीडी में मिलेजुले कबाड़ के 50 कंटेनर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जोधपुर आयुक्तालय के तहत आईसीडी कॉन्कॉर, कनकपुरा 27 जिंदा बम और 19.4 टन का युद्ध सामग्री का कबाड़ 2008 से पड़ा है। इसी तरह आईसीडी उदयपुर और आईसीडी भगत की कोठी में 195 किलो खाली कारतूस खोल और 102.8 टन युद्ध सामग्री का कबाड़ 2004 से पड़ा है।

बाहर से होने वाले वित्तपोषण के लिए नीतिगत रूपरेखा बनाए सरकार

नई दिल्ली। बजट के बाहर से धन उपलब्ध कराने और इसके वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसके लिए एक नीति बनानी चाहिए। वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) पर जारी कैग की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट से बाहर के वित्तपोषण संसद के नियंत्रण से बाहर हैं और इनका वित्तीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ता है।

ट्रंप के साथ दूसरे संभावित शिखर सम्मेलन की तैयारी

चीन पहुंचे किम जोंग उन

एजेंसी। बीजिंग

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन मंगलवार को अचानक चीन के दौरे पर पहुंचे। समझा जाता है कि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ संभावित दूसरे शिखर सम्मेलन से पहले अपने एकमात्र बड़े सहयोगी के साथ समन्वय करने के प्रयास के तहत वह चीन दौरे पर पहुंचे हैं।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर किम सात जनवरी से दस जनवरी तक चीन के दौरे पर हैं। यह जानकारी सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने मंगलवार को दी। समझा जाता है कि मंगलवार को वह अपना 36वां जन्मदिन भी मनाएंगे। खबरों के मुताबिक उनके साथ उनकी पत्नी री सोल जू और वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनमें किम योंग चोल भी हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक समझौते में चोल उनके प्रमुख सहयोगी हैं। कुछ दिनों पहले किम ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील नहीं दी और दबाव कम नहीं किया तो वह वैकल्पिक मार्ग चुन सकते हैं।

यह दौरा ऐसे समय में भी हो रहा है जब किम और ट्रम्प के बीच दूसरे शिखर सम्मेलन की बातचीत चल रही है। दोनों के बीच पहला शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष जून में सिंगापुर में हुआ था। ट्रम्प के साथ पहली बैठक से पहले और बाद में भी किम ने पिछले वर्ष शी से मुलाकात की थी। दक्षिण कोरिया की योनहाप संवाद समिति ने खबर दी थी कि उत्तर कोरिया की एक रेलगाड़ी चीन की सीमा में पहुंची है जिसके बाद सोमवार को कयास लगाए जाने लगे थे कि किम चीन के दौरे पर हैं। दोनों देशों की मीडिया ने मंगलवार की सुबह दौरे की पुष्टि की जब किम की विशिष्ट हरे और पीले रंग की रेलगाड़ी बीजिंग के एक स्टेशन पर पहुंची।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मुख्य सचिव और दो करीबियों को पद से हटाया

एजेंसी। सियोल

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन ने अपने मुख्य सचिव और दो अन्य करीबियों को मंगलवार को पद से हटा दिया। इसे उनकी गिरती छवि को बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मून ने अपनी पूर्ववर्ती पार्क ग्वेन हए के भ्रष्टाचार के आरोपों में अपदस्थ होने के बाद मई 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी।

पिछले साल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच रिश्तों में नरमी ने उन्हें चर्चा में ला दिया था। हालिया कुछ समय में धीमी विकास दर और बेरोजगारी ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है और सामाजिक सुधारों के उनके वादों के प्रति भी निराशा हाथ लगी है। मुख्य सचिव इम जोंग सेओक ने अपने हटाए जाने की जानकारी खुद पत्रकारों को दी। अब उनकी जगह चीन में दक्षिण कोरिया के राजदूत और तीन बार सांसद रह चुके नोह यंग मिन लेंगे। नोह (62) वर्ष 2000 में राजनीति में आने से पहले 1970 और 1980 के बीच लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता थे। राजनीति में आने के बाद वह मून की वाम के प्रति झुकाव रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए थे।

निसान के पूर्व चेयरमैन कार्लोस घोसन को ले जाने वाला एक वाहन टोक्यो डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलता हुआ। टोक्यो अधिकारियों ने उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की मांग की है। मुकदमे का सामना करने के लिए घोसन को अदालत में पेश किया गया

पोंपियो ने पश्चिम एशिया की यात्रा शुरू की

एजेंसी। अम्मान

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो क्षेत्र के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता जताने के लिए पश्चिम एशिया की लंबी यात्रा पर मंगलवार को अम्मान पहुंचे। युद्ध से जर्जर सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी के अमेरिकी राष्ट्रपति के औचक फैसले के बाद पोंपियो की अरब के आठ देशों की यह यात्रा हो रही है।

पोंपियो ने पत्रकारों को बताया कि वह दिखाएंगे कि अमेरिका ने पिछले दो साल के दौरान जितने मिशन पर हस्ताक्षर किए हैं वह अब भी उनके प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया कि इस्लामिक इस्टेट का अभ्योदय बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ।

उन्होंने कहा कि युद्ध से जर्जर सीरिया में आईएस की स्वयंभू खिलाफत को नष्ट करने का अभियान बेहद सफल रहा। उन्होंने कहा, और मुझ यकीन है कि हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि ओबामा प्रशासन के दौरान आईएसआईएस जिस तरह उभरा, अब दोबारा नहीं उभरे।

इमरान ने भारत पर शांति प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया

एजेंसी। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत पर शांति प्रस्तावों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि दो परमाणु सम्पन्न देशों के बीच किसी भी तरह की लड़ाई उनके लिए आत्मघाती साबित होगी। तुर्की की समाचार एजेंसी टीआरटी वर्ल्ड को दिए एक साक्षात्कार में खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अनुसार प्रधानमंत्री ने भारत के साथ वार्ता की फिर से इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि शीत युद्ध भी दोनों देशों के हित में नहीं है।

पार्टी ने उनके हवाले से कहा, दो परमाणु सम्पन्न देशों को युद्ध के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। यहां तक कि शीत युद्ध के बारे में भी नहीं क्योंकि स्थिति किसी भी समय खराब हो सकती है। दो परमाणु सशस्त्र देशों का युद्ध में शामिल होना आत्महत्या की तरह है। उन्होंने कहा कि भारत ने उनके शांति प्रस्तावों पर जवाब नहीं दिया।

भारत का कहना है कि आतंकवाद और संवाद साथ-साथ नहीं हो सकता। खान ने कहा, भारत को एक कदम आगे बढ़ाने की पेशकश दी गई थी और हम दो कदम उठाते। लेकिन भारत ने वार्ता की पाकिस्तान की पेशकश कई बार ठुकरा दी। खान ने यह भी कहा कि भारत कश्मीरी लोगों के अधिकारों को कभी नहीं कुचल पाएगा। गौरतलब है कि 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमलों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के सर्जिकल हमले के बाद से भारत-पाक के रिश्ते तनावपूर्ण हैं।

फ्रांस अनधिकृत प्रदर्शनों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने को तैयार : प्रधानमंत्री

एजेंसी। पेरिस

फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने हफ्तों से जारी हिंसक एलो वेस्ट प्रदर्शनों को खत्म करने के सरकारी प्रयासों के बीच सोमवार को अनधिकृत प्रदर्शनों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने की योजना का ऐलान किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में सात हफ्तों से जारी सरकार

विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हो रही झड़पों के मद्देनजर फिलिप ने कहा कि सरकार ऐसे कानून का समर्थन करेगी जिसमें प्रदर्शनों की घोषणा करने की जरूरत को नहीं समझने वालों, अनधिकृत प्रदर्शनों में भाग लेने वालों और नकाब पहनकर प्रदर्शनों में पहुंचने वालों के लिए सजा का प्रावधान हो। गौरतलब है कि फ्रांस में ईंधन करों में वृद्धि के विरोध में 17 नवंबर से एलो वेस्ट नाम से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में हिंसक रूप ले लिया था।

तिब्बत में चीनी सेना को छोटी तोपों से लैस कराया गया

एजेंसी। बीजिंग

भारत की सीमा से सटे तिब्बत में हल्के टैंक शामिल किए जाने के बाद अब चीनी सेना ने वहां तैनात अपने सैनिकों की युद्ध क्षमता सुधारने के लिए वाहनों पर रखी गईं होवित्जर तोपों से लैस कराया है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने मंगलवार को यह खबर दी। ग्लोबल टाइम्स समाचारपत्र की खबर के मुताबिक तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में तैनात चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) को सचल होवित्जर उपलब्ध कराए गए हैं जिसका मकसद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैनिकों की युद्ध क्षमता को सुधारना है।

खबर में चीनी सैन्य विश्लेषकों के हवाले से बताया गया कि नए उपकरण पीएलसी-81 वाहनों पर लगी होवित्जर तोप हैं। इसमें बताया गया कि यह घोषणा पीएलए ग्राउंड फोर्स के वीचैट अकाउंट से जारी एक लेख में शनिवार को की गई। खबर में बताया गया कि चीन-भारत के बीच 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान तिब्बत में एक आर्टिलरी ब्रिगेड ने इसका इस्तेमाल किया था।

सैन्य विशेषज्ञ एवं टीवी कमेंटेटर सोंग झोंगपिंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि होवित्जर करीब 50 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती है और वह लेजर एवं उपग्रह निर्देशित मिसाइलों को मार गिरा सकती है।

विक्रम मिस्री ने चीन में भारत के नए राजदूत के तौर पर पदभार ग्रहण किया

एजेंसी। बीजिंग

चीन में भारत के नए राजदूत विक्रम मिस्री ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया और चीन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने चीन और भारत के संबंधों पर चर्चा की। 54 वर्षीय मिस्री ने बीजिंग में विदेश मंत्रालय में प्रोटोकॉल के उपमहानिदेशक होंग ली को अपने परिचय पत्र की प्रति सौंपी।

यहां भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि मिस्री ने चीनी विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के महानिदेशक वु जियांगझाओ से मुलाकात की और भारत एवं चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर अपने विचार साझा किए। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी मिस्री गौतम बम्बावाले का स्थान लेंगे जो पिछले साल नवंबर में सेवानिवृत्त हुए थे। मिस्री ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब भारत और चीन 2017 डोकलाम गतिरोध को पीछे छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मिस्री म्यामां में भारत के राजदूत के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। मिस्री प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय में भी अलग-अलग पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तर अमेरिका सहित भारत के कई दूतावासों में सेवाएं दी हैं।

मिस्री का जन्म सात नवंबर, 1964 को श्रीनगर में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में स्नातक डिग्री हासिल की। मिस्री ने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की।

क्विक न्यूज

पूर्वी सीरिया में आईएस के हमले में 32 की मौत

बरूत। पूर्वी सीरिया में अपने अंतिम गढ़ की रक्षा में जुटे जिहादियों ने खराब मौसम का सहारा लेते हुए कुर्दों के नेतृत्व वाले बल पर घातक पलटवार किया। यह जानकारी मंगलवार को युद्ध पर नजर रखने वाले एक संगठन ने दी। इस्लामिक स्टेट समूह उन स्थानों पर अपना कब्जा बरकरार रखने में विफल रहा, जहां उसने हमले किए लेकिन हमले में अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स (एसडीएफ) के 23 सदस्य मारे गए। इसमें नौ जिहादी भी मारे गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि आईएस के लड़ाकों ने कम दृश्यता का फायदा उठाकर रविवार को यूफ्रेट्स (फरात) घाटी में एसडीएफ बलों पर हमला किया। ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने कहा, लड़ाई में एसडीएफ के 23 लड़ाके और नौ जिहादी मारे गए। लड़ाई पूरी रात चली और सोमवार की सुबह जाकर यह खत्म हुई। जिहादी अक्सर खराब मौसम का फायदा उठाकर विरोधियों पर हमला करते हैं।

अमेरिकी गोलीबारी मामले में उबर चालक ने छह लोगों की हत्या का जुर्म कबूला

शिकागो। अमेरिका के मिशिगन में गोलीबारी की घटना के आरोपी उबर चालक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सोमवार को स्वीकार कर लिया। गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई थी। उबर के चालक जेसन डाल्टन ने फरवरी 2016 में अमेरिका के छोटे शहर कालामाजू में गोलीबारी की घटना में अपने ऊपर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए। डाल्टन पर हत्या के छह, हत्या के प्रयास के दो और बंदूक रखने के आठ आरोप लगाए गए थे। उसे बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा काटनी पड़ सकती है।

अमेरिका में एक इराकी नागरिको कों लंबी हिरासत के बाद रिहा करने का आदेश

मिनियापोलिस (अमेरिका)। अमेरिका में मिनेसोटा के एक संघीय जज ने एक इराकी नागरिक को अमेरिका से बाहर भेजे जाने का अंतिम आदेश दिए जाने तक आव्रजन हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। जिला जज डेविड डोटी ने सोमवार को 35 वर्षीय फारस अदनान अली को 30 दिन के भीतर रिहा करने का आदेश दिया। अली आव्रजन से जुड़े आरोपों में 18 महीने से हिरासत में है। आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारियों ने अली पर आव्रजन दस्तावेजों में सद्दाम हुसैन शासन के दौरान सेना में सेवा देने की बात छिपाने का आरोप लगाया था। अली के वकीलों ने इस निर्वासन पूर्व हिरासत को अनुचित और दीर्घकालिक बताते हुए चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें सात महीने तक एकांत में रखा जाना शामिल है।

टेक्सास विश्वविद्यालय ऊर्जा संस्थान का नेतृत्व करेंगे भारतीय अमेरिकी

ह्यूस्टन। भारतीय मूल के अमेरिकी वरुण राय को टेक्सास विश्वविद्यालय के ऊर्जा संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। राय ने एक जनवरी को माइकल वेब्बर का स्थान लिया, जो सितंबर 2018 से इस संस्थान के कार्यवाहक निदेशक थे। भारतीय मूल के राय ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था और इसके बाद 2004 में इसी विषय में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमएस की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 2008 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इसी विशेष में डाक्टरेट किया।

माल्टा तट पर फंसे कुछ शरणार्थी भोजन से कर रहे हैं इनकार : सी-वॉच

एजेंसी। रोम

माल्टा के तट पर फंसे 49 शरणार्थियों में से कुछ भोजन करने से इनकार कर रहे हैं। शरणार्थियों को बचाने के लिए नौकाएं चला रहे समूहों में शामिल सी-वॉच इंटरनेशनल ने सोमवार को यह जानकारी दी। सी-वॉच इंटरनेशनल ने ट्वीट किया, हमें ऐसी खबर मिल रही हैं कि कुछ लोग भोजन करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें डर है कि उनकी मानसिक और स्वास्थ्य काफी बिगड़ सकता है। उत्तरी अफ्रीका से यूरोप जाने के लिए खतरनाक भूमध्य सागर पार करने के प्रयास के दौरान बचाए गए ए शरणार्थी 22 दिसंबर से ही सी-वॉच और सी-आई की नौकाओं में सवार हैं क्योंकि किसी भी देश ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। शरणार्थियों में कई बच्चे भी शामिल हैं।

लाहौर की एक अदालत में मंगलवार को एक चेक नागरिक टेरीजा हल्सकोवा को ले जाते हुए पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी। पाकिस्तानी पुलिस ने टेरीजा हल्सकोवा को हेरोइन की तस्करी के प्रयास के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया था

सिख समूहों ने करतारपुर परिसर को मूल स्वरूप में बनाए रखने की अपील की

एजेंसी। इस्लामाबाद

अमेरिका में सिखों के समूहों ने पाकिस्तान से करतारपुर साहिब परिसर (केएससी) में किसी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं करने की अपील की है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के लिए पाकिस्तान और भारत सरकार दोनों के राजी होने के बाद अमेरिकन सिख काउंसिल (एएससी) और सिख इन अमेरिका (एसआईए) ने ए अपील की है। नवंबर में भारतीय मंत्रिमंडल ने डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान सीमा तक करतारपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी और 26 नवंबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में एक कार्यक्रम में डेरा बाबा नानक-करतारपुर साहिब कॉरिडोर (अंतरराष्ट्रीय सीमा तक) की आधारशिला रखी थी।

करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के लिए पाकिस्तान और भारत सरकार दोनों के राजी होने के बाद अमेरिकन सिख काउंसिल (एएससी) और सिख इन अमेरिका (एसआईए) ने ए अपील की है।

भारत की तरफ शिलान्यास के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कॉरिडोर के लिए 28 नवंबर को आधारशिला रखी थी। डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से करीब चार किलोमीटर दूर पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर करतारपुर साहिब स्थित है। इसकी स्थापना सिख गुरु ने 1522 ई. में की थी। एएससी की वेबसाइट पर कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान या दुनिया भर से आने वाले सिख श्रद्धालुओं के ठहरने के इंतजाम के लिए मुख्य केएससी से कुछ दूरी पर रेस्टरूम आदि का निर्माण होना चाहिए ताकि करतारपुर साहिब मूल स्वरूप में बना रहे। गुरू साहिबजी से संबंधित करीब 100 एकड़ में फैले प्राकृतिक क्षेत्र और रावी नदी के पास के इलाके को जितना संभव हो उसके मूल स्वरूप में रहने देना चाहिए और इस जगह के वैभव को बनाए रखना चाहिए।

डॉन अखबार ने एएससी अध्यक्ष डॉ. गुरदास सिंह और एसआईए के अध्यक्ष गुरिंदर पाल सिंह के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान सरकार मूल पुरातात्विक और सांस्कृतिक ढांचे तथा परिसर में बदलाव कर सकती है।

अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के सामने तनख्वाह का संकट, राष्ट्र को संबोधित करेंगे ट्रंप

एजेंसी। वॉशिंगटन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के अपने रुख पर सख्ती से कायम रहते हुए मंगलवार की रात अपना पक्ष एवं तर्कों को राष्ट्र के सामने रखेंगे। सरकार के आंशिक रूप से ठप पड़े कामकाज को फिर से शुरू करने से पहले वह इस मुद्दे का हल चाहते हैं। खर्चों के लिए धन का अनुमोदन न मिलने से लगातार तीन सप्ताह से सरकारी कामकाज के आंशिक रूप से बंद रहने की वजह से हजारों संघीय कर्मचारियों को शुक्रवार को भी अपनी तनख्वाह नहीं मिली।

राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप अपने ओवल ऑफिस (कार्यालय) से यह पहला भाषण देंगे। इसके बाद वह मैक्सिको सीमा पर दीवार की जरूरत पर बल देने के लिए उस इलाके का दौरा करने वाले हैं। ट्रम्प का कहना है कि अवैध आव्रजन रोकने के दीर्घकालिक समाधान के लिए यह दीवार बनाना जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने ट्वीट किया वह इस दौरे का उपयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवीय संकट से निपटने के काम में लगे लोगों से मिलने के लिए करेंगे।

इसके अलावा प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बारे में भी विचार कर रहा है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को इस दीवार परियोजना पर संसद की अनुमति के बिना कार्य करने की छूट मिल जाए। ट्रंप प्रशान ने मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के लिए 5.6 अरब डॉलर की मांग की है लेकिन संसद से इसकी मंजूरी नहीं मिल पा रही है। ट्रंप टीवी पर संबोधन और सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे की घोषणा कर के विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और सत्तारूढ़ रिपब्लिकन सांसदों पर सरकारी कामकाज फिर से शुरू करने का दबाव बना रहे हैं।

वहीं इस बंद के चलते कर रिफंड में देरी की आशंका को दूर करते हुए ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि करदायकों का पैसा (रिफंड) उन्हें समय पर ही मिलेगा। रिफंड संबंधी यह छूट पिछली सरकारों में इस प्रकार की स्थिति में अपनाई गई परिपाटी से भिन्न होगा और इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है। व्हाइट हाउस बजट कार्यालय के कार्यवाहक निदेशक रसल वाउट ने कहा कि कर रिफंड के लिए विनियोग (धन खर्च करने) की एक मंजूरी पहले ही मिली हुई है उसकी कोई सीमा तय नहीं है। इसके आधार पर रिफंड का भुगतान सामान्य रूप से होता रहेगा।

अमेरिका में 15 वर्ष पुराने हत्या के चर्चित मामले में दोषी महिला को माफी मिली

शिकागो। अमेरिका की एक अदालत ने वर्षों पुराने हत्या के एक चर्चित मामले में दोषी सिन्टोइया ब्राउन को माफी दे दी है। वह 2004 में उस व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में सजा काट रही थी जिसने उसे सेक्स के लिए इस्तेमाल किया था। तब सिन्टोइया किशोरी थी। टेनेसी के गवर्नर बिल हैसलेम ने कहा कि अब 30 वर्ष की हो चुकी सिन्टोइया ब्राउन को 2004 में नैशविले में रियल एस्टेट एजेंट की हत्या के लिए बेहद कड़ी सजा दी गई थी। 2004 में 16 वर्षीय सिन्टोइया एक दलाल से बच कर भाग रही थी तब सेना का पूर्व निशानेबाज जॉनी एलन उसे अपने घर ले आया। लेकिन सिन्टोइया की मुसीबत खत्म नहीं हुई क्योंकि एलन भी उसे सेक्स के लिए ही अपने घर लाया था। उसने सिन्टोइया को अपने हथियार दिखा कर सेक्स के लिए मजबूर किया। अपनी जान के डर से सिन्टोइया ने एलन को मार डाला। अदालत ने सिन्टोइया को फर्स्ट डिग्री मर्डर (इरादतन हत्या) और डकैती का दोषी ठहराया था और उसे कम कम 51 साल कैद के बाद पैरोल की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले को दुखदाई और पेचीदा बताते हुए हैसलेम ने 10 वर्ष की पैरोल की शर्त के साथ सिन्टोइया को माफी दी है। उसे को समाज में रहने का प्रशिक्षण देने के बाद सात अगस्त को रिहा किया जाएगा। हैसलेम ने एक बयान में कहा, सिन्टोइया ब्राउन के कबूलनामे के मुताबिक, उसने 16 वर्ष की आयु में एक खतरनाक अपराध को अंजाम दिया था। सिन्टोइया के वकीलों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिन्टोइया ने अपने समर्थकों और गर्वनर का आभार व्यक्त किया है और खुद पर उनका भरोसा बरकरार करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का वादा किया है।

स्वास्थ्य

निकट दृष्टि दोष की जद में ज्यादातर अमेरिकी, आप भी रखें अपना और बच्चों का ख्याल

ह्यूस्टन। अमेरिका में निकट दृष्टि दोष (मायोपिया) की समस्या अब महामारी की हद तक बढ़ रही है। नेशनल आई इंस्टीट्यूट के डेटा के मुताबिक 42 प्रतिशत अमेरिकी इसकी जद में हैं जो 1971 में 25 प्रतिशत तक सीमित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक दूर की वस्तुएं देख सकने में अक्षम लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के एम्स ने पिछले साल एक अध्ययन में बताया था कि भारत में पांच से 15 आयुवर्ग के बच्चों में हर छह में से एक इस समस्या से ग्रस्त है। संयुक्त राष्ट्र के डेटा में भी कहा जा चुका है कि भारत जैसे जिन देशों में यह समस्या पहले बहुत कम रही वहां 2050 तक यह बहुत बढ़ जाएगी।

निकट दृष्टि दोष आम तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को ज्यादा होता है और यह काला मोतिया रोग (ग्लूकोमा) एवं आंशिक अंधेपन जैसी आंखों की दीर्घकालिक समस्याओं का कारण बन सकता है। तकनीक के अत्याधिक इस्तेमाल से बच्चों में निकट दृष्टि दोष बढ़ने के बीच संबंध की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस अध्ययन अब तक सामने नहीं आया है लेकिन कई शोधों में इन दोनों के बीच संबंध दिखाया गया है। निकट दृष्टि दोष के चलते बच्चों में धुंधला दिखने की समस्या को लेकर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय नेत्र संस्थान बच्चों में इस समस्या को दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष प्रबंधन सेवा उपलब्ध करा रहा है। टेक्सास में यह पहली तरह की सेवा होगी। पूर्व में हुए अध्ययनों में बताया गया है कि बच्चों को फोन से दूर रखने, घर से बाहर के खेल-कूद के लिए प्रोत्साहित करने से इस समस्या पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

पुजारा बल्लेबाजी में शीर्ष तीन में शामिल

- पुजारा के अब 881 रेटिंग अंक हैं
- विराट कोहली 922 अंक के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं न्यूजीलैंड के विलियमसन दूसरे स्थान पर
- सिडनी में 159 रन की नाबाद पारी खेलने वाले 21 वर्षीय पंत बल्लेबाजी रैंकिंग में 17वें स्थान पर पहुंचे

एजेंसी। दुबई

रन मशीन चेतेश्वर पुजारा आस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की मंगलवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग में बल्लेबाजों में शीर्ष तीन में शामिल हो गए हैं जबकि सिडनी टेस्ट में शानदार शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत ने 21 पायदान की लंबी छलांग लगाकर बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय विकेटकीपरों के पिछले रिकार्ड की बराबरी की। पुजारा ने चार मैचों की श्रृंखला में 521 रन बनाकर भारत की 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

उन्होंने सिडनी में आखिरी मैच में 193 रन बनाए जिससे वह बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पुजारा के अब 881 रेटिंग अंक हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली 922 अंक के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि उनके बाद न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का नंबर आता है। सिडनी में 159 रन की नाबाद पारी खेलने वाले 21 वर्षीय पंत बल्लेबाजी रैंकिंग में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस तरह से उन्होंने भारतीय विकेटकीपरों की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के फारूख इंजीनियर के पिछले रिकार्ड की बराबरी की। इंजीनियर जनवरी 1973 में 17वें नंबर पर काबिज थे।

विश्व रैंकिंग : पंत ने लंबी छलांग लगाकर भारतीय रिकार्ड की बराबरी की

पंत के 673 रेटिंग अंक हैं जो किसी भारतीय विकेटकीपर के सर्वाधिक अंक हैं। रेटिंग अंकों में उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी (662 अंक) का नंबर आता है लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 19 रही है। इंजीनियर के सर्वाधिक अंक 619 रहे हैं। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2019 के स्टार पंत केवल नौ टेस्ट मैच के बाद शीर्ष 20 में शामिल हो गए हैं। आस्ट्रेलिया दौरे से पहले वह 59वें स्थान पर थे। इस श्रृंखला में उन्होंने 350 रन बनाने के अलावा 20 कैच भी लिए। भारत के अन्य बल्लेबाजों में रविंद्र जडेजा छह पायदान ऊपर 57वें और सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पांच पायदान ऊपर 62वें स्थान पर पहुंच गए लेकिन अंजिक्य रहाणे तीन पायदान नीचे 22वें स्थान पर खिसक गए हैं। जडेजा गेंदबाजों और आलराउंडरों की रैंकिंग में भी

एक-एक पायदान आगे बढ़कर क्रमशः पांचवें और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव सात पायदान आगे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 45वीं रैंकिंग पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने आस्ट्रेलिया की पहली पारी में 99 रन देकर पांच विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह 16वें स्थान पर बने हुए हैं जबकि मोहम्मद शमी एक पायदान ऊपर 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चोटिल होने के कारण बाहर होने वाले रविचंद्रन अश्विन नौवें स्थान पर खिसक गए हैं। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस को पहली पारी में 79 रन बनाने का फायदा मिला है और वह 21 स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 69वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में नाथन लियोन एक पायदान ऊपर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच की समाप्ति के बाद जारी इस रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच केपटाउन में खेला गया मैच भी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्कराम पाकिस्तान के खिलाफ केपटाउन में 78 रन की पारी के दम पर फिर से शीर्ष दस में शामिल हो गए हैं। वह बल्लेबाजी रैंकिंग में सात पायदान आगे बढ़कर दसवें स्थान पर काबिज हो गए हैं। तेम्बा वावुमा (पांच पायदान ऊपर 26वें स्थान) पहली बार शीर्ष 30 में शामिल हुए हैं जबकि कप्तान फाफ डु प्लेसिस का छह स्थान का फायदा हुआ है और अब वह 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों में वर्नोन फिलैंडर एक पायदान ऊपर तीसरे जबकि डुआने ओलिवर चार पायदान चढ़कर 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों में असद शाफिक पांच स्थान आगे 24वें जबकि बाबर आजम 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शान मसूद 22 पायदान की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 65वीं जबकि कप्तान सरफराज अहमद 42वें से 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों में शाहीन अफरीदी ने 13 स्थान आगे 60वें नंबर पर पहुंच गए हैं। टीम रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है तथा भारत 116 अंक के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। आस्ट्रेलिया (101) को एक अंक का नुकसान हुआ लेकिन वह पांचवें स्थान पर बरकरार है।

बीसीसीआई ने टीम के सदस्यों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की

नई दिल्ली। बीसीसीआई ने आस्ट्रेलियाई सरजमी पर पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली भारतीय टीम के अंतिम एकादश शामिल सदस्यो के लिए मंगलवार को प्रत्एक मैच के लिए 15 लाख रूपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। टीम को बधाई देते हुए बीसीसीआई ने सभी रिजर्व खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यो के लिए भी नकद पुरस्कार की घोषणा की। यह बोनस राशि मैच मे मिलने वाली फीस के बराबर का होगा जो अंतिम एकादश मे खेलने के लिए प्रत्एक मैच मे 15 लाख रूपए है और मैच के रिजर्व खिलाड़ियों के लिए साढ़े सात लाख रूपए है। सभी कोच को भी 25-25 लाख रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा जबकि कोचिंग नही देने वाले सहयोगी स्टाफ को भी बोनस मिलेगा जो उनके वेतन और पेशेवर फीस के अनुपातिक होगा

PUBLIC NOTICE

Plot No 251, Phase-IV, Sec-57, HSIIDC Industrial Estate Kundli, Distt- Sonipat, Haryana Measuring 450 Sq. Mtrs was allotted by the corporation of Late Sh. Subhash Chander (now deceased) R/o A-3/51, Paschim Vihar, N.D-63 vide regular letter of allotment (RLA) dated 13-12-2004. The Corporation has been informed that the original allottee Late Subhash Chander had expired on 26-12-2017. The legal hairs of the deceased allottee Late Chander Kanta (Wife) Puneet Chandra (Son) & Ruchika Behl (Daughter) have approached the corporation for transfer of share of Subhash Chander in the plot in question in favour of Puneet Chandra in this regard. The corporation is in process of considering their request & transferring the said plot in the favour of Puneet Chandra. Through this public notice it is here by informed that any person have reservation / objection to said transfer may file his/her objection in writing before the undersigned alongwith an affidavit within a period of 30 days from the date of publication of this notice. In case no response is received with in the aforesaid period, it will be presumed that no body has any objection to the transfer of the said share in the plot and the corporation shall go head with transfer of plot in favour of Sh. Puneet Chandra.

Haryana State Industrail And Infrastructure Dev. Corp. Ltd

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार का एक आईडी कार्ड आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड आईडी कार्ड नं 02857 को 8 जनवरी- 2019 को लापता और। या खो दिया गया है।
किसी को भी, जो उक्त आईडी कार्ड पाता है, से अनुरोध किया जाता है कि वह उक्त आईडी कार्ड को मैनेजर डेट सर्विसेज एंड मैनेजमेंट ग्रुप, आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड, एस डी टॉवर रोहिणी सके-08, नई दिल्ली-110085 को लौटा दे।
इसलिए, आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड के सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि उक्त आईडी कार्ड नंबर 02857 रखने वाले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कोई भुगतान न करें।
कृप्या आगे ध्यान दें कि उक्त आईडी कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने वाला व्यक्ति अपनी लागत और जो जोखिम पर ऐसा करेगा और आईसी आईसी आई बैंक किसी भी भुगतान के लिए बाध्य और। या जिम्मेदार नही होगा।

आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड
एसडी
दिनांक : 09/01/2019
स्थान : नई दिल्ली

लोक निर्माण विभाग, ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, कार्यपालक अभियन्ता, दक्षिण भवन (एम-422) लो.नि.वि. पी.टी.एस. मालवीय नगर, नई दिल्ली-17 द्वारा अद्योलिखित कार्यो के निष्पादन हेतु के.लो.नि.वि., एमअएस, बीएसएनएल की उचित सूचि में अनुमोदित एवं अन्य राज्य सरकार जो कि भवन एवं रोड में कार्य कर रहें योग्य अनुभवी ठेकेदारों से ऑनलाइन प्रतिशत दर-मद दर निविदा आमंत्रित की जाती है।

नियासू सं-105/ईई/पीडब्ल्यूडी/दक्षिण भवन (एम) 2018-19 निविदा आईडी संख्या :- 2018_पीडब्ल्यूडी_164910_1 कार्य का नाम:- दीपसार परिसर, सैक्टर, 3, पुष्प विहार, एम.बी. रोड नई दिल्ली-17, में रजिस्टर, पीए कक्ष योग और वी.सी.कक्ष संख्या 403 (प्रयोगशाला) में विभाजन कार्य।
अनुमानित लागत :- रु0 7,69,611/- धरोहर राशि रु0 15,392/- कार्य की निष्पादन अवधि :- 45 दिन टैण्डर को वेबसाईट https:/govtprocurement.delhi.gov.in पर अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय 10/01/2019 15:00 बजे। टैण्डर की खुलने की अन्तिम तिथि व समय 10/01/2019 15:30 बजे।
बिड प्रपत्र एवं अन्य विविरण वेबसाईट https:/govtprocurement.delhi.gov.inसे प्राप्त किया जा सकता है।

DIP/SHABDARTH/2669/18-19

प्रेस सूचना, ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपनिदेशक (उद्यान) मंडल दक्षिण, लो.नि.वि. आर. आर. लाइन ओल्ड बिल्डिंग, रिंग रोड बरार स्कवायर एवं धौला कुआं के बीच नई दिल्ली द्वारा के.लो.नि.वि. में क्रम सं0 1 के लिए Registered Agencies with service of Security Guard for watch and ward, क्र सं0 2 (उद्यान) एवं क्रम से. 3 के लिए उद्यान /सिविल श्रेणी एवं other registered agency from Ministry of Corporate Affairs में सूचीबद्व ठेकेदारों एवं एम.ई.एस., बी.एस.एन.एल. तथा अन्य राज्य सरकार /विभाग के अनुभवी ठेकेदार एवं अन्य अनुभवी ठेकेदार जिनके द्वारा अनुमानित लागत के 3 कार्य 40 प्रतिशत, अथवा अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत तक का कार्य किया गया हो। निम्नलिखित कार्य के लिए ऑन लाईन माध्यम से प्रतिशत दर / आइटम रेट ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. नि.आ.सू.सं.-65/उ.नि.(उ.)/दक्षिण/2018-19 (आई डी सं0 2019_PWD_164955_1) कार्य का नाम:- वर्ष 2018-19 के दौरान उदयान उपमंडल दक्षिण । उदयान मंडल दक्षिण/लोनिवि के अन्तर्गत विभिन्न सडकों पर उदयान कार्य के रखरखाव का कार्य। (उपशीर्ष मंडल कार्यालय की रखवाली के लिए सुरक्षा गार्ड की सेवाएं प्रदान करना)
अनुमानित लागत :- रु0 10,17,928/- धरोहर राशि रु0 20,359/- कार्य सम्पन्न अवधि :- 365 दिन निविदाएं जमा कराने के अंन्तिम तिथि व समय 17/01/2019 को 3:00 बजे।
2. नि.आ.सू.सं.-69/उ.नि.(उ.)/दक्षिण/2017-18 (आई डी सं0 2019_PWD_165002_1) कार्य का नाम:- वर्ष 2018-19 के दौरान उदयान उपमंडल दक्षिण-II/उदयान मंडल दक्षिण/लोनिवि के अन्तर्गत चौधरी ब्रहम प्रकाश इंजीनियरिंग कालेज के उदयान कार्य के विकास का कार्य। (उपशीर्ष: उदयान कार्य)।
अनुमानित लागत :- रु0 10,84,637/- धरोहर राशि रु0 21,693/- कार्य सम्पन्न अवधि :- 455 दिन निविदाएं जमा कराने के अंन्तिम तिथि व समय 17/01/2019 को3:00 बजे।
3. नि.आ.सू.सं.-70/उ.नि.(उ.)/दक्षिण/2018-19 (आई डी सं0 2019_PWD_164960_1) कार्य का नाम:- वर्ष 2018-19 के दौरान उदयान मंडल दक्षिण/लोनिवि के अन्तर्गत उदयान कार्यो का रखरखाव। (उपशीर्ष उपमंडल एवं मंडल कार्यालय के लिए कम्पयूटर ऑपरेटर की सेवाएं प्रदान करना।
अनुमानित लागत :- रु0 9,77,702/- धरोहर राशि रु0 19,554/- कार्य की सम्पन्न अवधि :- 365 दिन निविदाएं जमा कराने के अंन्तिम तिथि व समय 18/01/2019 को 3:00 बजे।

DIP/Shabdarth/2681/18-19

बुमराह को आस्ट्रेलियाई वनडे और न्यूजीलैंड दौरे से विश्राम

एजेंसी, सिडनी। बेहतरीन फार्म में चल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी एकदिवसीय श्रृंखला और उसके बाद के न्यूजीलैंड दौरे से विश्राम दिया गया है और उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। बुमराह ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 21 विकेट लेकर भारत की 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। बीसीसीआई ने बयान में कहा, गेंदबाजो पर कार्यभार को ध्यान में रखते हुए उन्हें आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से पहले पर्याप्त विश्राम देने का फैसला किया गया। मोहम्मद सिराज को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे में उनके स्थान पर टीम में लिया गया है। इसमें कहा गया है, पंजाब के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है। केवल 12 महीने पहले टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बुमराह अब तीनो प्रारूपो मे भारत के मुख्य गेंदबाज बन गए है। बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और इशांत शर्मा की मौजूदगी वाले आक्रमण को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ तेज आक्रमण माना जा रहा है। कप्तान विराट कोहली ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमी पर टेस्ट श्रृंखला मे पहली जीत के बाद तेज गेंदबाजो के कार्यभार को व्यवस्थित करने पर जोर दिया था जिसके बाद बुमराह को विश्राम देने का फैसला किया गया। आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा जिसका पहला मैच शनिवार को खेला जाएगा। इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे मे भारतीय टीम पांच वनडे और तीन टी20 मैचो की श्रृंखला खेलेगी।

विराट और उसकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया: विवियन रिचर्ड्स

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया मे पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को शानदार करार दिया। रिचर्ड्स ने वीडियो संदेश मे कहा, मुझे इस अवसर पर विराट और उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया मे इस तरह के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देनी चाहिए। यह हमेशा मुश्किल होता है लेकिन आप विजेता बनकर निकले। वेस्टइंडीज के 66 साल के इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज बने चेतेश्वर पुजारा की भी तारीफ की। मुझे वह खरा सोना लगा। सबने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम और मेरे दोस्त रवि शास्त्री को बधाई।

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Satyendra Mohan S/o Bachi Ram Bhatt residing at C-225, 2nd floor, Pandav Nagar, Delhi- 110092, have changed my name to Satyendra Mohan Bhatt for all future purposes.

PD(8265)

यूपी ने ली असम पर बढ़त

रिंकू सिंह 96 रन बनाकर शतक की ओर बढ़ रहे

रणजी : पहली पारी की बढ़त 202 रन की

एजेंसी। कानपुर

उत्तर प्रदेश ने तीन खिलाड़ियों के अर्धशतकों से रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मैच के दूसरे दिन पहली पारी में पांच विकेट पर 377 रन बनाकर असम के खिलाफ अपनी बढ़त 202 रन की कर ली। स्टंप उखड़ने तक रिंकू सिंह 96 रन बनाकर शतक की ओर बढ़ रहे हैं और विकेटकीपर बल्लेबाज उपेंद्र यादव 38 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। असम की पहली पारी 175 रन पर सिमट गई थी। टीम ने सुबह एक विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया। मोहम्मद सैफ 12 रन पर खेल रहे थे, उन्होंने इसे अर्धशतक में बदलते हुए 113 गेंद में छह चौके से 58 रन बनाए। कप्तान अक्षदीप नाथ ने भी अर्धशतक बनाया, उन्होंने 143 गेंद में 10 चौके से 81 रन की पारी खेली। प्रियम गर्ग ने 44 रन का योगदान दिया जबकि रिंकू 96 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

त्रिपुरा पर बड़ी जीत से राजस्थान क्वार्टर फाइनल में

अगरतला। राजस्थान ने मंगलवार को यहां मैच के दूसरे दिन ही त्रिपुरा को पारी और 77 रन से करारी शिकस्त दी और ग्रुप सी से शीर्ष पर रहकर शान के साथ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। त्रिपुरा की टीम पहली पारी में केवल 35 रन पर ढेर हो गई जिसके जवाब में राजस्थान ने 218 रन बनाए थे। त्रिपुरा के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी नहीं चल पाए और उसकी पूरी टीम 25.3 ओवर में 106 रन पर सिमट गई। राजस्थान ने इस तरह से बोनस अंक हासिल किया तथा नौ मैचों में 51 अंकों के साथ लीग चरण के अपने अभियान का अंत किया। उसका ग्रुप सी से शीर्ष पर रहना तय है क्योंकि इस ग्रुप से दूसरे नंबर पर चल रहे उत्तर प्रदेश के 38 अंक हैं।

बड़ौदा दो विकेट से जीतकर नाकआउट की दौड़ में

वड़ोदरा। बड़ौदा रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए में कर्नाटक को दो विकेट से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के नाकआउट के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में शामिल है। कर्नाटक हार के बावजूद आठ मैचों में 27 अंक से विदर्भ (सात मैचों में 28 अंक) के बाद दूसरे स्थान पर चल रही जबकि इस मैच से छह अंक हासिल करने वाली बड़ौदा आठ मैचों में 26 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। सुबह दो विकेट पर 13 रन से आगे खेलते हुए कर्नाटक की दूसरी पारी 220 रन पर सिमट गई जिससे बड़ौदा को जीत के लिए 110 रन का लक्ष्य मिला। कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ ने 64 और कप्तान मनीष पांडे ने 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली।

यशपाल की अर्धशतकीय पारी से मणिपुर का संघर्ष जारी

पटना। कप्तान यशपाल शर्मा के नाबाद 84 रन से मणिपुर ने रणजी ट्राफी प्लेट ग्रुप के मैच के दूसरे दिन मंगलवार को यहां दूसरी पारी में सात विकेट पर 217 रन बना लिए। मणिपुर की कुल बढ़त 116 रन की हो गई है और उसके तीन विकेट बचे हैं। यशपाल ने प्रियोजीत सिंह (64) के साथ तीसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर बिहार को परेशानी में डाला। यशपाल ने 142 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके लगाए। बिहार की ओर से कप्तान आशुतोष अमन ने चार जबकि समर कादरी ने तीन विकेट लिए। इससे पहले बिहार ने पांच विकेट पर 107 रन से आगे खेलते हुए पहली पारी में 257 रन बनाए।

सौराष्ट्र 356 रन पर सिमटा, विदर्भ के दो विकेटपर 63 रन

राजकोट। सौराष्ट्र ने निचले क्रम मे धर्मेंद्रसिंह जडेजा की 72 रन की पारी और कमलेश मकवाना के साथ आठवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की बदौलत रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच मे विदर्भ के खिलाफ दूसरे दिन पहली पारी में 356 रन बनाए। स्टंप तक विदर्भ की टीम ने दो विकेट गंवाकर 63 रन बना लिए थे। वसीम जाफर 19 और गणेश सतीश तीन रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे है। विदर्भ की टीम अब भी 293 रन से पीछे है और उसके आठ विकेट बाकी है। सौराष्ट्र ने पांच विकेट पर 218 रन से खेलना शुरू किया। उसने दो विकेट जल्द ही गंवा दिए लेकिन धर्मेंद्रसिंह जडेजा और कमलेश मकवाना ने अच्छी पारियां खेलने मे सफल रहे। इन दोनो ने आठवें विकेट के लिए 112 रन की शतकीय साझेदारी निभाकर टीम को बड़े स्कोर की ओर पहुंचाया। कमलेश हालांकि एक रन से अर्धशतक से चूककर 49 रन बनाकर नाबाद रहे। धर्मेंद्रसिंह ने 113 गेंद मे 12 चौकेसे 72 रन बनाए।

मध्यप्रदेश की नाकआउट में पहुंचने की राह मुश्किल हुई

इंदौर। हरफनमौला गिरिनाथ रेड्डी (29 रन पर छह विकेट) की करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से आंध्र ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच मे मंगलवार को दूसरे दिन मध्यप्रदेश की पहली पारी को 90 रन पर समेट दिया। दिन का खेल खत्म होने तक आंध्र ने दूसरी पारी मे सात विकेट पर 198 रन बना लिए जिससे उनकी कुल बढ़त 239 रन हो गई। मध्यप्रदेश को नाकआउट मे पहुंचने के लिए इस मैच मे जीत दर्ज करना जरूरी है लेकिन पहली पारी मे तीन विकेट पर 24 रन से आगे खेलते हुए टीम 90 रन पर ढेर हो गई। तेज गेंदबाज गिरिनाथ रेड्डी के छह विकेट के अलावा विजय कुमार ने दो तथा केवी शशिकांत और जी मनीष ने एक-एक विकेट लिए। पहली पारी मे 42 रन की बढ़त लेने वाली आंध्र की टीम ने दूसरी पारी मे अच्छी शुरूआत की लेकिन सीआर ज्ञानेश्वर (43) और प्रशांत कुमार (44) की पहले विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी टूटने के बाद पारी लड़खड़ा गई। स्टंप्स के समय करण शिंदे 45 और केवी शशिकांत आठ रन बना कर खेल रहे थे। मध्यप्रदेश के लिए दूसरी पारी मे गौरव यादव, कुलदीप सेन और शुभम शर्मा ने दो-दो विकेट लिए।

युवराज फ्लाप लेकिन अनमोलप्रीत के शतक से पंजाब बड़े स्कोर की ओर

अनमोलप्रीत सिंह

कोलकाता। अनमोलप्रीत सिंह (नाबाद 124) की नाबाद शतकीय पारी से पंजाब ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी के मैच में मंगलवार को दूसरे दिन यहां पहली पारी में सात विकेट पर 357 रन बनाकर बंगाल पर 170 रन की बढ़त कायम कर ली। भारतीय टीम के वापसी की उम्मीद रखने वाले हरफनमौला खिलाड़ी युवराज एक बार फिर नाकाम रहे। उन्होंने ने चार गेंद खेली और सिर्फ एक रन बनाया। अनमोलप्रीत ने 288 गेंद की नाबाद पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। पंजाब ने दिन की शुरूआत दो विकेट के नुकसान पर 47 रन से आगे की। कल के नाबाद बल्लेबाजो शुभमान गिल (91) और अनमोलप्रीत सिंह ने तीसरे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को मुकेश कुमार (89 रन पर चार विकेट) ने शुभमान का विकेट लेकर तोड़ा। शुभमान ने 36 रन से आगे खेलते हुए 119 गेंद मे 91 रन बनाए। उन्होने अपनी पारी मे 11 चौके लगाए। अनमोलप्रीत ने इसके बाद कप्तान मंदीप सिंह (44) ने चौथे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की। मंदीप के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने बाए युवराज सिंह एक रन बनाकर प्रदीप्त प्रमाणिक (100 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर बोल्ड हुए। अनमोलप्रीत को विकेटकीपर गितांश खरे (42) का अच्छा साथ मिला। दोनो ने सातवें विकेट के लिए 80 रन जोड़े। स्टंप्स के समय अनमोलप्रीत के साथ विनय चौधरी 10 रन बनाकर खेल रहे थे। बंगाल के लिए मुकेश ने चार और प्रदीप्त ने तीन विकेट लिए।

तमिलनाडु 432 रन पर सिमटी, दिल्ली ने गंवाए दो विकेट

चेन्नई। तमिलनाडु ने मंगलवार को यहां रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 432 रन बनाकर स्टंप तक दिल्ली के दो विकेट झटक लिए। कुणाल चंदेला के रन आउट होते ही दिन का खेल समाप्त कर दिया, दूसरे छोर पर ध्रुव शोरे खाता भी नही खोल सके थे। शिवम शर्मा सात रन बनाकर आउट हुए, इससे दिल्ली की टीम ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए और वह अब भी 397 रन से पीछे है। सुबह तमिलनाडु ने तीन विकेट पर 215 रन से आगे खेलना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज अभिनव मुकुंद पहले दिन ही शतक बना चुके थे, उन्होने 104 रन की पारी को आगे बढ़ाते हुए 134 रन बनाए। इसके बाद पी रंजन पॉल और एम शाहरूख खान ने मिलकर छठे विकेट के लिए 82 रन की भागीदारी निभाते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। रंजन पॉल ने 129 गेंद खेलते हुए 12 चौके और एक छक्के से 78 रन की पारी खेली। वही शाहरूख खान ने 55 रन बनाए जिसके लिए उन्होने 139 गेंद का सामना किया जिसमे चार चौके और एक छक्का जड़ा था। दिल्ली के गेंदबाजो मे विकास मिश्रा सबसे सफल रहे जिन्होने पांच विकेट हासिल किए जबकि शिवम शर्मा भी चार विकेट झटकने मे कामयाब रहे।

रेलवे ने महाराष्ट्र को पारी से हराया

नई दिल्ली। बाएं हाथ के स्पिनरो अविनाश यादव (71 रन पर पांच विकेट) और हर्ष त्यागी (29 रन पर चार विकेट) की फिरकी के जादू से रेलवे ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच मे मंगलवार को दूसरे दिन यहां यहां महाराष्ट्र की दूसरी परी 131 रन पर समेट कर पारी और 58 रन से जीत दर्ज की। पहली पारी मे 70 रन पर आउट होने वाली महाराष्ट्र की टीम के लिए सत्यजीत बाचव ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। महाराष्ट्र के बल्लेबाजो के पास अविनाश और हर्ष की स्पिन गेंदबाजी का कई जवाब नही था और पूरी टीम दूसरी पारी मे मात्र 39.1 ओवर ही खेल सकी। अविनाश ने पहली पारी मे भी चार विकेट लिए थे। रेलवे ने इससे पहले दिन की शुरूआत नौ विकेट पर 184 रन से की। कप्तान महेश रावत ने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने हुए अनुरीत सिंह के साथ दसवे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की जिससे टीम ने 259 रन बनाकर 189 रन की बढ़त कायम की। अनुरीत 36 रन पर नाबाद रहे जबकि मैन ऑफ द मैच रावत ने 52 रन से आगे खेलते हुए 89 रन बनाए। महाराष्ट्र की ओर से बाचव ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 108 रन देकर आठ विकेट लिए। रेलवे को इस जीत से सात अंक मिले लेकिन दोनो टीमें पहले ही नाकआउट चरण से बाहर हो चुकी है।

राहुल का नाबाद शतक, केरल के पांच विकेट पर 219 रन

नादौन। केरल ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश को 297 रन पर समेटने के बाद सलामी बल्लेबाज पोन्नम राहुल के नाबाद शतक से स्टंप तक पहली पारी मे पांच विकेट पर 219 रन बना लिए। राहुल 195 गेंद मे 13 चौके और एक छक्के की मदद से 103 रन बनाकर क्रीज पर डटे है जबकि दूसरे छोर पर संजू सैमसन 32 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे है। हिमाचल प्रदेश ने सुबह सात विकेट पर 257 रन से आगे खेलना शुरू किया। अंकित कलसी 89 रन पर खेल रहे थे और मंगलवार को शतक पूरा किया। लेकिन 101 रन पर आउट हो गए, इसके लिए उन्होने 202 गेंद खेली जिसमें 12 चौके जड़े थे। एम डी नीधिश ने 24 ओवर मे 88 रन देकर छह विकेट हासिल किए जबकि बासिल थम्पी और संदीप वारियर को दो दो विकेट मिले।

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम: नामालूम, पुत्र: नामालूम, पता: नामालूम, उम्र: लगभग 42 वर्ष, कद: 5'3" फीट, रंग: सांवला, पहनावा: सफेद रंग की चैकदार कमीज, काले रंग की जैकेट और स्लेटी रंग की लाइनदार पैन्ट। जो दिनांक 24.12.2018 को ट्रक मार्केट इन्डस्ट्रियल एरिया, मंगोलपुरी, दिल्ली के पास से बेहोशी की अवस्था में पाया गया। जिसे संजय गांधी अस्पताल, दिल्ली में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान 25.12.2018 को डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके संदर्भ में DD No. 14-B दिनांक 25.12.2018 से थाना मंगोलपुरी, दिल्ली में दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वह तुरन्त अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

थानाध्यक्ष
थाना मंगोलपुरी, दिल्ली
फोन न.: 011-27922186, 27921168
DP/1775/OD/19

गुमशुदा की तलाश

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की (फोटो में दर्शाई गई) जिसका नाम **मीरा,** पुत्री विजय, पता एस.आर.एस.-137, मुलचंद का मकान, पीरागढ़ी गाँव, नई दिल्ली जो दिनांक 11.02.2015 से लापता है। इस संदर्भ में एफ.आई.आर. नं. 108/15, भा.द.सं. की धारा 363 के अन्तर्गत, दिनांक 13.02.2015 थाना पश्चिम विहार वेस्ट, दिल्ली में दर्ज है।
जिसका हुलिया नीचे दिया गया है:
उम्र: 15 साल, **रंग:** साफ, **कद:** 5'0", **चेहरा:** गोल, **पहनावा:** जिसने लाल रंग की जैकेट और हरे रंग की जींस की पैंट पहन रखी है।
अगर किसी को इस गुमशुदा लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।
वेब साईट: http://cbi.nic.in
ई-मेल: cic@cbi.gov.in
फैक्स: 011-24368639
फोन नं.: 011-24368638, 24368641

थानाध्यक्ष
थाना पश्चिम विहार वेस्ट, दिल्ली
फोन नं.: 011-25268394, 25280980
DP/1765/OD/19

ICICI Bank
ICICI Bank Limited

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पाड्रा रोड, वडोदरा, गुजरात-390 007
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू). मुंबई-400 051
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., द्वितीय तल, वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान, नई दिल्ली-110 055

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-नीलामी

[नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, "जैसी है जहां है", जैसी है जो भी है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी ;

क्र. सं. (क)	कर्जदार (रों)/सह-कर्जदारों/गारंटरों का नाम/ऋण खाता संख्या (ख)	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई (ग)	बकाया राशि (रू. में) (घ)	सुरक्षित मूल्य (रू. में) (ङ)	धरोहर राशि जमा (रू. में) (च)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (छ)	नीलामी की तिथि एवं समय (ज)
1.	श्री गुरिन्दर सिंह साहनी, (कर्जदार) राजिन्दर कौर, जोत इम्पेक्स प्रा. लि. (सह-कर्जदार) (एलबीजीयूआर00002380237) (एलबीडीइएल00002382381)	डीपीटी 632, छठा तल, प्राइम टावर प्लॉट 79 एवं 80, ओखला फेज-1, नई दिल्ली- 110020 तथा परिमाप क्षेत्रफल 801 वर्ग फीट कार्पेट एरिया - 485वर्ग फीट	रू. 10,256,466/- (28 दिसम्बर, 2018 को)	रू. 85,00,000/- (रूपए पिचासी लाख)	रू. 8,50,000/-	15 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक	31 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से
2.	श्री गुरिन्दर सिंह साहनी, राजिन्दर कौर, जोत इम्पेक्स प्रा. लि. (सह-कर्जदार) (एलबीडीईएल00002352373/एलबीजीयूआर00002380239)	डीपीटी 633, छठा तल, प्राइम टावर प्लॉट 79 एवं 80, ओखला फेज-1, नई दिल्ली- 110020 तथा परिमाप क्षेत्रफल 759 वर्ग फीट कार्पेट एरिया - 475वर्ग फीट	रू. 10,734,730/- (28 दिसम्बर, 2018 को)	रू. 83,00,000/- (रूपए पिचासी लाख)	रू. 8,30,000/-	15 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक	31 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से

ऑनलाइन नीलामी नीलामी एजेन्सी "श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड" (यूआरएल लिंक - "https://eauctions.samil.in") की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी। बंधकदाताओं/सूचनाप्रेषिती को 30 जनवरी, 2019 को अप. 5.00 बजे से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। संभावित बिडर (बिडर्स) को अपनी ऑफर उपरोक्त धरोहर राशि जमा (कालम च में वर्णितानुसार) सहित एक मोहरबंद लिफाफे में "सम्पत्ति के क्रय हेतु ऑफर" शीर्षांकित कर इस प्रकार प्रस्तुत करें कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, वीडियोकॉन टावर, ब्लॉक ई-1, झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 में अथवा हमारे मार्केटिंग एजेन्ट श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के द्वितीय तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 स्थित कार्यालय में 30 जनवरी, 2019 को अथवा पूर्व अप. 5.00 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। मार्केटिंग एजेन्सी को नीलामी के सम्यक् संचालन के लिए नीलामकार के रूप में भी अनुबंधित किया गया है। ईएमडी डीडी/पीओ राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड" के पक्ष में तथा दिल्ली में देय होना चाहिए।
निरीक्षण, नीलामी के निबंधन और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के मोबाइल नम्बर 8584874809/9650193259 पर अथवा श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के 9910453434 पर सम्पर्क करें।
केवल बैंक/ई-नीलामी विक्रेता पदाधिकारी द्वारा अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त और पंजीकृत की गई निविदाएं ही नीलामी हेतु मान्य होंगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की वेबसाइट देखें: https://www.icicibank.com/notice-board/properties-for-sale/properties.page?

तिथि : 09 जनवरी, 2019
स्थान : दिल्ली/एनसीआर

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

पायनियर
नई दिल्ली , बुधवार, 9 जनवरी, 2019

डकार रैली के पहले चरण में मेना को 14वां और संतोष को 20वां स्थान

पिस्को। स्पेन के ओरियोल मेना और हीरो मोटोस्पोर्ट्स के उनके साथी सीएस संतोष डकार रैली के पहले चरण के बाद क्रमशः 14वें और 20वें स्थान पर रहे। पहले चरण में होंडा फैक्ट्री रेसिंग के जॉन बैरेडाबोर्ट 57 मिनट 36 सेकेंड के साथ शीर्ष पर रहे। संतोष उनसे नौ मिनट 13 सेकेंड पीछे रहे। हीरो मोटोस्पोर्ट्स के ही जोकिम रोड्रिग्स चोटी के राइडर से दस मिनट 14 सेकेंड पीछे रहे। वह पहले चरण के बाद 23वें स्थान पर रहे। पहले ड्यून में कुछ परेशानी झेलने के बावजूद मेना ने अच्छा प्रदर्शन किया और 14वें स्थान पर रहे। डकार रैली में भाग ले रहे एक अन्य भारतीय टीवीएस रेसिंग के प्रभाकर अरविंद पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन नही कर पाए और 70वें स्थान पर रहे।

आस्ट्रेलियाई सरदाना को मुंबई शतरंज का खिताब

मुंबई। आस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय मास्टर ऋषि सरदाना ने सोमवार की रात यहां चौथे मुंबई अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। सरदाना ने नौवें और अंतिम दौर में भारत के अंतरराष्ट्रीय मास्टर एआई मुथैया को हराया। भारतीय मूल के 22 वर्षीय आस्ट्रेलिया के कुल सात अंक रहे। वियतनाम के ग्रैंडमास्टर ट्रान तुआन मिन, भारत के ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु पुराणिक और युवा अंतरराष्ट्रीय मास्टर डी गुकेश के भी सात सात अंक रहे लेकिन सरदाना को बेहतर टाईब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता घोषित किया गया। टाईब्रेक स्कोर के आधार पर तुआन मिन दूसरे, पुराणिक तीसरे और गुकेश चौथे स्थान पर रहे।

केन्द्रीय सचिवालय, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र की जीत

चेन्नई। केन्द्रीय सचिवालय ने शानदार फार्म जारी रखते हुए नौवीं हाकी इंडिया सीनियर पुरूष चैम्पियनशिप 2019 (बी डिवीजन) के मैच में मंगलवार को यहां हाकी मध्य प्रदेश को हराकर पूल सी में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पिछले मैच में हाकी गुजरात को 20-0 से पराजित करने वाली दिल्ली की केंद्रीय सचिवालय की टीम ने हाकी मध्य प्रदेश को 2-0 से हराया। उनके लिए धरमवीर यादव और प्रदीप मोर ने गोल किए। पूल सी के अन्य मैच में हाकी गुजरात ने हाकी मिजोरम को 3-2 से मात दी। मध्य प्रदेश हाकी अकादमी ने पूल ए के मैच में तेलंगाना हाकी को 10-। के बड़े अंतर से हराया। ग्रुप के दिन के दूसरे मैच में हाकी महाराष्ट्र ने हाकी बिहार को 10-0 से शिकस्त दी। हाकी झारखंड ने पूल बी के मुकाबले में मणिपुर हाकी को 2-0 से हराया। पूल डी में बेंगलुरू हाकी संघ और छत्तीसगढ़ हाकी के बीच खेला गया करीबी मुकाबला 3-3 से ड्रा रहा।

कुलदीप विश्व कप के लिए पहली पसंद के स्पिनर होंगे: शास्त्री

एजेंसी। नई दिल्ली

कोच रवि शास्त्री को लगता कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव का आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पदार्पण टेस्ट में शानदार प्रदर्शन उन्हें इंग्लैंड में होने वाले आगामी विश्व कप में वह अंतिम एकादश में चयन के लिए पहली पसंद का स्पिनर बनाता है।

कुलदीप ने सिडनी में आस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रा हुए चौथे टेस्ट की पहली पारी में पांच विकेट हासिल किए और भारतीय कोच ने कलाई के इस स्पिनर की तारीफों के पुल बांधे। शास्त्री ने इंडिया टुडे टीवी चैनल से कहा, कुलदीप इससे विश्व कप के लिए खिलाड़ियों की जमात में आ गया। वह शायद विश्व कप में खेलने वाली हर भारतीय अंतिम एकादश में शामिल हो सकता है क्योंकि उसे कलाई से स्पिन करने का फायदा मिलेगा। हमें शायद अन्य दो अंगुली के स्पिनरों के बीच चुनने की जरूरत होगी क्योंकि कलाई का यह स्पिनर अब प्राथमिकता सूची में है। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी 350 रन बनाकर प्रभावित किया और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर है। हालांकि उन्हें आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वनडे के लिए चुनी गई टीम में शामिल नहीं है। शास्त्री ने कहा कि पंत को मैच फिनिश करने की कला सीखने का विशेष काम दिया गया है जो विश्व कप के दौरान भारत के लिए काफी अहम होगा। शास्त्री ने कहा, हमने उसे इसलिए वापस जाने को कहा क्योंकि वह लगातार क्रिकेट खेल रहा है। मुझे लगता है कि उसे दो हफ्तों के लिए ब्रेक की जरूरत है और फिर वह भारत ए टीम से जुड़ेगा।

न्यूजीलैंड ने किया श्रीलंका का सूपड़ा साफ

● टेलर और निकोल्स के शतक

एजेंसी। नेल्सन

अनुभवी बल्लेबाज रोस टेलर (137) और हेनरी निकोल्स (नाबाद 124) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 154 रन की साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने तीसरे एकदिवसीय मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को 115 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। टास हार कर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में चार विकेट पर 364 रन बनाए जो नेल्सन के सैक्सटन ओवल मैदान में नया रिकार्ड है।

श्रीलंका की टीम 41.4 ओवर में 249 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की शुरूआत अच्छी नहीं रही और पांचवें ओवर तक में टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो का विकेट गंवा दिया। यह दोनों विकेट श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा (93 रन पर तीन विकेट) ने लिए। इसके बाद कप्तान केन विलियमसन (55) ने टेलर के साथ तीसरे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। विलियमसन के आउट होने के बाद टेलर और निकोल्स ने आतिशी बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। टेलर ने 131 गेंद की पारी में नौ चौके और चार छक्के लगाए।

यूपी की पुरुष टीम को टेटे में कांस्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गत दिनों कटक में हुई सीनियर नेशनल एंड अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में यूपी को गुजरात से 3-1 से हार के चलते कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यूपी की टीम ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में पिछली बार की रजत पदक विजेता हरियाणा को कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। इससे पहले यूपी ने पदक के प्रबल दावेदार पश्चिम बंगाल को 3-2 से हराते हुए अंतिम आठ में जगह बनाई थी। यूपी टेबल टेनिस संघ के सचिव अरुण बनर्जी ने बताया कि यूपी ने इससे पहले 2000 में लखनऊ में हुई राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। उससे पहले यूपी की पुरुष टीम ने गांधीधाम में 1976 में हुई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने बताया कि यूपी टीम ने इस कैलेंडर वर्ष में सब जूनियर युगल में कांस्य, जूनियर बालिका टीम ने रजत, यूथ बालक टीम ने कांस्य और अब पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता।

फुटबाल ट्रायल 16 से

लखनऊ। जम्मू एंड कश्मीर में 11 से 16 फरवरी तक होने वाली संतोष ट्राफी (नार्थ जोन) के लिए उत्तर प्रदेश की टीम का चयन-ट्रायल 16 और जनवरी को आगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश फुटबाल संघ के संयुक्त सचिव मो. शाहिद ने दी।

स्मिथ, वार्नर की वापसी पर सब कुछ अच्छा होने की सोच आस्ट्रेलिया का खुद के साथ मजाक : वान

सिडनी। इंग्लैड के पूर्व कप्तान माइकल वान का मानना है कि भारत के हाथो पहली बार घरेलू टेस्ट श्रृंखला गंवाने वाले आस्ट्रेलिया को अगर यह लगता है कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यह उसका खुद के साथ मजाक होगा।

भारत की जीत के बाद वान ने डेली टेलीग्राफ मे अपने कालम मे लिखा कि आस्ट्रेलिया निलंबित स्मिथ और वार्नर की अनुपस्थिति के बजाय कई अन्य गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। अगर आप यह सोचते हो कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के चयन के लिए उपलब्ध होने के तुरंत बाद आस्ट्रेलिया की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर आप गलत है। भारत के खिलाफ उसकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, चयन और रणनीति सभी बेकार रही और आस्ट्रेलिया को स्वीकार करना होगा कि उसकी टीम अब बहुत अच्छी नही है। यह सही है कि अपने दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बाहर होने से कोई भी टीम संघर्ष करेगी लेकिन स्मिथ और वार्नर को गंवाना कमियो को छुपाने का बहाना नही है। वान को लगता है कि वर्तमान परिस्थिति मे आस्ट्रेलिया विश्व कप 2019 के बाद होने वाली एशेज श्रृंखला मे इंग्लैड को नही हरा पाएगा। उनकी बल्लेबाजी तकनीक बेहतर होनी चाहिए और गेंदबाजी में अधिक निरंतरता की जरूरत है। उनकी टेस्ट टीम को हर विभाग मे सुधार की जरूरत है। अगर वे सोचते है कि स्मिथ और वार्नर की वापसी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वे खुद से मजाक कर रहे है।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण जितेन्द्र कुमार जग्गी एवं उनकी पत्नी विनिता जग्गी निवासीगण 169–ए, पॉकेट–जे एण्ड के, दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095 ने अपने पुत्र अमन जग्गी को उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखलकर संबंध विच्छेदकर लिये हैं, भविष्य में उसके किसी भी कृत्य हेतु मेरे मुवक्किलगण जिम्मेदार नहीं होंगे।

मोहित बसंल (अधिवक्ता)
चैम्बर नं0 जी–414, तृतीय तल,
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

Public Notice

To be known to all that I, Omwati W/o Shri Desh Raj R/o House No.31, Lord Budha Appartment, Paschim Vihar, New Delhi, Lost Documents In Respect Of **DDA LIG Flat No. 48-C,Second Floor,AT Madipur, Rohtak Road,Delhi,Vide DDA File No.L012(107)/84/MP/NP**,has applied for conversion of the aforesaid FLAT from lease hold to free hold in DDA.The original document**(1)SITE POSSESSION (2)NOC(water and electric)** of the above flat have been lost. An FIR to this effect has been lodged in Police Station, New Delhi,vide NCR No.**128025/2019,DATED 08/01/2019.**Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above address/Phone No 9667054622 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director LAB(H)DDA,Vikas Sadan, INA, New Delhi.

वरुण शतकीय पारी, ध्रुव स्पोर्ट्स की बड़ी जीत

लखनऊ। वरुण प्रताप सिंह के नाबाद शतकीय पारी की बदौलत ध्रुव स्पोर्ट्स प्रमोशन ने बीबीडी डी डिवीजन लीग क्रिकेट में कल्याणपुर स्ट्राइकर्स को 187 रनों से पराजित कर दिया। डीएवी ग्राउंड में ध्रुव स्पोर्ट्स प्रमोशन ने पहले बैटिंग करके 40 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए। वरुण प्रताप सिंह ने 115 गेंदों में 18 चौके की मदद से नाबाद 141 रन बनाए। इसके अलावा अश्विनी गुप्ता ने 54 रन का योगदान दिया। अंश आर्या ने 52 रन देकर दो विकेट लिए। जवाब में कल्याणपुर स्ट्राइकर्स 29.5 ओवर में केवल 70 रन बनाकर आल आउट हो गयी। उत्सव पांडेय ने सर्वाधिक 13 रन बनाए। सुजल तिवारी ने 17 रन देकर तीन, अंशुमान सिंह ने आठ रन देकर तीन और अंकित कुमार ने 18 रन देकर तीन विकेट लिए। अखिलेश दास स्टेडियम में डी डिवीजन के दूसरे मैच में अन्नपूर्णा क्रिकेट क्लब ने यूपी रेंजर्स क्रिकेट क्लब को 68 रनों से हराया। अन्नपूर्णा क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करके 24.4 ओवर में 130 रन बनाए। अभिषेक सिंह ने 38 रन बनाए। नितिन यादव ने चार और हरेन्द्र भारद्वाज ने तीन विकेट लिए। जवाब में यूपी रेंजर्स क्रिकेट क्लब की टीम 19.5 ओवर में केवल 62 रन बनाकर आल आउट हो गयी। नितिन यादव ने सबसे ज्यादा 14 रन बनाए। अजीत सिंह और अभय सिंह ने तीन-तीन विकेट प्राप्त किए। दो विकेट चंदन मौलिक ने लिए। चौक स्टेडियम में बी डिवीजन के मैच में डीवाईए ने अवध स्काई स्पोर्ट्स क्लब को 10 विकेट से हराया। अवध स्काई ने पहले बल्लेबाजी करके 26 ओवर में 73 रन बनाए। जवाब में डीवाईए ने 14 ओवर में बगैर कोई नुकसान के 75 रन बनाकर 10 विकेट से जीत हासिल की।

पीडब्ल्यूएल युवा पहलवानों के लिए बेहतर मंच : बजरंग

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदकधारी बजरंग पूनिया ने मंगलवार को कहा कि आगामी प्रो कुश्ती लीग युवा भारतीय पहलवानों को अंतरराष्ट्रीय पहलवानों से सीखने का बेहतर मंच मुहैया कराएगी। पीडब्ल्यूएल का चौथा चरण 14 से 31 जनवरी से शुरू होगा जिसमें विजेता टीम को 1.9 करोड़ रुपए और उप विजेता को 1.1 करोड़ रुपए की राशि की ईनामी राशि मिलेगी।

AXIS BANK

खुदरा आस्ति केन्द्र, दिल्ली : लोअर ग्राउण्ड फ्लोर तथा अपर ग्राउण्ड फ्लोर, हिमालय हाउस, के.जी. मार्ग, दिल्ली–110001 अन्य पता : ऐक्सिस बैंक लि., ऐक्सिस हाउस, टावर टी–2, द्वितीय तल, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)–201301खुदरा आस्ति केन्द्र, गाजियाबाद : बीएफ–1ए, 2, 3, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेंटर, नीति खंड–1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201012 खुदरा आस्ति केन्द्र, फरीदाबाद : ऐक्सिस बैंक लि., एससीओ–8, हुडा शॉपिंग सेंटर, सेक्टर–16, फरीदाबाद, हरियाणा–121002 खुदरा आस्ति केन्द्र, गुरूग्राम : ऐक्सिस बैंक लि., एएससी गुरूग्राम , एसजी–107, डीएलएफ गैलेरिया कॉम्प्लेक्स, निकट डाक घर, डीएलएफ सिटी फेज–4, गुरूग्राम–122009 कार्पोरेट कार्यालय : ऐक्सिस हाउस, ब्लॉक–बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुंबई–400025 पंजीकृत कार्यालय : "त्रिशूल", तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत कब्जा सूचना

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने, ऐक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/ बंधकदाता(ओं) से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) तथा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।
कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐक्सिस बैंक की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।
कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का वर्णन	
1. श्री रजनीश सिंह कार्की पुत्र श्री जोहर सिंह कार्की स्वामी मैसर्स रजनीश कार्की ऐंड एसोसिएट्स, प्लॉट नबर 23, ब्लॉक नंबर एल–1/13, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली (कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता) अन्य पता : श्री रजनीश सिंह कार्की सी/ओ मैसर्स रजनीश कार्की ऐंड एसोसिएट्स (एक स्ट्रैटजी ऐंड ऑर्गनाइजेशन डिजाइन बुटीक)एल–1/13, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली–110016 अन्य पता : श्री रजनीश सिंह कार्की , बी–102, ग्लेन गेट, हीरानंदानी गार्डन्स, पोवाई, मुंबई–400076 2. श्रीमती मनीषा रजनीश कार्की, पत्नी निवासी प्लॉट नंबर –13, एल–1/13, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली–110016 अन्य पता : श्रीमती मनीषा रजनीश कार्की, बी–102, ग्लेन गेट, हीरानंदानी गार्डन्स, पोवाई, मुंबई–400076	आवासीय मकान परिमाप 625 वर्ग गज (522.57 वर्ग मीटर) सम्पत्ति सं. 13, ब्लॉक, एल–1, सम्पूर्ण भू तल, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : प्लॉट नबर एल–1/14, 15 एवं 16 पश्चिम : एल–1/5 एवं 6, उत्तर : रोड, दक्षिण : एल–1/4.	
	मांग सूचना की तिथि	29–अगस्त–2018
	कब्जा की तिथि	5–जन–2019
	मांग सूचना में राशि (रू.)	29–अगस्त–2018 तक रू. 10,75,257/– एसएमई ओडी एवं रू. 26,109,068/– गृह ऋण कुल बकाया राशि रू. 2,71,84,325/– + भावी ब्याज, अनुषंगी खर्च एवं लागत

एतद्द्वारा उपरि–वर्णित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर करने की सूचना दी जाती है, अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर, बंधक सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
दिनांकित : 09–जनवरी–2019, हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली ऐक्सिस बैंक लिमिटेड

ICICI Bank
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पाड्रा रोड, वडोदरा, गुजरात–390 007
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू). मुंबई–400 051
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., द्वितीय तल, वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान, नई दिल्ली–110 055

सार्वजनिक सूचना – प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा–सह–नीलामी

[नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, "जैसी है जहां है", जैसी है जो भी है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी;

क्र. सं. (क)	कर्जदार (रों)/सह–कर्जदारों /गारंटरों का नाम/ऋण खाता संख्या (ख)	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई (ग)	बकाया राशि (रू. में) (घ)	सुरक्षित मूल्य (रू. में) (ङ)	धरोहर राशि जमा (रू. में) (च)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (छ)	नीलामी की तिथि एवं समय (ज)
1.	एन्सोल पावर प्राइवेट लिमिटेड (एलबीडीईएल00002007805, एलबीडीईएल00002021341)	सम्पूर्ण प्रथम तल फ्लैट, छत का अधिकार नहीं, प्लॉट नंबर 07, ब्लॉक डी, आवासीय कालोनी लेकवुड सिटी, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद परिमाप – 180.39 वर्ग मीटर	रू. 2,39,73,841/– (2 जनवरी, 2019 को)	रू. 1,35,00, 000/–	रू. 13,50, 000/–	21 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक	31 जनवरी, 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक
2.	सचिन मित्तल (कर्जदार)/ श्रुति मित्तल (सह–कर्जदार) एलबीएफडीबी00001841651, एलबीएनओडी00001601582, एलबीएनओडी00001751857, एनएचएनओडी00000728878)	डीटीजे 104 (प्रथम तल) टावर बी, डीएलएफ टावर, डीएलएफ गैलेरिया, जासोला, नई दिल्ली–110025 परिमाप कवर्ड एरिया – 1317 वर्ग फीट	रू. 2,45,55,120/– (19 दिसम्बर, 2018 को)	रू. 2,12,60, 000/–	रू. 21,26, 000/–	21 जनवरी, 2019 को अप. 2.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक	31 जनवरी, 2019 को अप. 1.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी नीलामी एजेन्सी श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड (यूआरएल लिंक – षिजजचेरूध्ध्वतवचमतजलर्ेउपसण्पदष्) की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी। बंधकदाताओं/सूचनाप्रेषिती को 30 जनवरी, 2019 को अप. 5.00 बजे से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
संभावित बिडर (बिडर्स) को अपनी ऑफर उपरोक्त धरोहर राशि जमा (कालम च में वर्णितानुसार) सहित एक मोहरबंद लिफाफे में "सम्पत्ति के क्रय हेतु ऑफर" शीर्षांकित कर इस प्रकार प्रस्तुत करें कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, वीडियोकॉन टावर, ब्लॉक ई–1, झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 में अथवा हमारे मार्केटिंग एजेन्ट श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के द्वितीय तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 स्थित कार्यालय में 30 जनवरी, 2019 को अथवा पूर्व अप. 5.00 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। मार्केटिंग एजेन्सी को नीलामी के सम्यक् संचालन के लिए नीलामकार के रूप में भी अनुबंधित किया गया है। ईएमडी डीडी/पीओ राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड" के पक्ष में तथा दिल्ली में देय होना चाहिए।
निरीक्षण, नीलामी के निबंधन और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के मोबाइल नम्बर 8584874809/9650193259 पर अथवा श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के 9910453434 पर सम्पर्क करें। केवल बैंक/ई–नीलामी विक्रेता पदाधिकारी द्वारा अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त और पंजीकृत की गई निविदाएं ही नीलामी हेतु मान्य होंगी।
प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की वेबसाइट देखें: https://www.icicibank.com/notice-board/properties-for-sale/properties.page?
हस्ता./–
तिथि : 09 जनवरी, 2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली/एनसीआर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

नाकामी भूल आगे बढ़ने को तैयार जिमनास्ट अनस

● खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी में जुटे

पुणे। मोहम्मद अनस बेहद दबाव में अपनी काबिलियत के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन न करने से निश्चित निराश होते हैं लेकिन वह हमेशा आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। कोल्ड वायरस में डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाई लेने के बाद अनस मुश्किल में फंस गए थे लेकिन इससे बच भी गए। वह अब इस बात को साबित करने को बेताब हैं कि वह देश के सर्वश्रेष्ठ युवा जिमनास्ट हैं। पिछले साल दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में अनस ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स से पहले एक बार फिर उन्हें ब्वॉएज अंडर-21 में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। स्टैंड्स से वह अपनी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश की अंडर-17 टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। वह इस बात को जानकर बेहद दबाव में थे कि उनसे सभी को ब्यूनस आयर्स में होने वाले यूथ ओलम्पिक में उनके क्वालीफाई करने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि परिणामस्वरुप मैं जकार्ता में खेली गई एशियन जूनियर चैम्पियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सका था। वॉल्ट में मैंने 13,000 अंक लिए थे लेकिन मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक नहीं खेल सका था। अनस ने कहा कि वह अब उस असफलता को पीछे छोड़ चुके हैं। बकौल अनसए ष्मैंने सीख लिया है और अब मैं अपना ध्यान सिर्फ खेल में सुधार करने की प्रक्रिया पर लगाऊंगा और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करूंगा। मुझे इस बात से भी आत्मविश्वास मिला जब अनुशासन समिति ने कहा कि मैंने डॉक्टर की सलाह पर दवाई ली थी और इस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वह अब किसी भी तरह की दवाई लेने से पहले काफी सावधान रहते हैं और अपने अनुभव के बारे में बिना हिचके साथी जिमनास्टों से बातें करते हैं। एक दबाव भरे समय से बाहर आकर अपने आप को श्री शिव छत्रपति स्पोटर्स कॉम्पलेक्स के हॉल में अपनी बात रखनाए इसके लिए मानसिक तौर पर काफी मजबूती की जरूरत है। अनस ने कहा कि वह पहले से ज्यादा तैयार हैंए ष्नेशनल स्पोटर्स अकादमीए जहां मैं तैयारी करता हूंए मेरे प्रशिक्षकोंए मेरे माता.पिता और हर उस इंसान का जो मुझमें विश्वास करता हैए का शुक्रगुजार हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा यह मेरे लिए 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी का मंच है।

क्रास कंट्री के लिए यूपी टीम घोषित

लखनऊ। मथुरा में 20 जनवरी को होने वाली नेशनल क्रास कंट्री चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम घोषित कर दी गयी है। यूपी एथलेटिक्स एसो. के सचिव पीके श्रीवास्तव के अनुसार इसी चैंपियनशि के आधार पर अंतराष्ट्रीय क्रास कंट्री चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन किया जाएगा। पुरुष(10 किमी): अमरजीत सिंह, संजय पटेल, सुनील कुमार यादव, दीप नारायण, वीरेन्द्र कुमार वर्मा, राजा किशोर रावत। पुरुष अंडर-20 (8 किमी): श्याम, मुकेश यादव, नितीश कुमार, राकेश यादव, दिनेश कुमार। पुरुष अंडर-18 (6 किमी): मनीष कुमार, चंदन भारद्वाज। महिला (10 किमी): पूनम सिंह, स्मृति, सुमन सिंह, रीमा पटेल, ज्योति सिंह, हेमलता शर्मा। महिला अंडर-20 (6 किमी): काजल पासवान, वंदना, पूजा वर्मा, शिखा गुप्ता, रंजना पटेल, शीलू। लड़की अंडर-18 (4 किमी): अमृता पटेल। लड़की अंडर-16 (2 किमी): अंतिमा पाल, पुष्पा यादव। मैनेजर: जय सिंह चौहान, कृष्ण कुमार यादव। कोच: विभा, संजीव कुमार।

ताइक्वांडो में जीते दो स्वर्ण

लखनऊ। गत दो से छह जनवरी तक विदिशा (मध्य प्रदेश)में सम्पन्न 64वें एसजीएफआई नेशनल खेलों में साई सेंटर लखनऊ की ताइक्वांडो की प्रशिक्षु पूजा राघव ने दो स्वर्ण पदक जीते। पूजा को यह सफलता अंडर-19 (40 किग्रा) और अंडर-17 (42 किग्रा) में मिली। इसके अलावा साई की ही अंजलि ने अंडर-19 (42 किग्रा) वर्ग में कांस्य पदक जीता।

आर्यावर्त ने सेंट्रल अकादमी को 122 रनों से दी शिकस्त

लखनऊ। आर्यावर्त अकादमी ने सेंट्रल अकादमी को 122 रनों से शिकस्त देकर फूलमती स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट मे पूरे अंक हासिल किए। आर्यावर्त ग्राउंड में खेले गए लीग मैच में आर्यावर्त अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करके 40 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। विनीत सिंह ने 107 गेंदों में 17 चौके व दो छक्के की सहायता से 121 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसके अलावा निशांत सिंह ने 68 रन बनाए। यश साहनी ने 61 रन देकर तीन विकेट प्राप्त किए। जवाब में सेंट्रल अकादमी की टीम 29.3 ओवर में 172 रन बनाकर आल आउट हो गयी। यश साहनी ने सर्वाधिक 61 रन का योगदान दिया। अजय पाल ने 43 रन देकर पांच विकेट चटकाए। एनईआर स्टेडियम में खेले गए दूसरे लीग मैच में लाइफ केयर ने आईपीआरके को चार विकेट से मात दी। आईपीआरके ने पहले बल्लेबाजी करके 21 ओवर में 53 रन बनाए। जवाब में लाइफ केयर ने 10.4 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाकर मैच जीत लिया। माइक्रोलिट ग्राउंड में खेले गए तहसरे लीग मैच में डिवाइन क्रिकेट अकादमी ने पैंथर क्रिकेट अकादमी को दो विकेट से पराजित किया। डिवाइन क्रिकेट अकादमी के 40 ओवर में बनाए 174 रनों के जवाब में पैंथर क्रिकेट अकादमी ने 37.3 ओवर में आठ विकेट पर 175 रन बनाकर मैच जीत लिया।

सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में तीन देशों के कबड्डी टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव

कराची। पाकिस्तान मे भारत सहित तीन देशों के अंतरराष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट को सुरक्षा मंजूरी नही मिलने के बाद कार्यक्रम मे बदलाव किया गया है। इस टूर्नामेंट मे भारत और पाकिस्तान के अलावा तीसरी टीम ईरान की है। आयोजको ने मंगलवार को बताया कि झांग मे होने वाले शुरूआती मैच के लिए सुरक्षा की मंजूरी नही मिलने के कारण टूर्नामेंट के कार्यक्रम मे बदलाव किया गया है। टूर्नामेंट की शुरूआत मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से होनी था लेकिन अब इसका आयोजन 10 से 14 जनवरी तक होगा। आयोजको ने कहा, हमे गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मंजूरी नही मिली और अब यह प्रतियोगिता 10 जनवरी से बहावलपुर में शुरू होगी।

धन की कमी के करण ओलंपिक क्वालीफायर से हट सकता है पाकिस्तान

कराची। धन की कमी से जूझ रही पाकिस्तान हाकी महासंघ (पीएचएफ) एफआईएच प्रो हाकी लीग से हटने पर विचार कर रहा है जो 2020 ओलंपिक खेलो का क्वालीफाइंग टूर्नामेंट है। पाकिस्तान की टीम पर इससे पहले भारत मे पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए विश्व कप मे धन की कमी के कारण भाग नही लेने का खतरा मंडरा रहा था। पाकिस्तान को प्रो हाकी लीग के पहले चरण के मैच को अर्जेटीना के ब्यूनस आयर्स मे दो फरवरी को खेलना है। इसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैड का दौरा करना है।

आईपीएल का आयोजन भारत में, मार्च में शुरू होगा

एजेंसी। नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आगामी 12वां सत्र 23 मार्च से शुरू होगा और इस टी20 क्रिकेट लीग का आयोजन भारत में ही किया जाएगा।

आम चुनावों से आईपीएल की तारीख के टकराव को लेकर ऐसी आशंका जताई जा रही थी इसका आयोजन देश से बाहर किया जा सकता है लेकिन प्रशासकों की समिति (सीओए) ने मंगलवार को बताया कि लीग अपने तय समय से पहले 23 मार्च से शुरू होगी और इसका आयोजन देश में किया जाएगा। सीओए अध्यक्ष विनोद राय और इसकी सदस्य महिला टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुल्जी ने मंगलवार को मुलाकात करके इसके स्थलों और तारीखों पर चर्चा की। राय ने पीटीआई से कहा, सभी प्राथमिक स्थलों के लिए वैकल्पिक स्थल भी रखा जाएगा ताकि अगर मैच को स्थानांतरित करने की जरूरत हुई तो इसे किया जा सके। यह केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श पर किया जाएगा। वैकल्पिक स्थल इसलिए रखा जा रहा ताकि चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अगर प्राथमिक स्थल वाले राज्य में मतदान या मतगणना या प्रधानमंत्री की रैली हुई तो मैच को वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित किया जा सके। लोकसभा चुनावों की तारीख से टकराव की स्थिति को लेकर पिछले काफी समय से आईपीएल के स्थल को लेकर संशय की स्थिति थी लेकन इससे यह साफ हो गया कि आईपीएल का आयोजन देश में ही होगा। बीसीसीआई के बयान में कहा गया, आईपीएल 2019 के कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले सीओए सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली बार 2010 में आईपीएल मार्च में शुरू हुआ था। इसके बाद लीग हमेशा अप्रैल के पहले हिस्से में शुरू होकर मई के आखिरी में संपन्न होती थी।

आईपीएल पहले करने की एक वजह इस साल इंग्लैंड में होने वाला एकदिवसीय विश्व कप भी है जो 30 मई से शुरू होगा। बीसीसीआई के नए संविधान के अनुसार आईपीएल के संपन्न होने और भारतीय टीम के अंतरराष्ट्रीय मैचों के बीच 15 दिनों का अंतर होना चाहिए। राय ने कहा कि मैच स्थलों और तारीखों को बाद में सरकारी एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम को पूरा तैयार करने के बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों से तारीखों और स्थलों की मंजूरी ले लेंगे। आम चुनाव के कारण दो बार आईपीएल का आयोजन देश के बाहर हुआ है। 2009 में पूरे सत्र को दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था जबकि 2014 में कुछ मैचों को यूएई में खेला गया था। बीसीसीआई के अधिकारियों ने जयपुर में हुई खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान यह संकेत दिया था की आईपीएल के आगामी सत्र का आयोजन भारत में ही होगा।

ICICI Bank
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पाड्रा रोड, वडोदरा, गुजरात–390 007
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू). मुंबई–400 051
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान, नई दिल्ली–110 055

सार्वजनिक सूचना – प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा–सह–नीलामी

[नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, "जैसी है जहां है", जैसी है जो भी है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी ; ;

क स. (क)	कर्जदार (रों)/सह–कर्जदारों /गारंटरों का नाम/ऋण खाता संख्या (ख)	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ज्ञात ऋणभारों, सहित यदि कोई, (ग)	बकाया राशि (रू. में) (घ)	सुरक्षित मूल्य (रू. में) (ङ)	सुरक्षित मूल्य (रू. में) (ङ)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (छ)	नीलामी की तिथि एवं समय (ज)
1.	सुभाष चन्द्र ध्यानी (कर्जदार)/ मीरा ध्यानी (सह–कर्जदार) एलबीडीईएल00002004672	फ्लैट नंबर 2103, टावर सी, एवीजे हाइट्स, प्लॉट नंबर जीएच 12/2, सेक्टर–जीटा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य, परिमाप क्षेत्रफल – 2400 वर्ग फीट	रू. 90,81,269/– (27 दिसम्बर, 2018 को)	रू. 58,00,0 00/–	रू. 5,80,000 /–	22 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक	31 जनवरी, 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक
2.	सीमा त्यागी (कर्जदार)/ दीपक त्यागी (सह–कर्जदार) एलबीजीयूआर00001983799	फ्लैट नंबर ई 1803, एवीजे हाइट्स, प्लॉट नंबर जीएच 12/2, सेक्टर–जीटा–1, ग्रेटर नोएडा परिमाप क्षेत्रफल – 1250 वर्ग फीट	रू. 52,01,142/– (27 दिसम्बर, 2018 को)	रू. 33,00,0 00/–	रू. 3,30,000 /–	22 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक	31 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक
3.	जितेन्द्र कुमार जायसवाल (कर्जदार)/ संगीता (सह–कर्जदार) एलबीडीईएल00001946929 एलबीडीईएल00001970023	फ्लैट नंबर ई 1801, 18वां तल, टावर एल, एवीजे हाइट्स, प्लॉट नंबर जीएच 12/2, सेक्टर–जीटा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश परिमाप क्षेत्रफल – 1050 वर्ग फीट	रू. 33,77,047/– (26 दिसम्बर, 2018 को)	रू. 22,80,0 00/–	रू. 2,28,000 /–	22 जनवरी, 2019 को मध्या. 12.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक	31 जनवरी, 2019 को अप. 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी नीलामी एजेन्सी श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड (यूआरएल लिंक – षिजजचेरूध्ध्वतवचमतजलर्ेउपसण्पदष्) की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी। बंधकदाताओं/सूचनाप्रेषिती को 30 जनवरी, 2019 को अप. 5.00 बजे से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
संभावित बिडर (बिडर्स) को अपनी ऑफर उपरोक्त धरोहर राशि जमा (कालम च में वर्णितानुसार) सहित एक मोहरबंद लिफाफे में "सम्पत्ति के क्रय हेतु ऑफर" शीर्षांकित कर इस प्रकार प्रस्तुत करें कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, वीडियोकॉन टावर, ब्लॉक ई–1, झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 में अथवा हमारे मार्केटिंग एजेन्ट श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के द्वितीय तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 स्थित कार्यालय में 30 जनवरी, 2019 को अथवा पूर्व अप. 5.00 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। मार्केटिंग एजेन्सी को नीलामी के सम्यक् संचालन के लिए नीलामकार के रूप में भी अनुबंधित किया गया है। ईएमडी डीडी/पीओ राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड" के पक्ष में तथा दिल्ली में देय होना चाहिए।
निरीक्षण, नीलामी के निबंधन और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के मोबाइल नम्बर 8584874809/9650193259 पर अथवा श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड के 9910453434 पर सम्पर्क करें। केवल बैंक/ई–नीलामी विक्रेता पदाधिकारी द्वारा अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त और पंजीकृत की गई निविदाएं ही नीलामी हेतु मान्य होंगी।
प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की वेबसाइट देखें : https://www.icicibank.com/notice-board/properties-for-sale/properties.page?
हस्ता./–
तिथि : 09 जनवरी, 2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

फिल्म निर्माता राकेश रोशन को शुरुआती स्तर का कैंसर

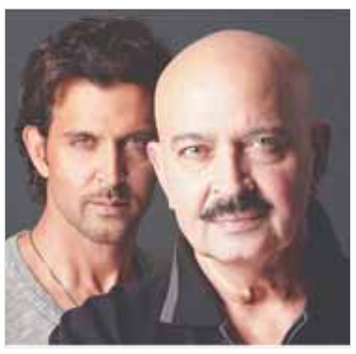

मुंबई। वरिष्ठ फिल्म निर्माता-अभिनेता राकेश रोशन गले के शुरुआती स्तर के कैंसर से पीड़ित हैं। राकेश के बेटे और अभिनेता रितिक रोशन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रितिक ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनके पिता सर्जरी के लिए तैयार हैं। रितिक ने राकेश (69) के साथ एक जिम में ली गई तस्वीर साझा करते हुए कहा कि मेरे लिए शायद यह दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। रितिक ने लिखा, वह गले के शुरुआती कैंसर से पीड़ित पाए गए हैं, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए उनका मनोबल ऊंचा हैं। राकेश और रितिक कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं जिनमें कहो ना प्यार है , कोई मिल गया , कृष सीरीज और काबिल जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। इससे पहले राकेश रोशन की बेटी सुनैना भी कुछ वर्ष पहले सर्वाइकल कैंसर का शिकार हुई थीं। वह अब बिल्कुल ठीक हैं।

अमरीश पुरी महान इंसान व अभिनेता थे: अख्तर

मुंबई। दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी की 14वीं पुण्यतिथि से पहले दिग्गज गीतकार व पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वह एक महान इंसान और महान अभिनेता थे। जी बॉलीवुड के 'क्लासिक लीजेंड्स सीजन 5' की आगामी कड़ी में जावेद, अमरीश पुरी की उपलब्धियों और हिंदी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान को बताएंगे। उन्होंने कहा, अमरीश पुरी को एक महान अभिनेता के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन मेरे जैसे लोग, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन्हें एक महान अभिनेता के साथ-साथ एक महान इंसान के रूप में याद करेंगे। जावेद ने अमरीश को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अमरीश पुरी महान इंसान व अभिनेता दोनों का मिश्रण थे। प्रख्यात फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक बार कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कई फिल्में देखी हैं लेकिन उन्होंने कभी भी इतना अच्छा खलनायक नहीं देखा।

'लोग पहले फिल्म देखें और फिर टिप्पणी करें'

अभिनेता **अक्षय खन्ना** और निर्देशक **विजय रत्नाकर गुट्टे** बता रहे हैं कि किस प्रकार उनकी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' दो व्यक्तियों के बीच के ऐसे संबंधों को सामने लाने का काम करती है जो व्यावसायिक संबंधों की परिभाषा से परे थे। प्रस्तुत है पायनियर संवाददाता **चहक मित्तल** की रिपोर्ट-

एक ऐसी राजनीतिक फिल्म का निर्माण, जिसमें समकालीन चरित्रों को उनके नाम के साथ जस का तस रखा गया हो, को बारूदी सुरंग बनते देर नहीं लगती, विशेषकर तब जब देश में राजनीतिक घटनाचक्र तेजी से घूम रहा हो। ऐसे में संजय बारू की इसी नाम की पुस्तक पर आधारित तथा विजय रत्नाकर गुट्टे के निर्देशन में बनी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर: डा. मनमोहन सिंह' का विवादों में घिरना स्वाभाविक ही था। ज्ञातव्य हो कि फिल्म में अनुपम खेर डा. मनमोहन और अक्षय खन्ना संजय बारू की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म 2019 के आसन्न लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत विवादों में घिरती नजर आ रही है।

लेकिन अक्षय खन्ना को फिल्म के विषय का इस प्रकार विवादों में घिरने का जरा भी अनुमान नहीं था। वो कहते हैं, 'हमें बिलकुल ये अनुमान नहीं था। ये तो था कि ऐसी पहली फिल्म जिसमें चरित्रों के नाम भी जस के तस हैं, पर कुछ हलचल तो अनुमानित थी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन हमने इस सीमा तक इसका अनुमान नहीं लगाया था।

वो ये भी बताते हैं कि जिसे लोग विवाद कह रहे हैं वो तो एक प्रकार का विमर्श है और हमारे जैसे लोकतंत्र में विमर्श तो होते ही रहने चाहिये।

गुट्टे बताते हैं कि उन्हें इस प्रकार के झगड़े का जरा भी भान नहीं था क्योंकि फिल्म ऐसी एक पुस्तक पर आधारित थी जो पिछले 4 साल से सार्वजनिक क्षेत्र में थी और लोगों को इसकी विषय सामग्री के बारे में पता भी था। ऐसे में यदि तब इस पुस्तक पर कोई विवाद नहीं हुआ तो अब क्यों?

फिल्म में अक्षय संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार बने हैं। तो वो किस प्रकार से ये चरित्र निभा पाने में समर्थ हुए? अक्षय मानते हैं कि उन्हें संजय बारू के चरित्र को समझने या सीखने के लिए कोई

विशेष प्रयास नहीं करने पड़े क्योंकि फिल्म के निर्देशक नहीं चाहते थे कि मैं संजय बारू जैसा दिखूं, बोलूं या चलूं या फिर उनके जैसे वस्त्र पहनूं। वो तो अपना एक अलग चरित्र निर्मित करना चाहते थे। अक्षय बताते हैं, 'विजय मानते थे कि बारू का किरदार अकेला ऐसा किरदार था जिसे वो जैसा चाहे ढाल सकते थे। क्योंकि वो मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या सोनिया गांधी के निकट के नहीं थे। अन्य किरदारों को तो वैसा ही चित्रित करना ही था जैसे वे दिखते थे।'

उनका कहना था कि उन्हे बारू जैसा बनने के लिए जरा भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़े, 'मैंने इसे निर्देशक और अपनी इच्छा के अनुरूप किया था। लेकिन पुस्तक पढ़ने और उनसे मिलने के बाद उनके बारे में जो भी सीखने को मिला, मैं कह सकता हूं कि वो एक श्रेष्ठ और प्रेरक व्यक्ति हैं।'

वो बताते हैं कि किस प्रकार बारू के पिता ने पीवी नरसिम्हा राव के लिए लिखते थे जिन्हें मनमोहन अपना गुरू मानते थे। अक्षय को मनमोहन सिंह और

बारू के बीच के रोचक संबंधों के बारे में जानकर काफी खुश थे। वे दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। सिंह बारू को अपना विश्वस्त मानते थे। मुझे पता चला कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केवल बारू को ही फोन किया था।'

वो इसे एक प्रेम प्रसंग मानते हैं, वो बताते हैं कि फिल्म इसी बारे में है, 'ये केवल इन दो लोगों के बीच की दोस्ती के बारे में है। उन्होंने हमेशा भारत और विदेश में प्रधानमंत्री की छवि की रक्षा की। उनका काम प्रधानमंत्री और उनकी छवि को भारत और विदेश में अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का था जो उन्होंने लगन, कौशल और प्रभावी ढंग से किया। कोई भी प्रधानमंत्री के साथ उनके काम करने और उनके जाने के बाद के अंतर को देखकर इसे समझ सकता है।'

तो फिर उनके व्यक्तिगत राजनीतिक विचार ऐसा रोल करने के बाद किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं? अक्षय मानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक इतिहास से उनकी इस प्रकार की मुठभेड़ से उन्हें ये पता चला कि चीजें किस प्रकार से होती रहती हैं।

दिल चाहता है कि इस अभिनेता का कहना है, 'मुझे लगा कि राजनीति अंतत: अनुकूलतम के अस्तित्व का खेल है। इसमें यदि आप अपने काम में कुशल नहीं हैं तो आप अधिक दिन तक टिक नहीं सकते। आप जीवन में भी अधिक दूर तक नहीं जा सकते। राजनीति में भी ऐसा ही है। ये अस्तित्व बजाए रखने का खेल है। ऐसी पृष्ठभूमि में बचे रहने के लिए उन्हें जो करना पड़ता था वो करते थे। इस फिल्म में भी दो लोगों के बीच के संबंधों को सामने रखा गया है जबकि ये भी दिखाया गया है कि लोग पृष्ठभूमि में किस प्रकार की राजनीतिक करते रहते हैं। लेकिन ये काफी अच्छा है।'

तो उनके जैसे चुनौतीपूर्ण और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति और अभिनेता के लिए ये रोल करना कितना संघर्षपूर्ण था?

लेकिन इस अभिनेता का कहना है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो बताते हैं, 'मैं अभिनय को आध्यात्मिकता के आलोक में नहीं देखता। ये मुझे अत्यंत स्वाभाविक तौर पर आती है। मैं तो केवल अपना काम करने का आनंद लेता हूं।'

वो आगे बताते हैं, 'मैं बहुत लंबे समय से अभिनय करता रहा हूं और अब मुझे इससे संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही यदि कैमरे के पीछे ऐसा संवेदनशील व्यक्ति हो जो जरूरत पर आपका मार्गदर्शन करता हो और आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सुनिश्चित करता हो, तो ऐसे व्यक्ति विजय गुट्टे के आसपास रहते सबकुछ आसान लगने लगता है। जब आप निर्देशक के प्रिय हों और उनके साथ स्नेह हो तो ये आपके प्रदर्शन में भी दिखाई देता है।' वो आगे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करता है, आपका हाथ पकड़कर आपको सहारा देता रहता हो तो कहना ही पड़ता है, 'आपके प्रदर्शन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। और विजय जी के कारण मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।'

यूट्यूब पर 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर: डा. मनमोहन सिंह' के नं. एक पर वायरल होने वाले ट्रेलर को हटाए जाने के बारे में उनका कहना था, 'मैं इसपर टिप्पणी करने की तकनीकी दक्षता नहीं रखता, लेकिन हटाए जाने से पहले भी इसपर होने वाली टिप्पणियों में काफीकुछ कह ही दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक अलग टाइप की दुनिया है जिसे इससे पहले नहीं देखा गया था। इसमें भारतीय राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मुझे नहीं पता कि वे इसे एक विवाद का रूप क्यों देते जा रहे हैं। ये केवल एक सुंदर कहानी भर है।'

जब विजय ने इसकी शूटिंग प्रारंभ की थी, उनका कहना है कि उन्हें लगा था कि वो केवल एक फिल्म की शूटिंग मात्र कर रहे हैं लेकिन 'मैंने कभी भी इसे राजनीतिक फिल्म की तरह से नहीं देखा था। मेरे लिए ये केवल एक फिल्म थी और बारू की इस पुस्तक को परदे पर सर्वश्रेष्ठ ढंग से उतारना ही हमारा ध्येय था। इसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं राजनीति को कोई नया मोड़ दे रहा हूं या इसके माध्यम से लोगों के विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में जनता को भी इसे केवल एक कहानी या फिल्म या दो लोगों के बीच के संबंध जो पेशेवर तथा व्यक्तिगत दोनों थे, की कहानी, न कि राजनीतिक इतिहास के तौर पर लेना चाहिये।'

उनका कहना है, 'मुझे लगता है कि इसे केवल ट्रेलर के आधार पर जज करना प्रारंभ करने के स्थान पर लोगों को पहले ये फिल्म देखना चाहिये और फिर इसपर टिप्पणी करनी चाहिये।

फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज हो रही है

न्यूयॉर्क: द मॉक्सी स्क्वायर स्क्वायर पर मैजिक ऑवर रूफटॉप में एमटीवी के 'लिंडसे लोहान के बीच क्लब' सीरीज की प्रीमियर पार्टी में भाग लेतीं (बाएं से) बैरेट विल्बर्ट वीड, लिंडसे लोहान, एशले पार्क और केट रॉकवेल।

केविन स्पेसी ने खुद को निर्दोष बताया

नैनटकेट अभिनेता केविन स्पेसी ने 2016 में 18 वर्षीय एक बसब्वॉय को गलत तरीके से छूने के मामले में सोमवार को खुद को निर्दोष बताया। इस आरोप के बाद ही स्पेसी के खिलाफ यौन दुराचार के मामलों की झड़ी लग गई थी और इसका उनके करियर पर काफी बुरा असर पड़ा था। बॉस्टन के पूर्व टीवी प्रस्तोता हीथर अनरूह भी हाउस ऑफ कार्ड्स के अभिनेता पर उनके बेटे के साथ नैनटकेट के मैसचुसेट्स रिसॉर्ट द्वीप स्थित एक बार में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया लगा चुके हैं। नैनटकेट डिस्ट्रिक्ट अदालत के न्यायाधीश थोमस बैरट ने स्पेसी को उसके आरोपी और व्यक्ति के परिवार से दूर रहने को कहा है। स्पेसी चार मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में पेश नहीं होंगे लेकिन फोन के जरिए मौजूद रहेंगे। अदालत से निकलते समय स्पेसी और उनके वकील ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

रेसुल पुकुट्टी बने साउंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका बोर्ड के सदस्य

लॉस एंजिलिस। ऑस्कर पुरस्कार विजेता साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्हें मोशन पिक्चर्स साउंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका (एमपीएसई) के बोर्ड का सदस्य चुना गया है। 47 वर्षीय पुकुट्टी ने ट्वीट किया, मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एमपीएसई के बोर्ड का सदस्य चुना गया है। इस समय अपने दूसरे घर लॉस एंजिलिस में मौजूद पुकुट्टी ने कहा, ... भारतीय फिल्म उद्योग के लिए यह सम्मान की बात है। ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने शहर के बारे में कहा, इस जमीन ने मुझे सब कुछ दिया है। इससे पहले पुकुट्टी ने वाट्सऐप का स्क्रीनशॉट भेजा, जिसमें बोर्ड के अन्य सदस्यों के नाम भी लिखे थे। पुकुट्टी समेत इन सदस्यों को दो वर्ष के लिए चुना गया है। बोर्ड के सदस्यों में जेम्स बार्थ, पेरी लामाका, पॉलेट विक्टर लिफ्टन, डेविड बारबर, गैरेट मोंटगोमेरी, डेनियल ब्लैंक, मिगुएल अरुजो और जामे स्क्वॉट का नाम शामिल है।

मोदी पर बायोपिक: विवेक ने कहा कि ऐसा अवसर जीवन में एकाध बार ही मिलता है

एजेंसी। मुंबई

अभिनेता विवेक ऑबेरॉय एक बायोपिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वघोषित प्रशंसक ऑबेरॉय ने कहा कि इस तरह के किरदार निभाने का मौका जीवन में कभी-कभी ही मिल पाता है।

इस बायोपिक का निर्देशन उमंग कुमार कर रहे हैं। इससे पहले कुमार मैरी कॉम और सरबजीत जैस बायोपिक फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च के

मौके पर अभिनेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद और वह और अच्छे इंसान और अच्छे अभिनेता बनेंगे।

अभिनेता ने संवाददाताओं से कहा, मैं बेहद खुश हूं। आज मैं वह महसूस कर रहा हूं जो 16 साल पहले कंपनी फिल्म के दिनों में किया करता था। मुझे उसी तरह की उत्सुकता और भूख (अभिनय की) महसूस हो रही है। ऐसा अवसर किसी भी अभिनेता को कभी कभार ही मिलता है। मेरा विश्वास है कि जब इस फिल्म की शूटिंग खत्म होगी तो मैं अच्छा अभिनेता और एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। इस फिल्म का पोस्टर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की उपस्थिति में 27 भाषाओं में जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मई, 2014 में अभिनेता अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।

बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे इसके निर्देशन पर गर्व है: उमंग कुमार

फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता उमंग कुमार ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर बायोपिक का निर्देशन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्हें इसे लेकर काफी गर्व भी है। उमंग पहले भी 'सरबजीत' और 'मैरी कॉम' जैसी बेहतरीन बायोपिक का निर्देशन कर चुके हैं। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के इतिहास में सबसे सफल नेताओं में से एक हैं। विवेक ओबेरॉय लेजेंड की भूमिका में हैं। सुरेश ओबेरॉय और संदीप सिंह ने इसका निर्माण किया है। बता दें कि पीए नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' का आधिकारिक पोस्टर कल सोमवार को रिलीज किया गया था। बता दें कि फिल्म के पोस्टर को 23 अलग-अलग भाषाओं में जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग मिड-जनवरी से शुरू हो जाएगी। फिल्म की टैगलाइन में लिखा है कि 'देशभक्ति की मेरी शक्ति है।'

"मेरा विश्वास है कि जब इस फिल्म की शूटिंग खत्म होगी तो मैं अच्छा अभिनेता और एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा।

सिनेमा को लोकतांत्रिक होना चाहिए: आहना

कुमरा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म में प्रियंका गांधी का किरदार अदा कर रही हैं।

एजेंसी। मुंबई

अभिनेत्री आहना कुमरा का कहना है कि सिनेमा को लोकतांत्रिक होना चाहिए और फिल्मों को लोगों तक पहुंचने का अच्छा अवसर मिलना चाहिए। कुमरा द ऐक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म में नजर आएंगी। अभिनेत्री का कहना है कि यह फिल्म किसी का भी पक्ष नहीं लेती है।

अभिनेत्री ने कहा, इस ट्रेलर को बेहतरीन तरीके से काटकर बनाया गया है। मैं गैरराजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं किसी का समर्थन नहीं करती। प्रत्एक फिल्म का अपना एक दृष्टकोण होता है। सिनेमा को लोकतांत्रिक होना चाहिए और मैंने अपने काम में इस चीज को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, आप क्या देखते हैं, यह आपके ऊपर है। किसी फिल्म को देखने और न देखने का फैसला आपके हाथों में होता है। शूटिंग के दौरान मुझे नहीं लगा कि यह फिल्म किसी का पक्ष ले रही है। यह फिल्म इसी नाम से प्रकाशित संजय बारू की किताब द ऐक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है। बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे। इस फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की और बारू का किरदार अक्षय खन्ना अदा कर रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है, जिसे कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। अभिनेत्री इस फिल्म में प्रियंका गांधी का किरदार अदा कर रही हैं।

उन्होंने कहा, पहले किसी को फिल्म देखनी चाहिए और फिर एक राय बनानी चाहिए। यह एक अच्छी फिल्म है और लोगों को इस फिल्म को एक मौका देना चाहिए। फिल्मनिर्माता और कलाकारों को नीचा दिखाना अच्छा नहीं होगा। अभिनेत्री ने प्रियंका गांधी का किरदार अदा करने के लिए रिसर्च के तौर पर गांधी के साक्षात्कार भी देखे।

उन्होंने कहा, वह (गांधी) मुझे आश्वस्त एवं शांत स्वभाव की लगती हैं। सार्वजनिक हस्ती होने के बाद भी वह लोगों की नजरों में नहीं रहती हैं, यहां तक कि इस सोशल मीडिया के युग में भी वह ऐसा करती है। मैं इस तरह की हस्ती को लेकर मंत्रमुग्ध हूं। यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हो रही है।

> पहले किसी को फिल्म देखनी चाहिए और फिर एक राय बनानी चाहिए। यह एक अच्छी फिल्म है और लोगों को इस फिल्म को एक मौका देना चाहिए।